चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

14 अक्टूबर–20 अक्टूबर 2013

राहुल और मायावती गठबंधन

मायावती और राहुल गांधी का साथ कुछ नये सियासी गुल खिला सकें, इसकी ख़ातिर कांग्रेस पार्टी एहतियातन कुछ जल्द और कठोर क़दम भी उठा सकती है. मसलन, जो ख़बरें कांग्रेस के रणनीतिकारों के अन्दरखानों से आ रही हैं, उसके मुताबिक, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बसपा की दोस्ती पर बौखलाएगी या गुर्राएगी, तब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के पहले ही संसद भंग करने की भी सिफ़ारिश कर सकती है और इसीलिए कांग्रेस ने संसद का शीतकालीन सत्र समय से पहले बुलाने की योजना भी बना रखी है. इसी शीतकालीन सत्र में सरकार अपने उन सभी बकाया विधेयकों को पास करा लेना चाहती है, जिसका सेहरा बांधकर वह जनता के बीच में जा सके और अपने कामकाज की मुनादी कर सके.

सियासत के तकाज़ों के मद्देनज़र, मुल्क़ में बेहद रोचक राजनीतिक तस्वीरें उभर रही हैं. पुराने साथियों का हाथ छूट रहा है, तो नये हमक़दम तलाशे जा रहे हैं. मक़सद, महज़ लोकसभा चुनाव में शह हासिल करना नहीं है, बल्कि पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में फ़तह हासिल करना भी है. इसी के मद्देनज़र कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी के बीच एक ख़ास रिश्ता पनपने लगा है. जो ख़बर है, उसके मुताबिक़ हाथ के पंजे और हाथी के दरम्यान एक क़रार हो चुका है. तय यह हुआ है कि राहुल और मायावती आने वाले लोकसभा चुनाव सहित पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की जंग मिलकर लड़ेंगे. अगर ऐसा होता है तो यक़ीनन इन चुनावों के नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं.

रूबी अरुण

इस सिलसिले में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती और कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी के बीच चुपके–चुपके ही मुलाक़ातों के कई निर्णायक दौर निबट चुके हैं और यह गठबंधन बस अब परवान चढ़ने ही वाला है. बसपा और कांग्रेस के बीच अमूमन सहमति बन चुकी है. डील बस एक मसले पर आकर अटक गई है, वह है लोकसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे की. सोनिया गांधी ने मायावती से यह बात साफ़तौर पर कह दी है कि उनके बीच यह सियासी रिश्ता तभी पुख़्ता होगा, जब मायावती कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की 80 संसदीय सीटों में से 35 पर लड़ने देने को राजी होंगी, वरना यह नई बनती दोस्ती बिखर भी सकती है. इस तरह मायावती 45 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर सकती हैं. पर मायावती चाहती हैं कि उनकी पार्टी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे. फ़िलहाल मायावती ने इस शर्त पर हामी नहीं भरी है, पर ख़बर है कि वे 35 और 45 के अनुपात पर तैयार हो जाएंगी और अगर कांग्रेस और बसपा की यह दोस्ती रंग लाती है, तब यह दोस्ती समाजवादी पार्टी और भाजपा के लिए चिंता की वज़ह बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा का साथ दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं को उनके पक्ष में एक साथ खड़ा कर सकता है.

मायावती और राहुल गांधी का गठबंधन कुछ नये सियासी गुल खिला सके, इसकी ख़ातिर कांग्रेस पार्टी एहतियातन जल्द कुछ कठोर क़दम भी उठा सकती है. जो ख़बरें कांग्रेस के रणनीतिकारों के अन्दरख़ानों से आ रही हैं, उनके मुताबिक, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस और बसपा की दोस्ती पर बौखलाएगी या गुर्राएगी, तब ऐसी स्थिति में कांग्रेस पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के पहले ही संसद भंग करने की भी सिफ़ारिश कर सकती है, इसीलिए कांग्रेस ने संसद का शीतकालीन सत्र समय से पहले बुलाने की योजना भी बना रखी है. इसी शीतकालीन सत्र में सरकार अपने उन सभी बकाया विधेयकों को पास करा लेना चाहती है, जिसका सेहरा बांधकर वह जनता के बीच में जा सके और अपने कामकाज की मुनादी कर सके. मतलब, कांग्रेस अपने ख़िलाफ़ लगे तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों और ख़िलाफ़ जाते जनमत के बावजूद, जीत पाने के लिए कोई कसर बाक़ी रखना नहीं चाहती. मायावती से गले मिलना भी इसी हसरत की एक अहम कड़ी है.

कांग्रेस और बसपा के गठबंधन की ये कोशिशें यूं ही नहीं हुईं हैं. हुआ ये कि जब राहुल गांधी ने दिग्विजय सिंह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभार वापस ले कर इस ज़िम्मेदारी को मधुसूदन मिस्त्री को सौंप दिया. तब मधुसूदन मिस्त्री ने उत्तर प्रदेश में एक गहन चुनावी सर्वे कराया. इस सर्वे की रिपोर्ट कांग्रेस के लिए बेहद हताशा भरी थी. जो नतीजे आए थे, उनमें बताया गया कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले अपने बूते उत्तर प्रदेश में चार से छह सीटें ही जीत पाएगी, जबकि अभी कांग्रेस के पास यूपी में लोकसभा की 22 सीटें हैं. तक़रीबन दो महीने पहले यह रिपोर्ट मधुसूदन मिस्त्री ने राहुल गांधी को पेश की और लगे हाथों यह सलाह भी दे दी कि कांग्रेस अगर बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, तो फ़ायदे में रहेगी. लिहाज़ा, मायावती तक यह सन्देश भिजवाया गया. ज़रूरत मायावती को भी थी, तो वह इस सिलसिले में सोनिया गांधी से मिलने आ पहुंचीं. सोनिया गांधी, अहमद पटेल और मायावती के बीच इस बाबत मंत्रणा हुई और ये तय हुआ कि दोनों साथ हो जाएं. पेच सिर्फ़ सीटों के बंटवारे का है. उम्मीद की जा रही है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस और बसपा भी अपने गठबंधन का ऐलान कर देंगी. अपने इस गठबंधन के ज़रिये कांग्रेस की यह पूरी कोशिश रहेगी की वह उत्तर प्रदेश में नरेन्द्र मोदी के विजय रथ को थाम ले और इसकी बिना पर मोदी के दिल्ली पर राज करने के सपने को भी तोड़ दे. कांग्रेस को यह लगता है कि उसके साथ बसपा के आ जाने से उसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में दलितों के वोट मिल जाएंगे. दिल्ली विधानसभा की कई सीटों पर भी तालमेल की गुंजाइश बन रही है. बसपा और कांग्रेस के बीच उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा के चुनावों के समय भी तालमेल होते–होते रह गया था. सीटों के बंटवारे और दलित मुसलमान वोट–बैंक का क्रेडिट अपने–अपने खाते में लेने की कवायद ने यह गठजोड़ नहीं होने दिया था, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालत ने राहुल गांधी और मायावती को यह बात अच्छी तरह समझा दिया है कि अगर अभी भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, तो हिन्दुस्तानी सियासत की ज़मीन पर शायद वे हाशिये पर चले जाएं, जिसका सीधा फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी और नरेन्द्र मोदी को ही मिलेगा और अगर वे साथ हो जाते हैं, तो अपनी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की दिल्ली तक पहुंचने की राह को वे मुश्किल कर देंगे, क्योंकि उनके एक साथ होने की स्थिति में दलित–मुस्लिम और ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण उनके पाले में हो जाएगा. जिसके फलस्वरूप जो दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां देश में तीसरे मोर्चे को शक्ल देने की मशक़्क़त कर रही हैं, उनकी राह भी थोड़ी कठिन हो जाएगी. इससे न सिर्फ पांच प्रदेशों के विधानसभा चुनावों, बल्कि आगामी लोकसभा चुनावों में भी टक्कर कांटे की हो सकती है.

मुज़फ़्फ़रनगर दंगों के बाद कांग्रेसी नेताओं को यह लगने लगा है कि दंगों से नाराज़ मुसलमान मतदाताओं का वोट उन्हें ही मिलेगा, पर राहुल और सोनिया इस बात से ख़ूब वाक़िफ़ हैं कि ये नाराज़ मुसलमान प्रदेश में उसी पार्टी को वोट देंगे, जो भाजपा को हराने की कूवत रखती हो और यहां, इस मामले में बसपा, कांग्रेस से आगे निकलती दिखाई दे रही है. अब तो मुस्लिम संगठन भी इस बात की घोषणा करने लगे हैं कि मायाराज में अल्पसंख्यक महफ़ूज़ थे. यह स्थिति बसपा को मज़बूत बना रही है. वहीं मायावती की ये मजबूरी है कि वे केंद्र में बनने वाली सरकार में अन्दर से शामिल होना चाहती हैं, वरना बाद में उन्हें अपने प्रदेश में तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. दूसरी तरफ बसपा के सामने सपा को भी रोकने की चुनौती है. इसलिए, बसपा और कांग्रेस का साथ मिलकर चलना मजबूरी भी है. हालांकि इस गठबंधन को लेकर दोनों पार्टियों के अन्दर थोड़ा डर भी है. कांग्रेस का भय

(शेष पृष्ठ 2 पर)

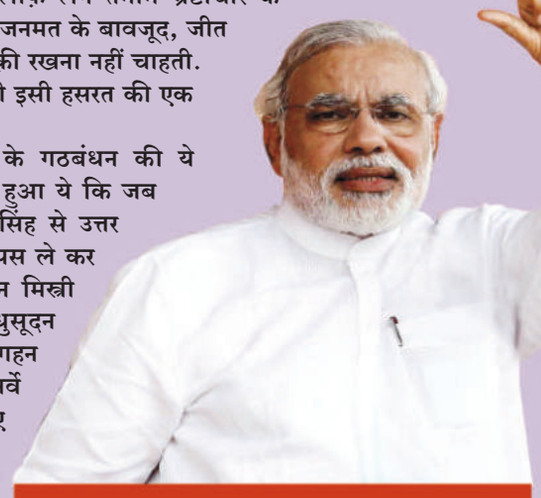

उम्मीद की जा रही है कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद कांग्रेस और बसपा भी अपने गठबंधन का ऐलान कर सकती हैं. अपने इस गठबंधन के ज़रिये कांग्रेस की यह पूरी कोशिश रहेगी की वह उत्तर प्रदेश में नरेन्द्र मोदी के विजय रथ को थाम ले और इसकी बिना पर मोदी के दिल्ली पर राज करने के सपने को भी तोड़ दे.

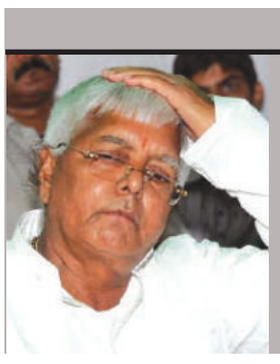

लालू को सजा नीतीश पर संशय 03

मुसलमान केवल मतदाता है 05

जुझारू महिला ने दिया खेती को नया आयाम 07

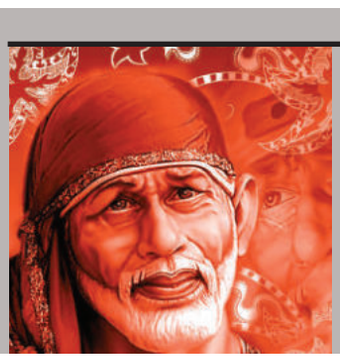

साई की महिमा 12

राहुल और मायावती गठबंधन

पृष्ठ एक का शेष

ये है कि अगर उसने बसपा के साथ लोकसभा चुनावों में देश भर में गठजोड़ किया तो उसके दलित वोटर छिटक कर मायावती के पाले में चले जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे, जैसा की पहले भी उत्तर प्रदेश में हो चुका है. वहीं, दूसरी तरफ बसपा का वोट बैंक भी कांग्रेस की तरफ आ जाएगा, पर कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक का रुझान बसपा की तरफ होगा या नहीं, कहना मुश्किल है. बावजूद इसके, कांग्रेस और बसपा, दोनों को ही इस गठबंधन में फ़ायदा ज़्यादा दिख रहा है.

यही वज़ह है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मधुसूदन मिस्त्री अचानक ही सपा के बारे में तल्ख़ लहजे में बात करने लगे हैं. उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी भी हद तक जाकर सपा की जन–विरोधी नीतियों का विरोध करने को कह दिया गया है. केन्द्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा भी इसीलिए लगातार सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ख़िलाफ़ कड़वी बातें कह रहे हैं, जबकि मामले को भांपते हुए मुलायम सिंह ने फ़िलहाल सारे आरोपों पर चुप्पी साध रखी है. अपनी तरफ से अभी उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ने का कोई इशारा नहीं किया है. मुलायम सिंह जानते हैं की फ़िलहाल प्रदेश का मुसलमान उनसे नाराज़ है. ऐसे में अगर वे कांग्रेस का हाथ छोड़ने का ऐलान करते हैं, तो नुकसान उन्हें ही होगा.

हालांकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा सूबा है, जहां का मुसलमान प्रदेश की किसी भी सीट पर पक्की जीत नहीं दिला सकता, पर ये ज़रूर है कि प्रदेश में मुसलमानों की

छत्तीसगढ़ में 11.61 प्रतिशत दलित वोट बैंक है, जबकि राजस्थान में 17.09 प्रतिशत दलित वोटर्स की हिस्सेदारी है. इन सभी प्रदेशों में बसपा की वजह से दलित वोट बैंक में बिखराव है, जिसका ख़ामियाज़ा कांग्रेस को उठाना पड़ता है. हालांकि इन चारो प्रदेशों में कांग्रेस का कोई परम्परागत दलित वोट बैंक नहीं रहा है.

जो संख्या है, वह कुछेक सीटों को छोड़कर बाकी हर सीट पर चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है. मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से सूबे में तक़रीबन 19 जिले ऐसे हैं, जहां मुसलमान बड़ी तादाद में रहते हैं. मसलन रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुज़फ्फरनगर, बलरामपुर, बरेली, बहराइच, अमरोहा, मेरठ आदि जिलों में मुसलमानों की आबादी बहुत घनी है. इसके अलावा पीलीभीत, खलीलाबाद, बदायूं, गाज़ियाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर ऐसे जिले हैं, जहां वोटरों का एक चौथाई हिस्सा, मुसलमान वोटर्स का है और इन सभी जगहों के मुसलमानों का तगड़ा झुकाव बसपा की तरफ हो चुका है.

साफ़ है कि अगर कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो जाता है, तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उसकी हैसियत से ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी.

इसी तरह अगर हम मध्य प्रदेश के इस वक़्त के हालात पर गौर करें, तो पाएंगे कि यहां स्थितियां 2008 सरीखी ही हैं. आप 2008 के चुनावी आंकड़ों को याद करें तो उनका विश्लेषण यही बताता है कि बसपा ने मध्य प्रदेश में तीसरी शक्ति के रूप में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई थी और अगर वहां कांग्रेस और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा होता तो मध्य प्रदेश में भाजपा दूसरी बार सरकार नहीं बना पाती. वहीं अगर बसपा ने भाजपा के साथ गठजोड़ कर लिया होता, तो शायद कांग्रेस प्रदेश से बाहर हो गई होती. हालांकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से बसपा ने महज़ 7 सीटें ही हासिल की थीं, पर 19 सीटें ऐसी थीं, जहां बसपा ने कहीं कांग्रेस, तो कहीं भाजपा को पीछे छोड़ कर नंबर दो पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी. चौदह विधानसभा क्षेत्र में बसपा ने 25 से 30 हज़ार वोट पाए थे और तकरीबन 70 विधानसभा क्षेत्रों में बसपा के उम्मीदवारों ने 10 से 20 हज़ार तक वोट हासिल कर लिए थे. अगर उस समय कांग्रेस के स्वयंभू नेताओं ने ज़मीनी हकीक़त की विवेचना की होती और मायावती से हाथ मिला लिया होता तो शायद मध्य प्रदेश उनकी ही सरकार होती. मध्य प्रदेश में भाजपा ने 230 विधानसभा सीटों में 143 सीटें हासिल कर अपनी सरकार बनाई थी. कांग्रेस को 71 सीटें मिलीं थीं और 7 सीटें जीतने वाली बसपा ने 57 अन्य सीटों पर अपनी दमदार उपस्थिति दिखाई थी. ज़ाहिर है कि ऐसे में अगर कांग्रेस और बसपा साथ होते तो ये 57 सीटें भाजपा के हाथ से निकल जातीं और वह सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होती, पर यही बसपा अगर भाजपा के साथ होती तो कांग्रेस 71 सीटों से सिमट कर 37–38 सीटों पर आ जाती. अभी भी मध्य प्रदेश में लगभग वैसे ही हालात हैं और इस बार कांग्रेस बसपा को साथ नहीं रखने की गलती दोहराना नहीं चाहती.

ठीक इसी तरह 2008 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही स्थितियां थीं. इस चुनाव में कांग्रेस को कुल 39.88 प्रतिशत वोट मिले थे. भाजपा को 36.43 प्रतिशत, जबकि 14.5 प्रतिशत वोट बसपा को मिले थे. हालांकि बसपा के खाते में दिल्ली विधानसभा की दो सीटें आई थीं. 2011 की जनगणना के आधार पर आंकलन करें तो इस बार की तस्वीर कुछ अलग होगी. दिल्ली में दलित और मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत 30 फ़ीसद से ज़्यादा है. अगर हम इनमें पुरबिया मतदाताओं को भी जोड़ दें तो यह 45 प्रतिशत से ऊपर चला जाता है. दिल्ली शहर की 70 सीटों में से 38 सीटों का जातीय गणित कुछ ऐसा है कि वहां कुल वोट शेयर 20 से 60 प्रतिशत तक का है. यहां 10 सीटें भाजपा के पास हैं, 4 अन्य दलों के पास और 34 सीटें कांग्रेस के पास है. गोकुल और बदरपुर की सीटें बसपा के पास है. मुस्लिम प्रभाव वाले इलाके जैसे ओखला, मटिया महल वगैरह की सीटें अन्य दलों के हिस्से में हैं. सुल्तानपुरी की सीट कांग्रेस के पास है, जहां दिल्ली में सबसे ज्यादा दलित रहते हैं और जिनका प्रतिशत 44 है. दिल्ली की एक दर्ज़न सुरक्षित सीटों में से 9 सीटें कांग्रेस के पास हैं और महज़ दो सीटें भाजपा के पास, एक पर बसपा का कब्ज़ा है. इन जातीय समीकरणों और प्रतिशत के दरम्यान कांग्रेस और बसपा का गठजोड़ यक़ीनन ज़बरदस्त रंग दिखा सकता है.

कमोबेश यही स्थिति पंजाब में है. पंजाब में 35 फ़ीसद से अधिक दलित आबादी है, पर बसपा अभी तक यहां के दलितों में अपनी पैठ नहीं बना सकी है. अभी तक यहां बसपा की भूमिका वोटकटवा तक ही सीमित है. पंजाब की 37 दलित जातियां, अपने–अपने हिसाब से अलग–अलग पार्टियों को समर्थन देकर यहां सरकार बनवाती रही हैं, लेकिन यहां अगर बसपा का गठजोड़ कांग्रेस के साथ होता है तो बिखरे हुए दलित वोटों का झुकाव उनके हक़ में हो सकता है.

छत्तीसगढ़ में 11.61 प्रतिशत दलित वोट है, जबकि राजस्थान में 17.09 प्रतिशत दलित वोटर्स की हिस्सेदारी है. इन सभी प्रदेशों में बसपा की वज़ह से दलित वोट बैंक में बिखराव है, जिसका ख़ामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ता है. हालांकि इन चारों प्रदेशों में कांग्रेस का कोई परम्परागत दलित वोट बैंक नहीं रहा है. इसलिए कांग्रेस, मायावती के साथ के बहाने इस बिखराव को सहेजने की कोशिश करेगी. कांग्रेस का साथ होने से बसपा की सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला, भाजपा के परम्परागत वोट बैंक पर भी असर डाल सकता है, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर कांग्रेस को ही मिलेगा. कांग्रेस मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं के वोटों के सहारे न सिर्फ़ उत्तर प्रदेश, बल्कि केंद्र की भी सत्ता संभालती रही है. ऐसे में अगर बसपा के मार्फ़त दलित वोटर भी उसके साथ हो जाएं तो यह बात भाजपा के नेताओं की हसरतों को मिटाने की वजह भी बन सकती है. कांग्रेस और बसपा के मिलने की खबर ने वैसे भी इन दिनों भाजपा नेताओं के माथे पर शिकन ला दी है.

बहरहाल, कांग्रेस और बसपा के हाईकमान में जो तालमेल नज़र आ रहा है, उससे तो यह डील होती दिखाई दे रही है, पर यह देखना रोचक होगा कि बसपा प्रमुख मायावती किन शर्तों पर कांग्रेस के साथ खड़ी होतीं हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 05 अंक 32
दिल्ली, 14 अक्टूबर–20 अक्टूबर 2013
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)
प्रथम तल, विराट कॉम्प्लेक्स के पीछे, सरदार पटेल पथ, कृष्णा अपार्टमेंट के नज़दीक, बोरिंग रोड, पटना–800013
फोन : 0612 2570092, 9431421901

ब्यूरो चीफ (लखनऊ)
अजय कुमार
जे–3/2 डालीबाग कॉलोनी, हजरतगंज, लखनऊ–226001
फोन : 0522–2204678, 9415005111

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के–2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022–42296060, +91–8451050786, +91–9266627379
फैक्स न. 0120–2544378

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

तबादलों पर सवाल

दिलीप चेरियन

दुर्गाशक्ति प्रकरण ने नौकराशाहों को एक तरह से जगा दिया है और राजनेताओं के उस हथियार को चुनौती देने की ताकत भी दे दी है, कभी जिसका इस्तेमाल नेता नौकरशाहों को दंडित करने के लिए करते थे. वह हथियार है नौकरशाहों का ट्रांसफर. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा दुर्गाशक्ति के विवादास्पद स्थानांतरण के विरोध में आईएएस ऑफिसर एसोसिएशन सार्वजनिक तौर पर खिलाफत पर उतर आया. और अब जब चौतरफा दबाव के चलते दुर्गाशक्ति की बहाली हो गई है तो इससे प्रभावित होकर दूसरे अधिकारी भी ऐसे प्रकरणों के खिलाफ खड़े होते दिख रहे हैं. हालांकि केंद्र उनके समर्थन में आता नहीं दिख रहा है.

सूत्रों के मुताबिक भारतीय पुलिस सेवा एसोसिएसन ने एक औपचारिक प्रतिनिधिमंडल बनाया है जो कि कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग को इस बात का संज्ञान देगा कि किस तरह से राज्यों में राजनेता अधिकारियों की ताकत को ट्रांसफर व निलंबन के माध्यम से खत्म कर रहे हैं. एसोसिएसन के जनरल सेक्रेट्री पंकज सिंह ने दो उदाहरणों का हवाला भी दिया है. एक मामला है उत्तर प्रदेश के 2003 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय मिश्रा का जिन्हें 15 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया है, इसी तरह छत्तीसगढ़ में आईपीएस मयंक मिश्रा को इस वर्ष के शुरू में ही सस्पेंड किया गया था. लेकिन सवाल तो यह है कि क्या केंद्र राज्य सरकार को रोकेगा कि वह अधिकारियों को इस तरह से संस्पेंड न करे. अभी इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए. ■

साउथ ब्लॉक

तीन अधिकारी अतिरिक्त सचिव बनेंगे

भारत सरकार ने तीन अधिकारियों को अतिरिक्त सचिव स्तर के पदों के लिए नामित किया है. ये हैं– 1980 बैच के बनवारी स्वरूप, 1981 बैच के वीआर सदासिवम और 1980 बैच की सुश्री अनन्या राय.

एसबीआई की पहली महिला अध्यक्ष

प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद के लिए अरुंधति भट्टाचार्य के नाम को हरी झंडी दे दी है. भारत की सबसे बडी बैंकिंग सेवा की वे पहली महिला अध्यक्ष होंगी.

शीतकालीन सत्र समय से पहले होगा

सरकार के उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया है कि केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र समय से पहले करा सकती है. यह संभवत: नवंबर के तीसरे सप्ताह में हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि सरकार लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ज्यादा से ज्यादा विधेयक पास कराना चाह रही है.

राजीव वर्मा रक्षा मंत्रालय गए

दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक राजीव वर्मा रक्षा मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं. वर्मा 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं.

अनिल कुमार की तैनाती में देरी

1982 बैच के बंगाल कैडर के आईपीएस अधिकारी अनिल कुमार की सीआरपीएफ के एडीजी के रूप में नियुक्ति में देरी हो रही है. रक्षा मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी देकर कैबिनेट की नियुक्ति समिति के पास भेज दी है. ■

मजबूत होती आईएफएस लॉबी

भारतीय विदेश सेवा (आइएफएस) ने आखिर एक प्रतिष्ठित राजनयिक पद को आखिरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के चंगुल से वापस अपने पाले में कर लिया है. हाल ही में यूनेस्को में स्थाई प्रतिनिधि के तौर पर 1987 बैच की आइएफएस अधिकारी रुचिरा कम्बोज की नियुक्ति हुई है. वे फिलहाल विदेश मंत्रालय में चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है. सूत्रों के मुताबिक पेरिस में यह पद कैरियर राजनयिकों के लिए आरक्षित रहता था. अब तक इस पर 1979 बैच के आईएएस ऑफिसर विनय शील ओबेराय की नियुक्ति थी.

एमएस कम्बोज की नियुक्ति के साथ, भारतीय विदेश सेवा लॉबी अब ताकतवर आईएएस लॉबी से कुछ दूसरे पदों को अपनी तरफ लाने की कोशिश में है. लेकिन आईएफएस लॉबी कितने दिनों तक अपनी पकड़ बनाए रखेगी, इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता. ■

बाबुओं के काम का परीक्षण

केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि जिन नौकरशाहों का प्रदर्शन उम्मीद से कम है उनकी सेवाएं या तो खत्म कर दी जाएंगी या समय से पहले सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह फैसला यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद 2004 में प्रस्तावित किया था. लेकिन जल्द ही इसे ताक पर रख दिया गया. अब सरकार ने एक बार फिर से इसे लागू करने का फैसला किया है. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु व अरुणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम यूनियन टेरिट्री ने तो अधिकारियों के प्रदर्शन का रिव्यू करना शुरू भी कर दिया है, जबकि पंजाब भी जल्द ही यह कदम उठाने जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक व अरुणाचल प्रदेश–गोवा–मिजोरम यूनियन टेरिट्री के तीन अधिकारियों को अच्छे प्रदर्शन न कर पाने के कारण समय से पहले रिटायरमेंट दिया जा रहा है. हालांकि उनके नाम अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं लेकिन उन लोगों ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. ■

dilipcherian@gmail..com

> राजद लालू को सजा के मामले को जोर–शोर से उठाने जा रही है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि जनता को यह समझाया जाए कि लालू प्रसाद को एक साज़िश के तहत इस मामले में फ़ंसाया गया और सज़ा दिलवाई गई. अगर श्याम बिहारी सिन्हा का बयान ही अपराध का आधार है, तो अब तक नीतीश और शिवानंद तिवारी से पूछताछ क्यों नहीं हुई?

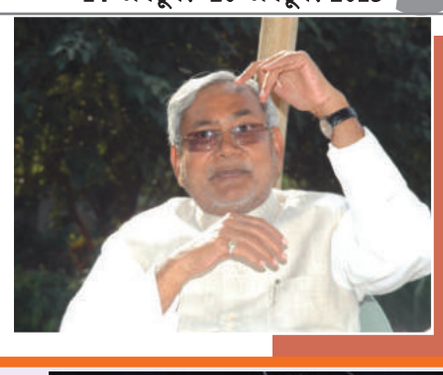

चारा घोटाला

लालू को सज़ा नीतीश पर संशय

सरोज सिंह

चारा घोटाले में लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में दो तरह की आशंकाएं गूंज रही हैं. पहली आशंका राजद के भविष्य को लेकर है. लोग यह जानने–समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 15 सालों तक बिहार की सत्ता को अपने हाथ में रखने वाली पार्टी क्या अब नये हालात का दबाव झेल पाएगी या फिर टूट जाएगी. क्या लालू प्रसाद पार्टी की कमान राबड़ी देवी, अपने बेटे तेजस्वी या फिर अपने किसी भरोसे के नेता को सौंप देंगे, लेकिन इससे बड़ा सवाल जो इन दिनों विपक्ष की पार्टियों के लिए बड़ा हथियार साबित हो रहा है, वह यह है कि क्या लालू के बाद चारा घोटाले में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के ख़िलाफ़ मामला नहीं चलना चाहिए. लालू प्रसाद की धर्मपत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कहती हैं कि सीबीआई की निष्पक्षता तो 22 नवंबर को पता चल जाएगी. गौरतलब है कि रांची हाईकोर्ट में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी के ख़िलाफ़ जो मामला चल रहा है, उस पर 22 नवंबर को अदालत अपना रुख़ साफ करने वाली है. मिथिलेश कुमार सिंह ने यह याचिका दायर कर रखी है, जिसमें पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई को काफी खरी–खोटी सुनाई थी और कहा था कि जांच ऐजेंसी को यह बताना चाहिए कि इस मामले में उसने यू–टर्न क्यों ले लिया. 22 नवंबर को सीबीआई को अपना जवाब देना है. मामले के क़ानूनी पक्ष को आगे बढ़ाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दीनू कुमार कहते हैं कि अगर श्याम बिहारी सिन्हा के बयान के आधार पर लालू प्रसाद के ख़िलाफ़ सुनवाई और सज़ा हो सकती है तो फिर इसी बयान के आधार पर नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? एक को सज़ा और दूसरे से पूछताछ भी नहीं, यह कैसे हो सकता है? रांची हाईकोर्ट के रुख़ के बाद भाजपा और लालू को सज़ा होने के बाद राजद इस मामले में काफ़ी आक्रामक हो गई है.

> **भाजपा जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ वह संघर्ष को अपना संकल्प बनाए रखेगी. लालू प्रसाद को सलाखों के भीतर भेजने के बाद अब नीतीश कुमार को भी वह नहीं छोड़ेगी. भाजपा को लग रहा है कि जो बेदाग़ चेहरा लिए नीतीश कुमार घूम रहे हैं, उस पर चारा घोटाले का दाग़ लगते ही चुनावी स्थितियां भाजपा के बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी.**

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक संजय टाइगर कहते हैं कि सीबीआई के पूर्व एसपी जावेद अहमद ने हाईकोर्ट में दाख़िल अपने शपथ पत्र में चारा घोटाले में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी सहित कई लोगों के संलिप्त रहने का आरोप लगाया था. उधर, इस मामले में सुशील मोदी ने एक बार फिर लालू प्रसाद के बाद नीतीश कुमार के ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया है. ग़ौरतलब है कि सुशील मोदी की याचिका पर ही लालू प्रसाद को लंबी सुनवाई के बाद सजा हुई. सुशील मोदी दावा करते हैं कि चारा घोटाले में नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी का भी जेल जाना तय है. वह कहते हैं कि चारा घोटाले के मुख्य अभियुक्त श्याम बिहारी सिन्हा ने कोर्ट में दिए अपने बयान में शिवानंद को पैसे दिए जाने की बात कही है. चारा घोटाले में बहस करने वाले और भाजपा नेता रविशंकर भी कहते हैं कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद जेल जा चुके हैं, अब नीतीश कुमार की बारी है, क्योंकि दस्तावेजों में उनका भी नाम है. माले नेता दीपांकर भी बार–बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को जान–बूझकर इस मामले में राहत दे दी गई है. जांच एजेंसी ने नरमी बरती है, लेकिन अब हमलोग ऐसा नहीं होने देंगे.

जानकार बताते हैं कि राजद इस मामले को जोर–शोर से उठाने जा रही है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है कि जनता को यह समझाया जाए कि लालू प्रसाद को एक साज़िश के तहत इस मामले में फ़ंसाया गया और सज़ा दिलवाई गई. अगर श्याम बिहारी सिन्हा का बयान ही अपराध का आधार है, तो अब तक नीतीश कुमार और शिवानंद तिवारी से पूछताछ क्यों नहीं हुई. राजद को लग रहा है कि अगर जनता यह समझ गई कि नीतीश कुमार को जान–बूझकर इस मामले में राहत दी गई तो पार्टी और लालू प्रसाद के प्रति एक सहानुभूति की लहर चल पड़ेगी. राबड़ी देवी ने तो इसकी शुरुआत यह कह कर दी कि एक ही मामले में दो तरह की जांच नहीं हो सकती. आने वाले दिनों में राजद इसे लेकर धरना–प्रदर्शन भी कर सकती है. चारा एक ऐसा मामला है, जो बार–बार राजद को बंधन में बांधता रहा है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का नाम आगे कर राजद इसका चुनावी लाभ लेने की रणनीति बना रही है. यही रणनीति भाजपा भी अपना रही है.

भाजपा जनता के बीच यह संदेश देना चाहती है कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ वह संघर्ष का अपना संकल्प बनाए रखेगी. लालू प्रसाद को सलाख़ों के भीतर भेजने के बाद अब नीतीश कुमार को भी वह नहीं छोड़ेगी. भाजपा को लग रहा है कि जो बेदाग़ चेहरा लिए नीतीश कुमार घूम रहे हैं, उस पर चारा घोटाले का दाग़ लगते ही चुनावी स्थितियां भाजपा के बिल्कुल अनुकूल हो जाएंगी. भाजपा यह सीना ठोंक कर कह सकती है कि उसे छोड़कर हर दल भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए जनता को बेदाग़ चेहरा ही पसंद करना चाहिए. भाजपा चारा घोटाले को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है, ताकि चुनाव प्रचार कथित संप्रादियकता के रंग में नहीं रंग सके. जहां तक लालू प्रसाद के सज़ा होने के बाद राजद के भविष्य का सवाल है तो यह कहा जा सकता है कि राजद को चुनावी लिहाज से बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा है. अगर राजद अपने नेता को जेल भेजने को साज़िश के तौर पर जनता को समझा सका तो लोकसभा में इसे फ़ायदा ही होगा. जहां तक नेतृत्व का सवाल है तो लालू प्रसाद को चुनौती देने की ताक़त अभी किसी में नहीं है. लालू जेल से ही पार्टी चलाएंगे. हो सकता है कि वह स्वास्थ्य के आधार पर अस्पताल में शिफ्ट हो जाएं और वहीं से पूरी पार्टी चले. दिखावे के लिए कोई संचालन समिति या एक कोर टीम का गठन हो सकता है पर वास्तविक ताक़त लालू के पास ही रहेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

उन नेताओं की सूची, जिनपर चारा घोटाले के सूत्रधार श्याम बिहारी सिन्हा से कथित तौर पर धन प्राप्त करने का आरोप है.

नाम	रुपये
नीतीश कुमार	1,00,00,000
ज्ञान रंजन	35,00,000
गुलशन लाल अजमानी	57,00,000
भोला राम तूफानी	50,00,000
विद्या सागर निषाद	50,000
राधानंदन झा	8,00,000
जगदीश शर्मा	5,00,000 प्रति माह
राजो सिंह	1,00,000 प्रति माह
राम दास सिंह (राय)	5,00,000 प्रति माह
धुती पाहन	15,00,000
रामचंद्र बैठा	2,50,000
सूरज मणि सिंह	7,50,000
करमचंद भगत	5,00,000
निरब्यास कुमार सिंह	15,00,000
शिवानंद तिवारी	60,00,000
जेउ सिंह यादव	15,00,000
प्रो. अमर कुमार सिंह	5,00,000
विवेकानंद शर्मा	28,50,000
अभय सिंह	20,00,000
उदय शंकर झा	1,00,000

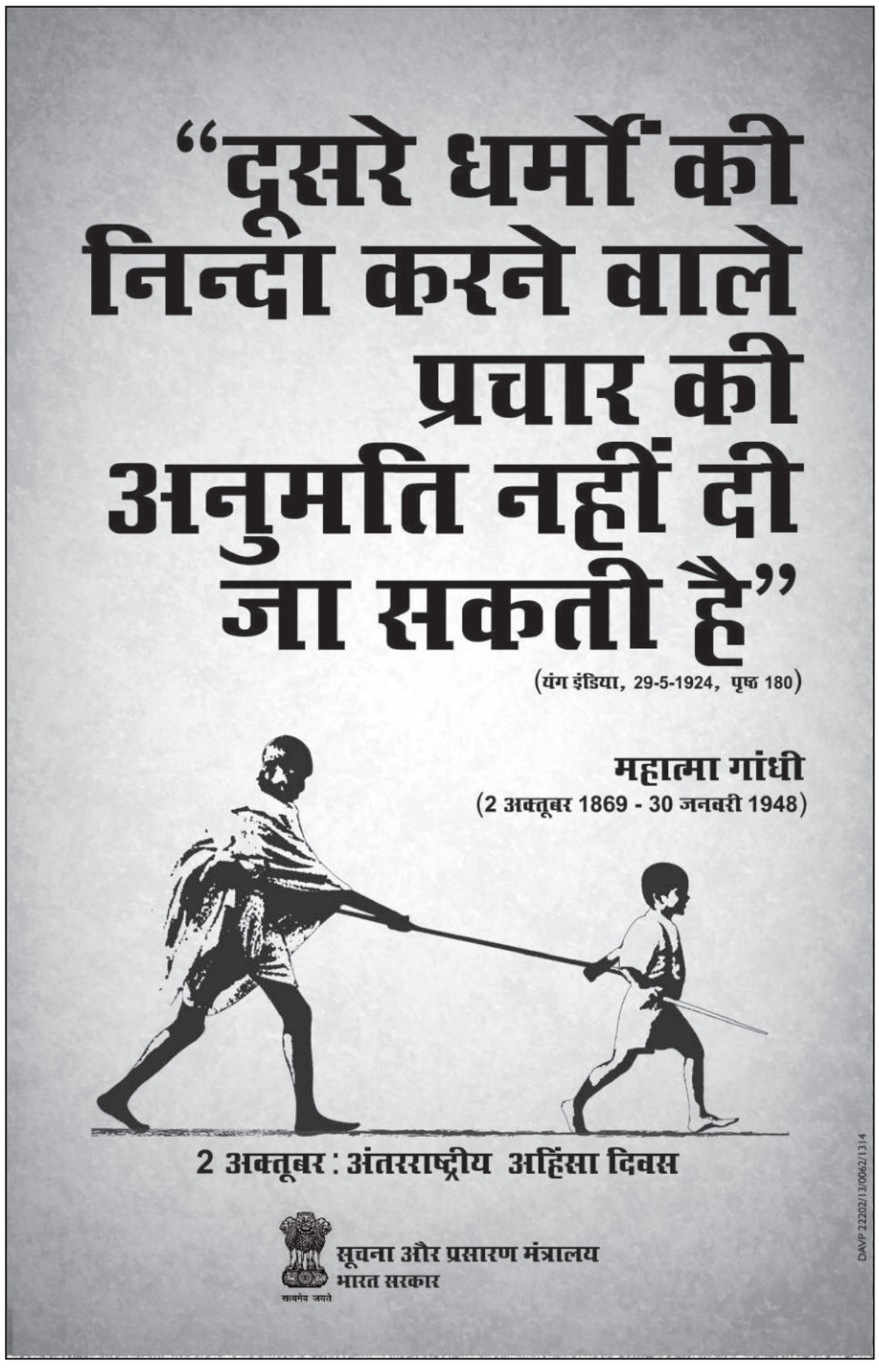

> लोकसभा चुनाव नजदीक है. कांग्रेस ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज़ कर दी हैं. मुसलमानों से झूठ बोलने का सिलसिला भी उतनी ही तेज़ी से शुरू हो चुका है. केन्द्रीय मंत्री के रहमान कह रहे हैं कि उनके मंत्रालय ने सच्चर कमेटी की 76 अनुशंसाओं में से 73 लागू कर दी हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आरंभिक 22 अनुशंसाओं में 12 अनुशंसाओं को यूपीए सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है और सरकार के मंत्री लगातार झूठ बोलने में लगे हुए हैं.

रशीद मसूद की राजनीति ख़त्म

अब इनकी बारी है

संजय सक्सेना

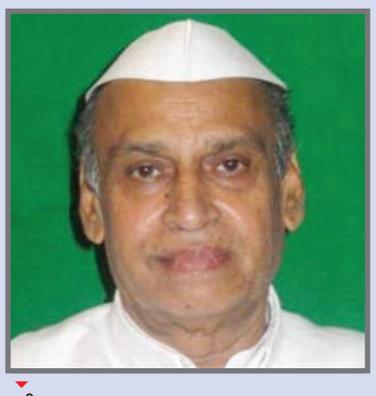

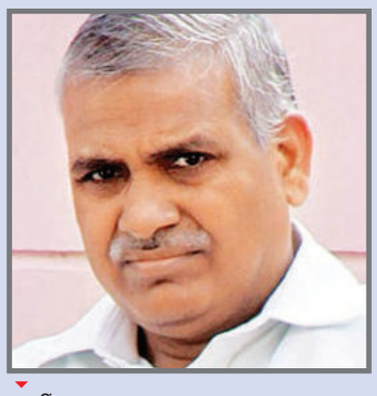

पुराने समाजवादी और अब कांग्रेसी सांसद (राज्यसभा सदस्य) रशीद मसूद आख़िरकार मेडिकल भर्ती घोटाले में सलाखों के पीछे पहुंच ही गए. दागी माननीयों के चुनाव न लड़ पाने को लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सबसे पहले मसूद पर वज्रपात कर गया. दूसरी तरफ अधिकांश बुद्धिजीवी और समाज का पढ़ा–लिखा वर्ग मसूद पर आए फैसले को राजनीतिक शुद्धिकरण की पहल से जोड़ रहा है. सजा मिलते ही यूपी की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले मसूद साहब का राजनीतिक करियर करीब–करीब खत्म माना जा रहा है. चार साल की सजा सुनाए जाते ही उनकी राज्यसभा की सदस्यता स्वत: समाप्त हो गई. आगे भी वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन जेल से बाहर आने का विकल्प जरूर उनके सामने खुला हुआ है. दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उन्हें एमबीबीएस सीटों संबंधी घोटाले में सजा सुनाई है. वह सजा के कारण सांसदी गंवाने वाले पहले नेता बन गए. मसूद को सजा सुनाए जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति सहम गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भी कई मसूद मौजूद हैं. यूपी के कई सजायाफ्ता दागी और बाहुबली शायद ही अगला चुनाव लड़ पाएं. वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं, जिन्हें अभी तक किसी अदालत ने सजा तो नहीं सुनाई है, लेकिन उनके गुनाहों को देखते हुए यह तय माना जा रहा है कि वह भी देर–सबेर सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं. आय से अधिक मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव को सीबीआई से भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन तमाम नेताओं का भाग्य मुलायम–माया जैसा नहीं है. अनेक सांसदों–विधायकों व पूर्व बसपा सरकार के कई मंत्रियों पर सजा की तलवार लटक रही है.

बहरहाल, रशीद मसूद को सजा मिलने से बसपा राज में हुए स्वास्थ्य घोटालों के चलते जेल में बंद पूर्व बसपा नेता और पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा, रंगनाथ मिश्र, बादशाह सिंह, चंद्रदेव यादव (सभी बसपाई) की भी नींद उड़ गई है. उनको अपना राजनीतिक करियर अंधकारमय लग रहा है. खैर, वैसे तो यूपी में समय–समय पर कई बड़े घोटाले (बोरा घोटाला, दवा खरीद घोटाला, चीनी मिलों की बिक्री घोटाला, स्मारक घोटाला, फॉर्म हाउस आदि घोटाले) हुए हैं, लेकिन इन घोटालों के आरोपियों की किस्मत अच्छी थी, जो उनका बाल भी बांका नहीं हुआ. आजकल जो दो घोटाले सबसे अधिक चर्चा में हैं, वह दोनों ही माया राज में हुए थे. करीब एक हजार करोड़ रुपये का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन घोटाला मायावती की सरकार में हुआ था. इसमें उनके मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा और एमएलए आरपी जायसवाल जेल की हवा खा चुके हैं. बाद में कुशवाहा बागी हो गए थे. सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और इतने सबूत एकत्र कर लिए हैं कि दोषियों का निकल पाना मुश्किल होगा. सजा तो बाद में सुनाई जाएगी.

बसपा राज में लैकफेड घोटाले ने भी खूब सुर्खियां बटोरी थीं, जिसमें बसपा के तत्कालीन मंत्रियों बादशाह सिंह, चंद्रेदव राम, रंगनाथ मिश्र समेत कई अधिकारी जेल में हैं. अब तक की जांच से पता चला है कि यह घोटाला भी लगभग तीस करोड़ का था. इसके भी पुख्ता सबूत मिल चुके हैं. बात उत्तर प्रदेश के दागी माननीयों की करें तो राज्य के कुल 403 विधायकों में से 189 यानी 47 प्रतिशत विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 98 पर हत्या और बलात्कार जैसी संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज हैं. इन आंकड़ों

नसीमुद्दीन सिद्दीकी

अतीक अहमद

मुख्तार अंसारी

बादशाह सिंह

रशीद मसूद

बाबू सिंह कुशवाहा

डीपी यादव

को देखकर समझा जा सकता है कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का उत्तर प्रदेश की राजनीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा. उत्तर प्रदेश की जनता का यह दुर्भाग्य रहा कि कोई भी पार्टी दागी–दबंगों को शरण देने के मामले में पीछे नहीं है. पहले तो नेता अपनी मजबूती के लिए दबंगों का सहारा लिया करते थे, बाद में इन दबंगों को राजनीति का ऐसा चस्का लगा कि वह स्वयं माननीय बनने लगे. पिछले विधानसभा चुनाव में विभिन्न दलों और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामों के आधार पर तैयार यूपी इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, समाजवादी पार्टी के 224 विधायकों में से 111 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं. इनमें से 56 के खिलाफ गंभीर आरोप लगे हैं. सपा के बाद दूसरा नंबर बसपा का है. इसके 80 विधायकों में से 29 के खिलाफ आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं. इसके 14 माननीयों पर गंभीर मामले दर्ज हैं. शुचिता की बात करने वाली भाजपा भी इससे अछूती नहीं है. इसके 47 में से 25 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं. इनमें 14 पर गंभीर आरोप हैं. वहीं कांग्रेस के 28 में से 13 विधायकों पर आपराधिक मामले हैं. 2007 में उप्र में दागी विधायकों की संख्या 35 प्रतिशत थी, जो अब बढ़ कर 47 फीसद पर पहुंच गई है.

बड़े दल तो बदनाम हैं ही, छोटी–छोटी राजनीतिक पार्टियां तो उनसे भी दो कदम आगे हैं. कई दलों के आका ही गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे हैं. ये लोग स्वयं तो चुनाव लड़ते ही हैं, दिल खोलकर दागियों को भी टिकट बांटते हैं. पिछले विधानसभा चुनाव में अपना दल, भासपा, पीस पार्टी, कौमी एकता दल, इंडियन जस्टिस पार्टी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी आदि छोटे–छोटे दलों ने दंबगों को खूब टिकट बांटा. बाहुबली मुख्तार अंसारी, बृजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी अतीक अहमद, डीपी यादव आदि ऐसे नाम हैं, जिन्होंने अपराध की दुनिया से राजनीति में कदम रखा था. कई तो बड़े दलों से भी चुनाव भी लड़ चुके हैं. बाहुबली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी कभी सपा व बसपा के माननीय हुआ करते थे. जब बड़े दलों में उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने अपना संगठन ही खड़ा कर लिया. लोकसभा चुनाव में अंसारी बंधुओं ने कौमी एकता दल, भासपा व पूर्वांचल में सक्रिय कुछ अन्य छोटे दलों के साथ एकता मंच गठित किया. 2009 के लोकसभा चुनाव में एकता मंच के बैनर तले बाहुबली मुख्तार अंसारी ने वाराणसी से भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी को चुनौती दी थी. मुख्तार इस बार फिर वाराणसी से ही ताल ठोंकने की फिराक में थे, लेकिन कोर्ट के फैसले ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी बलिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं. अफजाल अंसारी भी मुख्तार की तरह सपा–बसपा में रह चुके हैं. मुख्तार की पार्टी से ही जेल में बंद पूर्व बसपा नेता और माया कैबिनेट के मंत्री रहे बाबू सिंह कुशवाहा गाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने के चक्कर में थे. प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के टिकट पर बीते विधानसभा चुनाव में चंदौली की सैयदराजा सीट पर दूसरे स्थान पर रहे माफिया बृजेश सिंह अब मंच चंदौली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव में उतरना चाहते थे. प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने जनवादी पार्टी और वंचित जमात पार्टी के साथ राष्ट्रीय विकास मोर्चा का गठन किया है. बृजेश इसी मोर्च के बैनर तले चंदोली से लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे. बाहुबली अतीक अहमद ने पिछला लोकसभा चुनाव अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से लड़ा था. अपना दल ने उन्हें फिर से लोकसभा का टिकट देने का ऐलान किया था. 2012 में माफिया डीपी यादव विधानसभा चुनाव बदायूं के सहसवान सीट से अपनी पार्टी राष्ट्रीय परिवर्तन दल से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए. पिछले विधानसभा में वे और उनकी पत्नी इसी दल से विधायक थे. इन दिनों उनके भाजपा या राष्ट्रीय परिवर्तन दल के साथ जाने की अटकलें चल रही थीं, लेकिन इन माफियाओं के मंसूबों पर कोर्ट के फैसले और केंद्र सरकार द्वारा दागियों को माननीय बनाने के लिए लाए गए अध्यादेश को बकवास बता कर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया. उक्त नेताओं के अलावा माफिया बबलू श्रीवास्तव, बाहुबली धनंजय सिंह, अभय सिंह, रामू द्विवेदी और घपले व आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रंगनाथ मिश्र, राकेशधर त्रिपाठी, बादशाह सिंह, रामवीर उपाध्याय, रामअचल राजभर समेत विभिन्न दलों के तमाम नेताओं की सियासत पर भी ग्रहण लग गया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, उसके बाद मनमोहन सरकार द्वारा फैसले के खिलाफ लाया गया अध्यादेश, इस पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हस्ताक्षर करने से ना–नुकुर करना, फिर राहुल गांधी द्वारा अध्यादेश को बकवास बताना, यह सारा घटनाक्रम आम जनता के लिए फायदेमंद रहा. कोई रास्ता नहीं दिखाई देने पर राजनीतिक दलों ने भी सुर बदल लिया है. कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी का कहना है कि बीते 20 वर्षों में राजनीति का आपराधीकरण हुआ है. धनबल–बाहुबल का प्रभाव बढ़ा है.

आशा है कि इस फैसले के सार्थक परिणाम सामने आएंगे. सपा जो इस फैसले से सबसे अधिक प्रभावित होगी, उसके नेता काफी नपी–तुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सपा के प्रदेश महासचिव डॉ सीपी राय का कहना है कि न्यायालय का फैसला क्रांतिकारी है, लेकिन यह फैसला उस समाज के लिए है, जहां व्यवस्था व सत्ता आदर्शवादी हो, लेकिन जहां पुलिस रोज सैकड़ों फर्जी मुकदमें लिखती हो, आंदोलनकारियों को पीटती हो, उन पर गोली चलाती हो, फर्जी मुकदमा ठोंक देती हो, ऐसे देश में कहीं ऐसा न हो कि इस फैसले से लोकतंत्र की बुनियाद ही हिल जाए. ■

feedback@chauthiduniya.com

अल्पसंख्यक मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए

डॉ. क़मर तबरेज़

> भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय के ऊपर शुरू से ही आरोप लगते रहे हैं कि उसने सरकार की अधिकतर नीतियों को लागू नहीं किया है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान ख़ान ने भारत के अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर झूठ बोलने के अलावा अब तक कोई काम नहीं किया है. मंत्रालय के उदासीन रवैये को देखते हुए अब ऐसी आवाज़ें उठने लगी हैं कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को बंद कर दिया जाना चाहिए.

किसी देश की नीतियों को वहां की सरकार और उसके मंत्रालय ही लागू करते हैं. भारत में भी ऐसा ही होता है, लेकिन अगर कोई मंत्रालय सशक्त न हो और काम भी न करे, तो क्या करना चाहिए? इसका सीधा जवाब तो यही है कि ऐसे मंत्रालय को बंद कर देना चाहिए. कुछ ऐसा ही हाल है भारत के अल्पसंख्यक मंत्रालय का, जिसके ऊपर शुरू से ही इस प्रकार के आरोप लगते रहे हैं कि इसने सरकार की अधिकतर नीतियों को लागू नहीं किया है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रहमान ख़ान यूपीए सरकार के सबसे बेबस मंत्री के रूप में उभरकर सामने आए हैं. उन्होंने भारत के अल्पसंख्यकों के कल्याण को लेकर झूठ बोलने के अलावा अब तक कोई काम नहीं किया है. यही कारण है कि अब आम जनों और विद्वानों की ओर से ऐसा कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को बंद कर दिया जाना चाहिए.

मौजूदा दौर में दुनिया भर में धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण प्राप्त है. संयुक्त राष्ट्र भी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया कराने पर ज़ोर देता है. विभिन्न देशों के संविधानों में भी इसका ध्यान रखा गया है. जहां तक हमारे देश का सवाल है, कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद संविधान में अल्पसंख्यकों के तमाम अधिकार और सुरक्षा के उल्लेख के बावजूद कोई गंभीर प्रयास नहीं किया. मार्च 1977 में मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की सरकार को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने अल्पसंख्यक मामलों के राष्ट्रीय आयोग के गठन की घोषणा की. इसके बाद पी वी नरसिम्हा रॉव की अगुवाई में 30 सितंबर, 1994 को कांग्रेस की अल्पसंख्यक सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास व आर्थिक कॉर्पोरेशन का गठन किया. फिर 2004 के आम चुनावों में सफलता के बाद कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया और एक साल बाद मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए सच्चर कमेटी का गठन किया और 29 जनवरी, 2006 को विशेष रूप से अल्पसंख्यक मंत्रालय की घोषणा की.

विश्लेषण से पता चलता है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए कभी भी अल्पसंख्यकों के लिए कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया और 1977 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बाद इसे केवल राजनीतिक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल किया. इसका उदाहरण अल्पसंख्यक मामलों के राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, अल्पसंख्यक मंत्रालय और सच्चर कमेटी के क्रियान्वयन में मिलता है. सामाजिक न्याय एवं

सलमान ख़ुर्शीद

के. रहमान ख़ान

ए.आर. अंतुले

अधिकारिता मंत्रालय से काट कर बनाए गए अल्पसंख्यक मंत्रालय ने अब तक बजट आबंटित करने और स्कॉलरशिप बांटने के अलावा कोई नया काम नहीं किया है. यह काम तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भी कर सकता था, फिर अल्पसंख्यक मंत्रालय का क्या औचित्य है? अल्पसंख्यक मंत्रालय को भले ही केन्द्रीय मंत्रालय का दर्जा प्राप्त है, लेकिन वह अपने अधिकतर कार्यक्रमों को लागू करने के लिए या तो राज्य सरकारों पर निर्भर है या फिर स्वयंसेवी संगठनों पर. उसके पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है, जिससे यह मालूम हो सके कि उसने अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित जिन विकास कार्यों को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से बजट पास करवाए हैं, उन पर उचित ढंग से क्रियान्वयन हो भी रहा है या नहीं. 2001 की जनगणना के अनुसार, देश में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी लगभग 18.4 प्रतिशत है, जिनमें से मुसलमानों की आबादी 13.4 प्रतिशत, ईसाइयों की 2.3 प्रतिशत, सिक्खों की 1.9 प्रतिशत, बौद्धों की 0.8 प्रतिशत और पारसियों की आबादी 0.007 प्रतिशत है. कांग्रेस अल्पसंख्यकों के नाम पर अगर केवल मुसलमानों का ही नाम लेती है, तो इसका एकमात्र उद्देश्य चुनावों में मुस्लिम वोट हथियाना है. आंकड़ों से पता चलता है कि लोकसभा की 35 ऐसी सीटें हैं, जहां पर मुसलमानों की आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है, जबकि 38 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 21 से 30 प्रतिशत के बीच है और 145 सीटों पर मुसलमानों की आबादी 11 से 20 प्रतिशत के बीच है. जब भी आम चुनाव नज़दीक आते हैं, कांग्रेस मुसलमानों का वोट हथियाने के लिए तरह–तरह के हथकंडे अपनाने लगती है.

लोकसभा चुनाव नजदीक देख कांग्रेस ने फिर से मुसलमानों से झूठ बोलना शुरू कर दिया है. केन्द्रीय मंत्री के रहमान कह रहे हैं कि उनके मंत्रालय ने सच्चर कमेटी की 76 अनुशंसाओं में से 73 को लागू कर दिया है. चौथी दुनिया ने जब पड़ताल की तो पता चला कि आरंभिक 22 अनुशंसाओं में 12 अनुशंसाओं को यूपीए सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है. यूपीए सरकार के मंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं. सरकार ने अपनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में अल्पसंख्यक मंत्रालय को 7 हज़ार करोड़ रुपये आबंटित किए थे, मंत्रालय का दावा है कि उसने उन रुपयों में से 6,824 करोड़ रुपये ख़र्च कर दिए हैं, राशि ही ख़र्च की गई. सच्चाई यह है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय ने वर्ष 2008–09 में केन्द्र सरकार को 33.63 करोड़, 2009–10 में 31.50 करोड़ और 2010–11 में 587 करोड़ रुपये इसलिए वापस लौटा दिए, क्योंकि उन पैसों को ख़र्च ही नहीं किया जा सका. अल्पसंख्यक मंत्रालय की असमर्थता को देखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने कड़ी आपत्ति जताई थी. अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 90 ज़िलों में बहु क्षेत्रीय विकास के तहत विभिन्न योजनाओं पर ख़र्च करने के लिए केन्द्र की ओर से इस मंत्रालय को जो 462.26 करोड़ रुपये दिए गए थे, वह भी उसने केन्द्र को लौटा दिए गए. इस प्रकार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की 24 करोड़ रुपये की राशि, मैट्रिक स्कॉलरशिप की 33 करोड़, मैरिट कोमेंस स्कॉलरशिप की 26 करोड़ और वक़्फ़ बोर्ड के कंप्यूटरीकरण की 9.3 करोड़ रुपये की राशि को अल्पसंख्यक मंत्रालय ख़र्च करने में असफल रहा और नतीजतन इस पूरी राशि को इसे केन्द्र को वापस करना पड़ा. ऐसी स्थिति जबकि सच्चाई यह है कि मंत्रालय ने राज्यों को जो राशि आबंटित की थी, उनमें से अधिकतर राशि ख़र्च ही नहीं की गई. हाल ही में जारी सोशल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2012 के अनुसार, 2007–12 के दौरान राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यकों से संबंधित केन्द्र की ओर से जारी की गई राशि में से आधी राशि भी ख़र्च नहीं की. 12 राज्यों ने अल्पसंख्यकों से संबंधित 50 प्रतिशत से भी कम ख़र्च किया, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और असम जैसे राज्य सूची में ऊपर हैं. कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जहां पर इसमें से केवल 20 प्रतिशत में अल्पसंख्यकों, विशेषत: मुसलमानों के विकास के बारे में कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के सभी दावे खोखले ही साबित हो रहे हैं. सच्चर कमेटी ने सबसे अधिक ज़ोर मुसलमानों की शिक्षा व पिछड़ेपन को दूर करने पर दिया था, लेकिन 7 वर्ष बाद भी मुस्लिम समाज की शिक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए अलग से किसी प्रकार के आरक्षण की व्यवस्था भी अब तक नहीं की जा सकी है. ■

tabrez@chauthiduniya.com

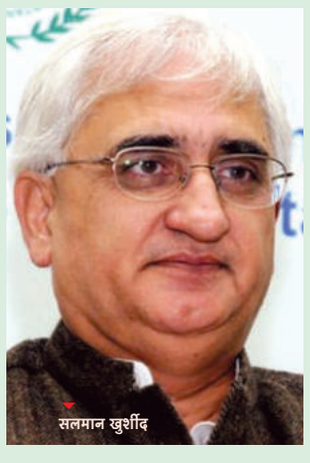

अल्पसंख्यक मंत्रालय का ढांचा

यूपीए सरकार ने भारत के अल्पसंख्यकों के कल्याण से संबंधित कल्याणकारी कार्यक्रमों को उचित ढंग से क्रियान्वित करने के लिए 29 जनवरी, 2006 को एक नया मंत्रालय बनाया और उसका नाम रखा अल्पसंख्यक मंत्रालय. इसे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से अलग करके एक नया मंत्रालय बनाया गया. महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुर्रहमान अंतुले को इसका पहला मंत्री बनाया गया, जो 2009 तक इस पद पर रहे. इसके बाद सलमान ख़ुर्शीद को अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया, जो 2012 तक इस पद पर रहे. वर्तमान मंत्री के रहमान ख़ान हैं, जिन्होंने 28 अक्टूबर, 2012 को अल्पसंख्यक मंत्री का पद संभाला था. वर्तमान में नैनोंग एरंग इसके राज्यमंत्री हैं. अल्पसंख्यक मंत्रालय के कुल पदाधिकारियों की वर्तमान संख्या 93 है, जिनमें एक सचिव, तीन संयुक्त सचिव और व आर्थिक सलाहकार (अतिरिक्त प्रभार) शामिल हैं. आश्चर्य की बात यह है कि 2006 में जिस समय यह मंत्रालय बनाया गया था और अब्दुर्रहमान अंतुले को जब इसका मंत्री बनाया गया था, इस समय इसके लिए अलग से न तो कोई भवन था और न ही कोई स्थायी कार्यालय, बल्कि एआर अंतुले जंतर मंतर रोड पर स्थित अपने सरकारी आवास से इसे चलाते थे, लेकिन आज, जब इस मंत्रालय के पास अपना कार्यालय भी है और इसके स्टाफ में कुल 93 सरकारी अधिकारी भी मौजूद हैं, फिर भी रहमान ख़ान अपने मंत्रालय को ठीक ढंग से नहीं चला पा रहे हैं. ■

भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने गुजरात में मुसलमानों को अन्य समुदायों के बराबर मौक़ा दिया है. वे विकास और भ्रष्टाचार के ख़ात्मे का मुद्दा आगे करके चुनाव में उतरे हैं. मोदी आजकल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में मुसलमानों की उपस्थिति भी दर्शायी जा रही है.

राजनीतिक पार्टियों की निगाह में

मुसलमान केवल मतदाता है

लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं. वोट बैंक की राजनीति फिर से शुरू हो गई है. सभी राजनीतिक दल वोट बटोरने के लिए सबसे ज़्यादा मुस्लिम समुदाय को लुभाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क़रीब 220 सीटों पर मुस्लिम मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं. आमतौर पर कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा भी इस बार कट्टर छति वाले नरेंद्र मोदी की अगुआई में मुस्लिमों को रिझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन मुसलमानों का मसीहा होने का दावा करने वाली किसी पार्टी के पास मुस्लिम समुदाय के लिए कोई स्पष्ट कार्यक्रम अब तक नहीं है, न ही पुराने वादे पूरे किए गए हैं. यह अब तक किसी ने घोषणा नहीं की है कि वे अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए क्या करने जा रहे हैं. सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक दल मुसलमानों को केवल वोट बैंक भर समझते हैं?

कृष्णकांत

आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक दलों में सबसे ज़्यादा खींचतान मुस्लिम वोटों को लेकर मची है. सारे दल अपने को मुस्लिमों का एकमात्र मसीहा बताकर उनके वोट बटोर लेने की जुगत में लगे हैं. हाल ही में भाजपा और आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के प्रमुख इलाकों में मस्जिदों के बाहर पर्चे बांटकर मुस्लिमों के कल्याण के दावे किए और उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश की. केंद्र में कांग्रेस और राज्यों में सपा, बसपा और जदयू जैसी क्षेत्रीय पार्टियां भी मुस्लिम हितों की एकमात्र झंडाबरदार होने के दावे करती रही हैं. सबसे दिलचस्प तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जो हिंदू कट्टरता को बढ़ावा देकर वजूद में आई और जिसकी पहचान ही एक सांप्रदायिक पार्टी की है, वह भी मुस्लिम मतदाताओं को अपने पाले में खींचने के प्रयास में लग गई है. उससे भी मज़ेदार बात यह है कि भाजपा द्वारा मुसलमानों को रिझाने की यह कोशिश उन नरेंद्र मोदी की अगुआई में हो रही है, जिनपर गुजरात में मुसलमानों के विरुद्ध नरसंहार सरीखा दंगा कराने का आरोप है. जिन मोदी ने गुजरात में अपनी सद्भावना यात्रा के दौरान मुस्लिम टोपी पहनने से इन्कार कर दिया था, अब उन्हीं मोदी की रैलियों में दाढ़ी और टोपीधारी मुसलमानों को विशेष प्रयास करके बुलाया जा रहा है. सवाल यह है कि क्या भाजपा की इन कोशिशों से देश का मुसलमान मोदी और भाजपा का दामन थामने का कोई कारण है?

दरअसल, भारतीय राजनीति में मुस्लिम समुदाय की ओर पर्याप्त और मजबूत प्रतिनिधित्व न होने की वजह से उनकी आवाजें तो कभी सुनी नहीं गईं, लेकिन उन्हें शिक्षा, विकास और आर्थिक अवसर देने के नाम पर बरगलाया जाता रहा है. आज़ादी के बाद देश में यह स्थिति नहीं थी. लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद एक आदर्शवादी राजनीति की नींव पड़ी थी. देश से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का वादा किया गया था, जहां सबके लिए जगह थी, सबके लिए समान अवसर थे, लेकिन साठ के दशक में सांप्रदायिकता के उभार के बाद स्थितियां बदल गईं. मुस्लिम समुदाय असुरक्षित महसूस करने लगा तो कांग्रेस, जो उस समय एकमात्र पार्टी थी, उसने हिंदू सांप्रदायिकता के उलट मुस्लिम सांप्रदायिकता को संरक्षण दिया और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की. अयोध्या में राम मंदिर के बहाने हिंदू सांप्रदायिकता को आधार बनाकर जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तो गैर–भाजपाई दलों को मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का और ज्यादा अवसर उपलब्ध हो गया. कांग्रेस के अलावा क्षेत्रीय दलों सपा, जदयू, राजद आदि ने मुस्लिम हितों के संरक्षण का दावा करके वोट बटोरने की राजनीति शुरू की. भाजपा के हिंदू राष्ट्रवाद से मुस्लिम समुदाय में जो डर बैठा, अन्य दलों ने उसका फायदा उठाया, लेकिन आज स्थिति यह है कि मुस्लिम समाज जहां था, वहीं ठहरा है. कांग्रेस छह दशकों से केंद्र की राजनीति में रही है, लेकिन वह मुस्लिम हितों के लिए गंभीर नहीं रही. पिछले दस साल से वह सत्ता में है और सच्चर समिति व रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया. पिछले दशकों की भांति इन दस सालों में भी देश के मुसलमानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया. इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमानों को जहां कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है, वहीं उसे नये राजनीतिक नेतृत्व की तलाश है, लेकिन भाजपा जिस हिंदू सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, उससे मुसलमानों का डर स्वाभाविक है.

भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी तर्क दे रहे हैं कि उन्होंने गुजरात में मुसलमानों को अन्य समुदायों के बराबर मौका दिया है. वे विकास और भ्रष्टाचार खात्मे का मुद्दा आगे करके चुनाव में उतरे हैं. मोदी आजकल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और उनकी रैलियों में मुसलमानों की उपस्थिति भी दर्शायी जा रही है. दिल्ली में 29 सितंबर को मोदी की रैली प्रस्तावित हुई तो जमात–ए–उलेमा–ए–हिंद ने कहा कि वह 20 हजार मुसलमानों के साथ मोदी की इस रैली का समर्थन करेंगी. संगठन के अध्यक्ष मौलाना सुहैब कासमी ने रैली के पहले जमात की बैठक में कहा कि कांग्रेस ने 65 सालों में मुसलमानों को ठगा है. अब उसे इसका ख़ामियाजा भुगतना होगा. हम कांग्रेस के इस प्रचार को झुठलाना चाहते हैं कि मुसलमान भाजपा के साथ नहीं है. हम 20 से 25 हज़ार मुसलमानों के साथ मोदी की रैली में पहुंचकर उनका समर्थन करेंगे. उस रैली में मुसलमानों की उपस्थिति दिखी भी, जब मंच के सामने करीब दो हज़ार मुसलमान आगे की पंक्तियों में बैठाए गए. इससे पहले मोदी की भोपाल रैली में मुसलमानों की उपस्थिति दर्ज की गई, जिसके बारे में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा रैली में आने के लिए खुद से बुर्के ख़रीदकर मुस्लिम महिलाओं में बांट रही है. भाजपा ने इस आरोप को नकारा और 50 हज़ार मुसलमानों के रैली में आने का दावा किया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वास्तव में यह असंभव–सा लगने वाला राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिलेगा कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस समेत अपने धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करने वाली अन्य पार्टियों को छोडकर भाजपा की ओर शिफ्ट होगा? कुछ मुस्लिम विद्वानों का कहना है कि कांग्रेस और धर्मनिरपेक्षता के झंडाबरदार दलों का मुस्लिम हितों के प्रति रिकॉर्ड बेईमानी भरा रहा है, इसलिए मुसलमान भाजपा की ओर जा तो सकते हैं, लेकिन मोदी और भाजपा को अपना सांप्रदायिक सुर बदलना पडेगा. उन्हें मुस्लिमों की समस्या पर बात करनी होगी. उन्हें चुनाव के पहले यह भरोसा देना होगा कि वे सत्ता में मुसलमानों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिकी आदि पर उल्लेखनीय ढंग से गौर करेंगे. इसके अलावा मोदी पर गुजरात दंगे की कालिख भी है, जिससे निपटना आसान नहीं है. उन्हें सब बातों से परे सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को सुरक्षा का भरोसा देना होगा.

नरेंद्र मोदी गुजरात दंगों के बाद से ही मजहब को लेकर कुछ कहने से बचते रहे हैं. हालांकि, उन्होंने 29 सितंबर की रैली में मजहब से ऊपर संविधान को रखते हुए अपनी उदार छवि पेश करने की कोशिश की. मोदी ने कहा कि सरकार का अपना चरित्र होता है, अपना संस्कार होता है. मेरे लिए एक ही मजहब है–नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट. मेरे लिए एक ही पवित्र धर्मग्रंथ है और वह है भारत का संविधान. मेरा एक ही कर्म है–देश के सवा सौ करोड़ लोगों की सेवा करना. हमें सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है. भाजपा भी मोदी की छवि को बदलना चाह रही है, ताकि मुस्लिमों को साथ लेकर चुनावी सफलता हासिल कर सके.

मोदी ने दिल्ली में अपनी रैली में भले ही मुसलमानों को अपनी रैली में न्यौता देकर विशेष रूप से उनके बारे में कुछ न कहा हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास जैसा जुमला और संविधान की सर्वोच्चता को अगर उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया है, तो इसका अर्थ यही है कि वे राष्ट्र को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, संविधान के मुताबिक चलाएंगे. वे भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित करने के सपने को पीछे छोड़कर सभी नागरिकों के साथ समान बर्ताव करेंगे. क्या मोदी ऐसा कर सकेंगे? अब तक यह माना जाता है कि मुसलमानों ने कमोबेश गैर–बीजेपी दलों को ही वोट दिया है. कहा जाता है कि जिन राज्यों में भाजपा के विरोध में कोई अन्य विकल्प मौजूद हैं, वहां मुसलमान भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए टैक्टिकल वोटिंग करते हैं. मोदी के मामले में मुसलमानों का डर भाजपा की अपेक्षा अधिक है.

फिलहाल सभी दल अपने को मुस्लिम हितों का संरक्षक घोषित करने में लगे हैं, लेकिन किसी के पास अब तक कोई स्पष्ट कार्यक्रम नहीं है, न ही किसी दल ने कोई अहम घोषणा की है. वे एक बड़े वोट बैंक पर अपनी गिद्ध दृष्टि तो जमाए हुए हैं, लेकिन उस समुदाय के लिए क्या करने जा रहे हैं, इस बारे में ख़ामोश हैं. आप पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने ज़रूर रमजान के दौरान स्कूलों में उर्दू को वैकल्पिक विषय के रूप में लागू करने और दिल्ली वक़्फ़ बोर्ड को राजनीतिक चंगुल से मुक्त कराने का वादा किया. ऐसी परिस्थितियों में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस और अन्य दलों से राजनीतिक धोखेबाज़ी का बदला लेने के लिए भाजपा के साथ जाएगा या अपने अन्य विकल्पों पर ही फिर से भरोसा करेगा, यह आने वाले चुनाव बताएंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

मुस्लिम वोटों का गुणा–गणित

देश में मुसलमानों की कुल आबादी 18 करोड़ है. अनुमान के मुताबिक, सभी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से 218 क्षेत्रों में मुसलमानों की मतदान में हिस्सेदारी 10 फ़ीसद से ज़्यादा है. लगभग 70 सीटों पर 20 फ़ीसद से अधिक निर्णायक मुस्लिम मतदाता हैं. इन सीटों पर भाजपा की कोशिश होती है कि यदि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर हो जाए तो उसे इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा. कांग्रेस और अन्य दल मुस्लिम वोटों को लक्ष्य बनाते हैं. देश भर में लोकसभा की क़रीब 150 सीटों पर मुसलमानों की वोट हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से ज़्यादा है और यहां पर जीत का अंतर 10 फ़ीसद से कम है. चूंकि मुस्लिम वोटरों के उलट हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण भाजपा या किसी एक पार्टी की ओर हो सकना मुश्किल होता है, इसलिए अपने को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले सभी दल निर्णायक मुस्लिम वोट अपने पक्ष में करने की ताक़त झोंकते हैं. कुछ लोकसभा सीटों में से क़रीब 220 सीटें ऐसी हैं, जिनपर मुस्लिम मतदाता सांसद तय करने की स्थिति में हैं. ये सीटें उन सीटों से अलग हैं, जहां मुस्लिम उम्मीदवार जीतते हैं. फ़िलहाल संसद में मुस्लिम सांसद सिर्फ़ 30 हैं. ये कुल संसद सदस्यों का लगभग छह फ़ीसद है, जबकि कुल आबादी में मुसलमान 14 फ़ीसद हैं. उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से पश्चिम की दो दर्जन सीटों पर मुसलमान 20 फ़ीसद से ज़्यादा हैं. इन आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही पार्टियां अपनी रणनीति बना रही हैं.

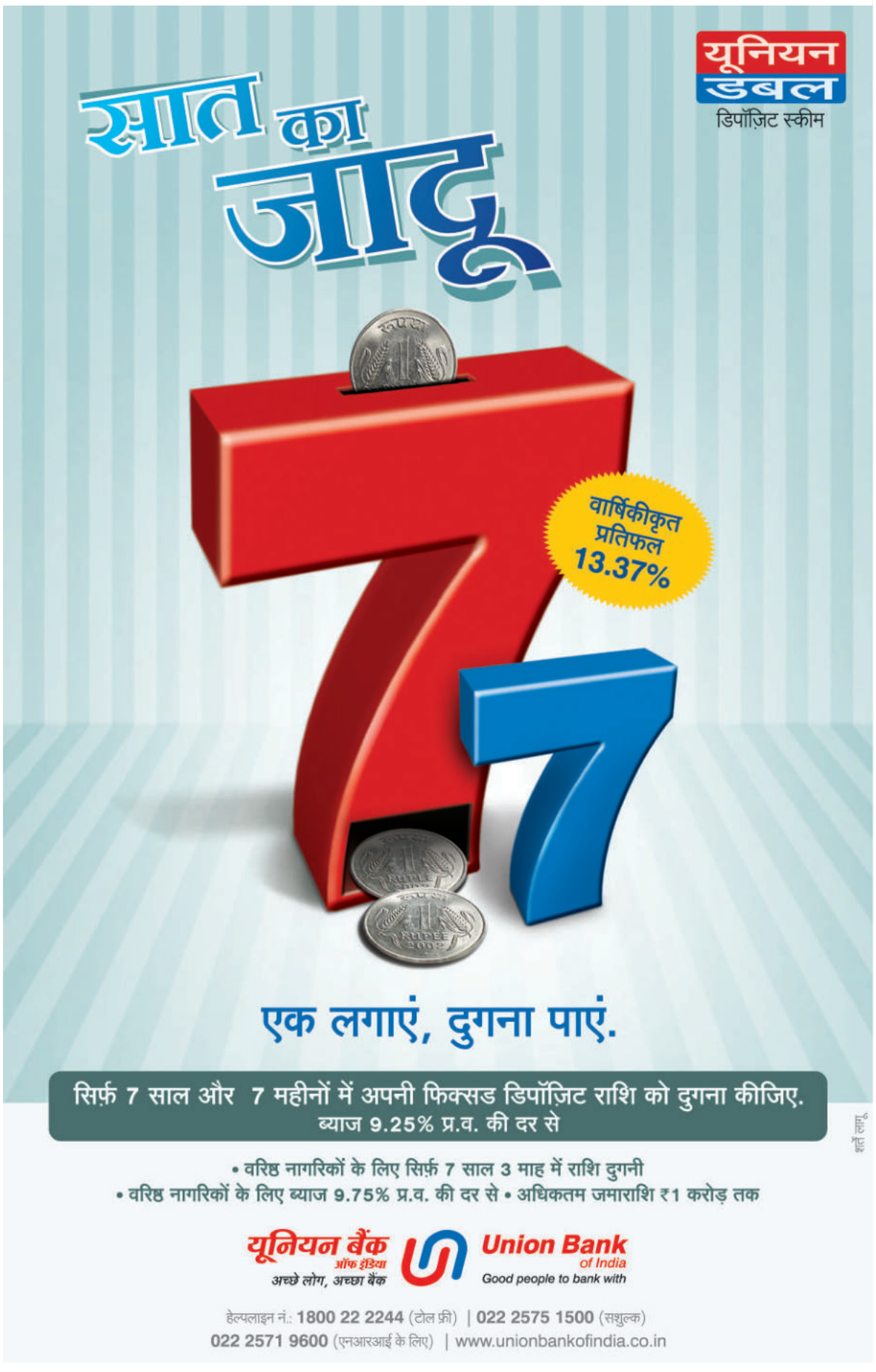

केंद्र में वी.पी. सिंह की सरकार के दौर से ही इस राज्य के राजनीतिक क्षत्रपों का दबदबा शिद्दत से महसूस किया जाने लगा था. एआईएडीएमके की प्रमुख जयललिता 90 के दशक में तेज़ी से राजनीतिक पटल पर उभरीं और उन्होंने तमिलनाडु के साथ–साथ सीधा दिल्ली पर निशाना साधा. उसके बाद से वह हों या डीएमके पार्टी के एम. करुणानिधि, इन दोनों की हर बार चुनावों के बाद केंद्रीय गठबंधन में जुड़ने की बातें सामने आती ही हैं.

भाषा की राजनीति का गढ़ है तमिलनाडु

राजनीतिक स्तर पर तमिलनाडु ने देश को कई स्थापनाएं दी हैं. क्षेत्रीय दलों को केंद्रीय राजनीति से जोड़ना और भाषा की राजनीति को वोट की राजनीति में तब्दील करने की शुरुआत तमिलनाडु से ही हुई, लेकिन इस राज्य में भी राजनीतिक दांव–पेंच उसी पैमाने पर खेले जाते हैं, जैसे देश के अन्य राज्यों में. चुनावी माहौल में चौथी दुनिया की यह कोशिश है कि अपने हिंदी पट्टी के पाठकों को गैर हिंदी भाषी राज्यों के राजनीतिक माहौल से अवगत कराए. इस कड़ी के दूसरे अंक में आइए समझते हैं दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु का राजनीतिक परिदृश्य.

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी ने आंदोलन की संपर्क भाषा का काम किया था और स्वाधीनता के बाद हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा मानना उस दौर में हिंदी की भूमिका की स्वाभाविक स्वीकृति थी. यहां तक देश में एकजुटता की राजनीति थी और देश के सामने आज़ादी ही एक मुद्दा था. 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी तो एकाएक भाषा की राजनीति सामने आई और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने का विरोध शुरू हुआ.

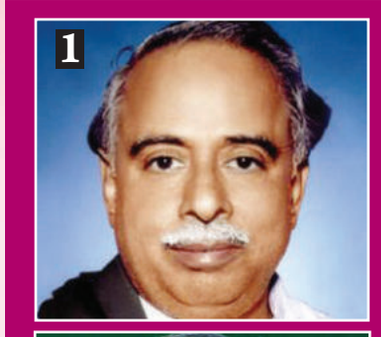

1. सीआर अन्नादुरई
2. ईवी रामास्वामी पेरियार
3. जे जयललिता
4. एम करुणानिधि
5. एनटी रामाराव

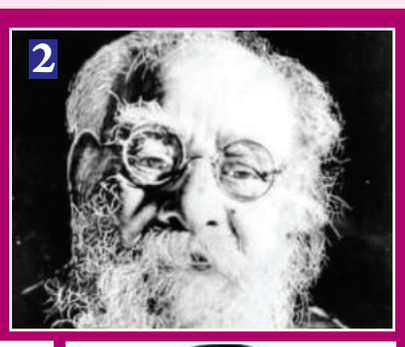

नीरज सिंह

भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के मद्देनज़र तमिलनाडु की पड़ताल करें तो इस राज्य ने देश को क्षेत्रीय दलों की राजनीति से सबसे पहले अवगत कराया. अंग्रेज़ों से स्वाधीनता की लड़ाई लड़ते हुए देश जब राजनीति का ककहरा सीख रहा था, मद्रास रेजीडेंसी में 1916 में जस्टिस पार्टी नाम से एक क्षेत्रीय दल का गठन हुआ. यही वजह है कि आज भी तमिलनाडु में राज्य सरकार क्षेत्रीय दलों की ही बनती है, लेकिन यह क्षेत्रीय दल केंद्र की राजनीति में पूरी दख़ल रखते हैं. मौजूदा संदर्भों में उत्तर भारतीय राज्यों या यों कहें कि हिंदी भाषी राज्यों की तुलना में दक्षिण भारत की राजनीति को देखें, तो जिस तरह उत्तर भारत में राजनीतिक पार्टियों ने जाति को आधार बनाकर राजनीति में पैठ बनानी शुरू की, उसी तरह तमिलनाडु में दलों ने भाषा को आधार बनाकर जनभावनाओं को अपने पक्ष में करना शुरू किया. धूमिल की कविता की एक पंक्ति इस स्थिति की बड़ी सटीक व्याख्या करती हैं कि बहस के लिए भूख की जगह, भाषा को रख दिया. भाषा की इस भ्रामक राजनीति की कहानी तमिलनाडु की राजनीति में शुरुआत से जुड़ी हो, ऐसा नहीं है. वास्तव में जब उत्तर भारत में जातीय राजनीतिक की सुगबुगाहट शुरू भी नहीं हुई थी, तब तमिलनाडु में दलित और पिछड़ी जातियों को लेकर राजनीतिक आंदोलन अपना रंग जमा चुका था. 1916 में टीएम नायर और राव बहादुर त्यागराज चेट्टी ने पहला ग़ैर–ब्राह्मण घोषणापत्र जारी किया था और 1921 में जस्टिस पार्टी ने स्थानीय चुनाव जीता था. बाद (संभवतः 1944) में ईवी रामास्वामी यानी पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया. ये एक ग़ैर राजनीतिक पार्टी थी, जिसने पहली बार द्रविड़नाडु (द्रविड़ों का देश) बनाने की मांग रखी थी. बहरहाल, यहां तक भाषा की राजनीति दिखाई की आहट नहीं आ पाई थी. दरअसल, भाषा के आधार पर जो विभाजन हुए, वह स्वतंत्रता के बाद हुए. ऐसा क्यों है पहले इसे समझते हैं.

स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी ने आंदोलन की संपर्क भाषा का काम किया था और स्वाधीनता के बाद हिंदी को राष्ट्र की संपर्क भाषा मानना उस दौर में हिंदी की भूमिका की स्वाभाविक स्वीकृति थी. यहां तक देश में एकजुटता की राजनीति थी और देश के सामने आज़ादी ही एक मुद्दा था. 1956 में जब भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठी तो एकाएक भाषा की राजनीति सामने आई और हिंदी को संपर्क भाषा बनाने का विरोध शुरू हुआ. तमिलनाडु में डीएमके की राजनीति ही हिंदी विरोध पर टिकी हुई है और 1965 से लेकर आज तक वह डीएमके का इतिहास ही हिंदी विरोध का रहा है और उसका भविष्य भी इसी पर निर्भर है, जबकि इधर केंद्रीय राजनीति पर गौर करें तो देश की राजनीति में हमेशा से ही हिंदी केंद्रीय स्थिति में रही. दक्षिण भारत से देश को दो प्रधानमंत्री मिले, जिसमें पी वी नरसिम्हा राव राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पैदा हुए पोलिटिकल इमोशन की देन थे और देवगौड़ा राजनीतिक परिस्थितियों की देन थे. बाकी तेरह प्रधानमंत्री कमोबेश हिंदी पट्टी के रहे. यही वजह है कि अहिंदी भाषी कई बार हिंदी और केंद्रीय सत्ता को एक ही मान लेते हैं. 1965 में तमिलनाडु में भयंकर हिंदी विरोधी दंगे हुए. 50 के दशक में के कामराज और 70 के दशक में. एम. जी. रामचंद्रन ने हिंदी के ख़िलाफ़ ज़ोरदार अभियान चलाया था. इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों ने तमिलनाडु में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया था. लोगों से कहा गया कि इससे तमिल भाषा पिछड़ जाएगी और हिंदी हावी हो जाएगी. भाषा की इस राजनीति के नाम पर एम जी ने ख़ूब वोट भी बटोरे.

यही वह दौर था, जब देश में भाषायी सांप्रदायिकता जन्म ले रही थी. गोवा में मराठी और कोंकणी के बीच झगड़ा बढ़ा. असम समस्या के केंद्र में भाषा ही है. पंजाब समस्या भी भाषा की राजनीति से जुड़ी है. गोरखालैंड आंदोलन की एक मांग नेपाली भाषा की स्वीकृति भी है. गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विरोध होते देख प्रतिक्रया उत्तर में भी दिखी और इसी दौर में लुंगी वालों की पुंगी बजाओ के जुमले जन्म लेने लगे थे.

दक्षिण भारत और विशेषकर तमिलनाडु को छोड़कर धीरे–धीरे समूचे देश में भाषा की राजनीति समाप्त होती रही. मुंबई में शिवसेना को इसे अपवाद के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन तमिलनाडु ने भाषा को राजनीतिक मुद्दा बनाए रखा. यही वजह है कि हिंदी के बाद इंग्लिश को लेकर भी तमिलनाडु में राजनीति गरमाती रही है. पिछले दिनों जब राज्य की मुख्यमंत्री जयललिता जहां सभी सरकारी स्कूलों में तमिल के साथ इंग्लिश मीडियम लागू करना चाहती थीं, वहीं डीएमके सुप्रीमो करुणानिधि ने इसका ज़ोरदार विरोध करना शुरू कर दिया. करुणानिधि का कहना है कि इससे तमिल भाषा पिछड़ जाएगी. तमिल कल्चर भी ख़त्म हो जाएगा. हालांकि ऐसा नहीं है कि जयललिता के भीतर कोई अंग्रेज़ी प्रेम जाग गया है, जो वे अंग्रेज़ी की तरफ़दारी कर रही है. इसके पीछे भी एक चुनावी गुणा–गणित है. दरअसल तमिलनाडु देश का इकलौता राज्य है जहां की शहरी जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या से ज्यादा है. इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेज़ी पूरे विश्व में रोज़गार की भाषा के तौर पर स्वीकारी जा चुकी है. जयललिता लोगों को यह संदेश दे रही हैं कि ग्रामीण तमिलनाडु के लोग अंग्रेज़ी पढ़कर रोज़गार के क़ाबिल बनें तो इसमें हर्ज़ क्या है. ज़ाहिर सी बात है रोज़गार कौन नहीं चाहेगा और इस बहाने से वह जयललिता के पक्ष में जाएगा.

किसी भी राज्य के राजनीतिक पहलुओं को समझने के लिए सबसे पहले वहां की दलीय सांगठनिक स्थिति को समझना होगा. 1916 में टीएम नायर और राव बहादुर त्यागराज चेट्टी ने जब पहला ग़ैर–ब्राह्मण घोषणापत्र जारी किया था, तभी जस्टिस पार्टी का गठन हुआ. बाद में 1944 में ईवी रामास्वामी यानी पेरियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम कर दिया. ये एक ग़ैर राजनीतिक पार्टी थी, जिसने पहली बार द्रविड़नाडु (द्रविड़ों का देश) बनाने की मांग रखी थी. आज़ादी के बाद मद्रास रेसीडेंसी नाम के राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने कांग्रेस के सी राजगोपालाचारी. बाद में यही मद्रास राज्य बन गया. बाद में इसी मद्रास राज्य का नाम तमिलनाडु कर दिया गया.

इस बीच पेरियार और सीएन अन्नादुरई के बीच मतभेद हो गए और पार्टी में अलगाव हो गया. अन्नादुरई ने द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) का गठन किया. साठ के दशक में हिंदी के ख़िलाफ़ हुए आंदोलन ने डीएमके को ताक़त दी और 1967 में डीएमके ने राज्य से कांग्रेस का सफ़ाया कर दिया और सीएन अन्नादुरई डीएमके के पहले मुख्यमंत्री बने. 1972 में डीएमके का विभाजन हो गया और एम जी रामचंद्रन ने ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) का गठन किया.

एमजीआर के निधन ने एआईएडीएमके में भी बंटवारा कर दिया. एक धड़ा उनकी पत्नी जानकी रामचंद्रन के साथ था और दूसरा जे जयललिता के साथ, लेकिन 1989 में एआईएडीएमके की हार के बाद दोनों धड़े फिर एक हो गए. इसके बाद भी डीएमके और एआईएडीएमके में छोटी–मोटी टूट–फूट होती रही, लेकिन यही दोनों दल बारी–बारी से सत्ता संभालते रहे. एमजीआर के निधन के बाद किसी भी एक दल को लगातार दूसरी बार सत्ता नहीं मिली. 90 के दशक में समूचा देश जातीय राजनीति के संक्रमण में फंस रहा था. तमिलनाडु भी इससे अछूता नहीं रहा और जाति के आधार पर कई छोटे–छोटे दलों ने इसी दौर में जन्म ले लिया, मसलन–टीएमसी, पीएमके, वीसीके, एमडीएमके और केएमपी इन सभी दलों ने तमिलनाडु के अलग–अलग इलाक़ों में अपना वर्चस्व कायम किया और फिर वे डीएमके और एआईएडीएमके साथ गठबंधन बनाते रहे.

हालांकि, समूछे भारत कर्नाटक आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और केरल में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है. उनके दम पर इन राज्यों का सत्ता समीकरण बनता–बिगड़ता रहा है. फिर वह विधानसभा चुनाव हों या लोकसभा चुनाव, लेकिन केंद्रीय राजनीति के लिहाज़ से तमिलनाडु दक्षिण भारत का शायद सबसे अहम राज्य है.

केंद्र में वी.पी. सिंह की सरकार के दौर से ही इस राज्य के राजनीतिक क्षत्रपों का दबदबा शिद्दत से महसूस किया जाने लगा था. एआईएडीएमके की प्रमुख जयललिता 90 के दशक में तेज़ी से राजनीतिक पटल पर उभरीं और उन्होंने तमिलनाडु के साथ–साथ सीधा दिल्ली पर निशाना साधा. उसके बाद से वह हों या डीएमके पार्टी के एम. करुणानिधि, इन दोनों की हर बार चुनावों के बाद केंद्रीय गठबंधन में जुड़ने की बातें सामने आती ही हैं, लेकिन अगर मुद्दों को आधार बना कर देखा जाए तो यहां का राजनीतिक माहौल भी आपको वैसा ही लगेगा, जैसा उत्तर भारत में हैं. कुछ वाक्यों से इसे स्पष्ट करते हैं. अगर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत खेलने आती है तो हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दल इसका विरोध करते हैं. कानपुर के इडेन गार्डेन में ऐसे ही एक बार खेल से पहले शिव सैनिकों ने पिच खोद दी थी. आईपीएल के पिछले संस्करण के दौरान तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने राज्य में सिंहली विरोधी भावनाओं को देखते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि राज्य में में आईपीएल मैचों को तभी खेलने की अनुमति दी जाएगी, जब इन मैचों में श्रीलंका का कोई खिलाड़ी, अम्पायर, अधिकारी या सहयोगी स्टाफ शामिल न हो. श्रीलंका के पूर्व कप्तान ने जयललिता के इस राजनीतिक क़दम का बड़ा ही क़रारा जवाब देते हुए कहा था कि जयललिता और करुणानिधि दोनों श्रीलंकाई खिलाड़ियों को तमिलनाडु में खेलने से इसलिए रोकना चाहते हैं, क्योंकि वे श्रीलंका पर मानव अधिकारों के हनन का आरोप लगा रहे हैं. इसलिए तमिलनाडु को छोड़कर अन्य भारतीय राज्यों में खेलने का मतलब हमारे देश के ख़िलाफ़ लगाए गए मानव अधिकारों के हनन के आरोपों का समर्थन है. रणतुंगा ने तमिलनाडु के दोनों नेताओं पर खेलों के साथ राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा था कि वे तमिलनाडु में चुनावों के समय को छोड़कर कभी उत्तर और पूर्व (श्रीलंका) के तमिलों के कल्याण के लिए चिंतित नहीं दिखते. ऐसा ही एक उदाहरण और है कि दीपा मेहता की फ़िल्म वाटर का बनारस में हिंदूवादी संगठनों ने राजनीतिक रंग देते हुए जमकर विरोध किया था, यह कहते हुए कि वाटर 1930 के दशक में बनारस में हिंदू विधवाओं की दिक्कत को दर्शाती हैं. तमिलनाडु की ओर चलें तो कमल हासन की फ़िल्म विश्वरूपम पर कुछ मुस्लिम संगठनों ने राजनीतिक रंग देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की और राज्य सरकार ने इस पर 15 दिन का प्रतिबंध लगाया. इन उदाहरणों से साफ़ है कि चाहे दक्षिण हो या उत्तर, राजनीतिक स्तर पर खेले जाने वाले दांव–पेच लगभग एक से ही हैं.

लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसके मद्देनज़र देखें तो सबसे ज्यादा उठापटक तमिलनाडु में ही दिख रही है. डीएमडीके मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में उभरता हुआ सबसे नया धूमकेतु है, यही वजह है कि राहुल गांधी जिनसे मिलने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को समय नहीं मिल पाता, वो राहुल गांधी डीएमडीके के नेता विजयकांत को जन्मदिन की बधाई देते हैं. अन्नाद्रमुक 2014 के लोकसभा चुनावों में वामपंथी पार्टियों के साथ और भाजपा के नैतिक समर्थन के बल पर लड़ेगी. आम राजनीतिक समझ रखने वाले को यह विचित्र लग सकता है, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा ही होता है. तमिलनाडु में अल्पसंख्यक यानी मुसलमान और ईसाई मतदाता द्रमुक का साथ पारंपरिक रूप से देते आए हैं, लेकिन इस वर्ष रमजान के महीने में जयललिता ने राज्य की हर उस मस्जिद को मुफ्त चावल बांटे, जिन्होंने इसकी मांग की, ताकि ग़रीब रोजेदारों को इफ़्तारी के लिए अनाज मुहैया कराया जा सके. सब्सिडी वाले खाद्यन्न मुहैया कराने की योजना के दम पर जयललिता ने एक ऐसा आधार बनाया है, जिसके खिसकने की उम्मीद न के बराबर है. राजनीति चाहे उत्तर की हो या दक्षिण की, एक बात तो साफ़ है मुद्दे लगभग वैसे ही रहते हैं. परिस्थितियां तक़रीबन वैसी ही रहती हैं. राजनीतिक दांव–पेंच लगभग वैसे ही रहते हैं. हां, तमिलनाडु के यह सारे प्रकरण इसलिए मौजूं और समझने योग्य हैं, क्योंकि कई बार केंद्रीय स्तर पर राजनीतिक राजनीतिक स्थिरता या अस्थिरता का ख़ाका खींचने में यह राज्य महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है. ■

जिस तरह उत्तर भारत में राजनीतिक पार्टियों ने जाति को आधार बनाकर राजनीति में पैठ बनानी शुरू की, उसी तरह तमिलनाडु में दलों ने भाषा को आधार बनाकर जनभावनाओं को अपने पक्ष में करना शुरू किया. धूमिल की कविता की एक पंक्ति इस स्थिति की बड़ी सटीक व्याख्या करती हैं कि बहस के लिए भूख की जगह, भाषा को रख दिया. जब उत्तर भारत में जातीय राजनीतिक की सुगबुगाहट शुरू भी नहीं हुई थी, तब तमिलनाडु में दलित और पिछड़ी जातियों को लेकर राजनीतिक आंदोलन अपना रंग जमा चुका था.

संतोष की बेटी राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर कार्यरत हैं और उनका बेटा जयपुर में क़ानून की पढ़ाई कर रहा है. दोनों बच्चों को अपने माता–पिता के किसान होने पर गर्व है. उन्हें इस बात पर फ़ख्र है कि उनकी मां की एक प्रगतिशील महिला किसान के रूप में पहचान है. संतोष को भी अपनी किसान वाली पहचान पर गर्व है. वह कहती हैं कि किसान होना कोई मजबूरी नहीं है. खेती करना किसान का कर्म है.

जुझारू महिला ने दिया खेती को नया आयाम

भारतीय समाज के लिए यह सुखद तस्वीर है कि देश की आधी आबादी अब चहारदीवारी से बाहर निकलकर पुरुषों की बराबरी में खड़ी दिखाई देती है, लेकिन अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां काम के नज़रिये से तो महिला पुरुषों के बराबर है, लेकिन नाम के नज़रिये से काफ़ी पीछे, लेकिन मोरारका फाउंडेशन की मदद से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के सीकर ज़िले की एक महिला संतोष पचार ने इस जुमले को ख़ारिज कर दिया है और खेती के क्षेत्र में वह नये मुकाम गढ़ रही हैं. उनके इस प्रयास को आज बड़े पैमाने पर पहचान भी मिल रही है.

नवीन चौहान

जब किसी किसान का ज़िक्र आता है, तब अनायास ही हमारे ज़ेहन में खेत में हल चलाते एक पुरुष की तस्वीर उभरती है. चाहे धान की रोपाई हो या फ़सल की कटाई, हर जगह महिलाएं ही काम करती दिखती हैं. इतना सब होने के बाद भी हम एक महिला को किसान के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते. आज हम बताते हैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में, जो इन पारंपरिक मापदंडों को धता बताकर जैविक खेती के क्षेत्र में सफलता की नई कहानी लिख रही है. राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के सीकर जिले के एक गांव में यह महिला संतोष पचार पुरुषों के साथ क़दम से क़दम मिलाकर चल रही हैं. माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाली संतोष को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कृषि क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए 3 लाख रुपये का राष्ट्रीय नवरत्न प्रतिष्ठा पुरस्कार प्रदान किया है. संतोष की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल है, जो गांव में रहकर चांद छूना चाहती हैं और अपने सपनों में मनचाहे रंग भरना चाहती हैं.

संतोष की कहानी वर्ष 2002 से शुरू होती है. उस साल संतोष के पति जाबरमल पचार के भाइयों के बीच पारिवारिक बंटवारा हुआ. बंटवारे के बाद उनके परिवार के हिस्से में पांच एकड़ ज़मीन आई. इस पांच एकड़ ज़मीन से उन्हें अपना परिवार चलाना था. उनका गांव राजस्थान के पानी की कमी वाले इलाके में आता है. इस वजह से उपज भी कम होती थी. उस दौरान संतोष को मोरारका फाउंडेशन द्वारा चलाए जाने वाले जैविक कृषि कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली. वह अपने पति के साथ फाउंडेशन की जैविक कृषि से संबंधित बैठक में शामिल होने गईं. उस समय वह कृषक बैठकों में शामिल होने वाली उस क्षेत्र की पहली महिला किसान थीं. ऊपर से पर्दा प्रथा के कारण सामाजिक बंदिशें, जिसकी वजह से वह खुलकर अपनी बातें सबके सामने नहीं रख पाती थीं, लेकिन जैविक कृषि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्हें इसके फायदे समझ में आए और इस तरह से खेती करने का तरीक़ा उनकी समझ में आया. इसके बाद उन्होंने जैविक खेती को अपनाने की ठानी, लेकिन उनके पास शुरुआती संसाधन जुटाने के लिए भी पैसे नहीं थे. इसके लिए मोरारका फाउंडेशन ने उनकी मदद की और उन्हें बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए केंचुए उपलब्ध कराए. संतोष ने अपने खेत में बर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेड बनाया और केंचुए उसमें छोड़ दिए. दस–पंद्रह दिन बाद उन्हें बेड में चायपत्ती की तरह दिखने वाली बर्मी कंपोस्ट बनती दिखाई दी. इससे उनका हौसला बढ़ा. 40–45 दिन बाद जब खाद पूरी तरह बनकर तैयार हुई तो उन्होंने सबसे पहले अपनी नर्सरी में इसका प्रयोग किया. संतोष ने जैविक और रासायनिक दोनों तरह की खादों का इस्तेमाल प्याज और गोभी में किया. जब दोनों तरह की सब्जियां तैयार हुईं तो दोनों में उन्हें बहुत अंतर दिखाई पड़ा. खाने में भी दोनों तरह के उत्पादों में ज़मीन–आसमान का फर्क था.

अपने नर्सरी के प्रयोग के बाद उन्होंने एक एकड़ जमीन में जैविक और 4 एकड़ में रासायनिक खेती की. उन्होंने एक एकड़ में जैविक तरीके से प्याज की खेती की. इसके बाद जो परिणाम निकलकर सामने आए, वे बहुत ही आश्चर्यजनक थे. चार एकड़ में उगाई गई प्याज की तुलना में उन्हें एक एकड़ में उगाई गई प्याज से ज्यादा फायदा हुआ. इसके बाद संतोष ने मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने अपनी इस सफलता की जानकारी जिले के कृषि विभाग और ज़िला कलेक्टर को दी. जिले की तत्कालीन कलेक्टर मंजूराज पाल ने संतोष से मुलाक़ात की और उनसे जैविक खेती के बारे में जानकारी हासिल की. कलेक्टर साहिबा ने संतोष के खेतों का दौरा किया. कलेक्टर साहिबा संतोष द्वारा उपजाई गई सब्ज़ियों से इतना प्रभावित हुईं कि बाद में उन्होंने जैविक तरीके से उगी गोभी, गाजर और पालक का सेवन भी किया. कलेक्टर उत्पादों की गुणवत्ता से भी बहुत प्रभावित हुईं. संतोष को जैविक खेती के क्षेत्र में प्रयास के लिए पंचायत स्तर पर ग्यारह हजार रुपये का प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिया गया.

इसके बाद संतोष को कृषि विभाग ने अपनी पूरी खेती जैविक रूप से करने के लिए कहा. इसके लिए उन्होंने हामी भर दी और अपने पति के साथ मिलकर बर्मी कंपोस्ट के पांच बेड बनाए. उन पांच बेडों के लिए आवश्यक गोबर उनके पास उपलब्ध नहीं था. इसके लिए उन्होंने ज्यादा गायें पालनी शुरू कीं, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव उनके जैविक खेती पर पड़ा. तब उनका अधिकांश समय जानवरों की देखभाल में लग जाता था. उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए जानवरों से जुड़े सारे कामों को ऑटोमेटिक बना डाला. उन्होंने जानवरों के दाना–पानी देने के कार्य को एयर वॉल्व और अन्य संसाधनों की मदद से आसान बना लिया. इससे खेत में काम करते वक्त उन्हें जानवरों के दाना–पानी की चिंता नहीं रहती थी. इसके बाद उन्होंने अपनी पूरी खेती जैविक तरीके से करनी शुरू की. उनके इस प्रयास को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सराहा और उन्हें 25000 रुपये से पुरस्कृत किया. इसके बाद संतोष शेखावटी के किसानों के लिए मिसाल बन गईं. हर साल उनका प्रयास निखार लाता गया. इस साल मार्च में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें गाजर की उन्नत किस्म उगाने के कारण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. संतोष यहां भी नहीं रुकीं. अब संतोष ने बाजरे का उत्पादन बढ़ाने का एक अन–ोखा तरीका इजाद किया. उन्होंने बाजरे की फसल के एक फीट के होने के बाद उसकी कटाई कर दी. कटाई का मकसद था कि तना टूटने के बाद पेड़ से पांच से आठ शाखाएं निकलें. हर शाखा में बाजरे का भुट्टा आया और इससे बाजरे का उत्पादन बढ़ गया. संतोष के अनुसार, इस तकनीक का उपयोग करके प्रति बीघा पांच से आठ क्विंटल उत्पादन लिया जा सकता है.

संतोष प्रतिवर्ष जैविक खेती करके पांच से सात लाख रुपये की वार्षिक आमदनी कर लेती हैं. फसल चक्रण से वे अपने कुछ खेतों में दो और कुछ में तीन फसल पैदा करती हैं. गाजर की जिस किस्म के लिए उन्हें राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, उस गाजर का रंग एक जैसा, लंबाई लगभग ढाई फुट है और गाजर के बीच का कड़ा भाग बेहद ही पतला है. अब संतोष का लक्ष्य भारत की सबसे लंबा गाजर और उसके बाद दुनिया का सबसे लंबा गाजर उगाना है. वह आत्मविश्वास से लबरेज हैं और अपनी सफलता की कहानी को एक नया आयाम देना चाहती हैं. उन्होंने गावों में, घरों में रहने वाली हर महिला को एक सपना दिया है. जब वह पहले खेती कार्यक्रमों में भाग लेती थीं तो समाज उनका विरोध करता था, लेकिन आज वही समाज उनकी मुखर होकर प्रशंसा करता है और कहता है कि संतोष ने हमारे घर–गांव का नाम देश–विदेश में रोशन किया है. संतोष बड़े विश्वास के साथ बताती हैं कि पहले किसान बैठकों में जाने वाली अकेली महिला होती थीं, लेकिन मैंने धीरे–धीरे घर, गांव और आसपास की महिलाओं को बैठकों में ले जाना शुरू किया. मैं अब तक 800 से ज्यादा महिलाओं को जैविक खेती का प्रशिक्षण देकर उनकी जिंदगी में बदलाव की पहल कर चुकी हूं. अब वे सभी महिलाएं समाज और परिवार के बेवजह के डर की परवाह किए बिना और कृषि कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर एक बेहतर किसान बनने की दिशा में अग्रसर हैं.

संतोष की बेटी राजस्थान पुलिस में एसआई के पद पर कार्यरत हैं और उनका बेटा जयपुर में कानून की पढ़ाई कर रहा है. दोनों बच्चों को अपने माता–पिता के किसान होने पर गर्व है. उन्हें इस बात पर फ़ख्र है कि उनकी मां की एक प्रगतिशील महिला किसान के रूप में पहचान है. संतोष को भी अपनी किसान वाली पहचान पर गर्व है. वह कहती हैं कि किसान होना कोई मजबूरी नहीं है. खेती करना किसान का कर्म है. किसान के काम को मैं नौकरी से ज्यादा महत्व देती हूं. वे कहती हैं कि सरकार को किसानों को एक कुशल श्रमिक के रूप में मान्यता देनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

संतोष की कहानी वर्ष 2002 से शुरू होती है. उस साल संतोष के पति जाबरमल पचार के भाइयों के बीच पारिवारिक बंटवारा हुआ. बंटवारे के बाद उनके परिवार के हिस्से में पांच एकड़ ज़मीन आई. इस पांच एकड़ ज़मीन से उन्हें अपना परिवार चलाना था. उनका गांव राजस्थान के पानी की कमी वाले इलाक़े में आता है. इस वजह से उपज भी कम होती थी. उस दौरान संतोष को मोरारका फाउंडेशन द्वारा चलाए जाने वाले जैविक कृषि कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली. वह अपने पति के साथ फाउंडेशन की जैविक कृषि से संबंधित बैठक में शामिल होने गईं.

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

अगर पार्टी इस युक्ति के साथ चलती है कि ईमानदार लोगों पर सवाल उठाकर ख़ुद की छवि को पाक़-साफ़ साबित किया जाए, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला. यह कांग्रेस की विश्वसनीयता को कमज़ोर करने और मोदी की विश्वसनीयता में इज़ाफ़ा करने वाला क़दम साबित होगा.

कांग्रेस पार्टी की विश्वसनीयता ख़तरे में है

भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली रैली, जो कि पूर्व सैनिकों के लिए आयोजित थी, उसमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी. के. सिंह भी मंच पर मोदी के साथ दिखाई दिए. जनरल वी. के. सिंह के सेना प्रमुख के कार्यकाल के दौरान ही उनकी उम्र से जुड़ा मामला प्रकाश में आया था और दुर्भाग्य से इस मामले में उन्हें न्याय नहीं मिल पाया. या तो सरकार की तरफ से या फिर माननीय न्यायालय की ओर से. बहरहाल, जनरल वी. के. सिंह गौरवपूर्ण तरीक़े से सेना से सेवानिवृत्त हुए. सेवानिवृत्ति के बाद भी एक ईमानदार छवि होने के नाते उन पर किसी तरह का सवालिया निशान लगाना संभव नहीं है. यहां तक कि सेना के भीतर मौजूद उनके विरोधी भी पूर्व सेनाध्यक्ष पर उंगली नहीं उठा सकते. वी. के. सिंह उसी जज़्बे को बरक़रार रखते हुए देश के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, किसानों से जुड़ी समस्याओं का हल चाह रहे हैं, भूमिहीनों की सहायता करना चाह रहे हैं और जिनकी ज़मीन छीन ली गई है, उनकी बेहतरी की दिशा में काम कर रहे हैं. और भी बहुत कुछ. इसी क्रम में वे पूर्व सैनिकों के लिए आयोजित नरेंद्र मोदी की रैली में शामिल हुए थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो जैसे किसी उन्माद के रोग से ग्रसित हो गई है. जब पार्टी ने देखा कि जनरल वी. के. सिंह नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो सरकार के भीतर खलबली–सी मच गई. कांग्रेस ने जनरल वी. के. सिंह पर झूठे आरोपों की झड़ी लगा दी. जनरल वी. के. सिंह पर जम्मू–कश्मीर में तख़्ता पलट का आरोप लगाया गया. विधायकों को पैसे देकर दल–बदलने के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया.

जम्मू–कश्मीर में तकरीबन सभी मंत्री गैर सरकारी संगठन चलाते हैं. वहां के सिस्टम में है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना के फंड से इन गैर सरकारी संगठनों को पैसे दिए जाते हैं. यह बैक चैनल डिप्लोमेसी का एक तरीक़ा है. मुझे समझ में नहीं आता है कि इस तरह की कूटनीति को साज़िश का नाम क्यों दिया जा रहा है? एकाएक सरकार पूर्व सेनाध्यक्ष पर आरोप लगाने लगती है कि आप सरकार गिराना चाहते थे. यह आरोप समझ से परे है. भला जनरल वी. के. सिंह को जम्मू–कश्मीर सरकार को गिराकर क्या हासिल होगा? वे जम्मू–कश्मीर के मुख्यमंत्री तो बन नहीं सकते और उससे भी हास्यास्पद तो यह है कि उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक मंत्री को 1.09 करोड़ की राशि दल बदलने के लिए दी. कांग्रेस पार्टी को यह समझना चाहिए कि आज के दौर में तो इतनी राशि लेकर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेटर भी दल नहीं बदलेगा. वास्तव में कांग्रेस पार्टी आंकड़ों के मामले में बहुत पीछे चल रही है.

अब चूंकि उन्हें कुछ न कुछ तो कहना ही है, तो पार्टी ने एक साफ और ईमानदार छवि के व्यक्ति को ही आरोपों की ज़द में लेना शुरू कर दिया. कांग्रेस यह भूल रही है कि देश की जनता को इस तरह की छद्म चालबाज़ियों से बहकाया नहीं जा सकता. जनता इस पूरे खेल को समझ रही है. कांग्रेस पार्टी ख़ुद तो पूरी तरह से धोटालों व भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और अब वह एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति पर आरोप लगा रही है. कांग्रेस वास्तव में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है. जनरल वी. के. सिंह कि छवि बेदाग है और उन पर कोई सवालिया निशान भी नहीं है. ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठाने का मतलब है कि आपने या तो अपनी नज़रें बंद कर ली हैं या फिर आप किसी के द्वारा प्रेरित हैं या फिर आप समझते हैं कि जनता बेवकूफ़ है और वह सरकार की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेगी.

वास्तव में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को यथार्थ के धरातल पर उतर आना चाहिए. प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार को चाहिए कि वह पीएम को यह सलाह दें कि इस तरह के दांव–पेंच से जनता का भरोसा नहीं जीता जा सकता. उन्हें विचारधारा पर बात करनी चाहिए. मेरे विचार में यह कांग्रेस के लिए फ़ायदे का सौदा है कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदावार घोषित किया है. कांग्रेस को चाहिए कि वह हर मामले पर इस तरह से प्रतिक्रिया न दे, बल्कि सही मुद्दों को आधार बनाए. अगर आप ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुनते हैं, तो देश ख़तरे में पड़ जाएगा. नरेंद्र मोदी एक तानाशाह हैं. वे सांप्रदायिक मानसिकता के हैं. अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अल्पसंख्यकों की मुश्किलें बढ़ेंगी. ये सभी मुद्दे कांग्रेस पार्टी को फिर से चुनाव जिताने के लिए काफ़ी हैं. हां, हो सकता है कि कांग्रेस को आगामी चुनावों में बहुमत न मिले, लेकिन वह गठबंधन सरकार तो बना ही सकती है, लेकिन अगर पार्टी इस युक्ति के साथ चलती है कि ईमानदार लोगों पर सवाल उठाकर ख़ुद की छवि को पाक़–साफ़ साबित किया जाए, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला. यह कांग्रेस की विश्वसनीयता को कमज़ोर करने और मोदी की विश्वसनीयता में इज़ाफ़ा करने वाला क़दम साबित होगा.

निश्चित रूप से हम इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते कि जनरल वी. के. सिंह को नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर बैठना चाहिए था, लेकिन यह उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है. कांग्रेस पार्टी को और परिपक्वता दिखाने की ज़रूरत है. मैं नहीं जानता की पार्टी के बड़े नेता इस दिशा में क्या कर रहे हैं, पार्टी प्रवक्ता क्या कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की छद्म कोशिशों को तुरंत बंद करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

नौकरशाही में ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ लोगों को रहना चाहिए

ठाकुर दास बंग

नौकरशाही को डरा–धमका कर नीति–भ्रष्ट करने की कोशिश हो रही है, ताकि उसे सत्तारूढ़ पार्टी के अनैतिक कामों का औज़ार बनाया जा सके. ढुलमुल व भ्रष्ट अधिकारियों को जिम्मेदार जगहों पर रखा जाता है, जबकि कर्तव्यनिष्ठ व ईमानदार अफसरों को साधारण व दूर–दराज जगहों में भेज दिया जाता है. जी–हुजूर लोगों को महत्व–पूर्ण जगहों में रखने के लिए वरिष्ठता का नियम तोड़ा जाता है, स्थानान्तरण को सताने के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और नौकरशाही को सत्तारूढ़ पार्टी के अधीन रखने के लिए ऐसे ही दूसरे तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है.

अनुभव से हम नौकरशाही को विकास में बाधक तथा एक जड़ वस्तु के रूप में उसे यथास्थिति का पोषक मानने के अभ्यस्त हो गए हैं. हम नौकरशाही के विस्तार और उसके द्वारा जीवन के हर अंग पर नियंत्रण करने के कड़े आलोचक रहे हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज के समाज में हम नौकरशाही के बिना काम नहीं चला सकते. इसलिए ऐसे संगठन का जो भी न्यून रूप रहे वह निर्दिष्ट नियमों के अनुसार चले, न कि व्यक्तियों की मनमानी के अनुसार. इसमें ईमानदार व कर्तव्यनिष्ठ लोगों को रहना चाहिए. इसी प्रकार लोगों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा संभव हो सकेगी. नौकरशाही का किस तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसकी अनगिनत मिसालें हैं. एक ज्वलंत उदाहरण है बिहार के राज्य परिवहन के जनरल मैनेजर का, जिसे पदोन्नति देकर इसलिए स्थानान्तरित किया गया, क्योंकि उसने राजनीतिक दबदबा रखनेवाले एक भ्रष्ट बस कन्डक्टर के ट्रांसफर व निलंबन का आदेश बदलने से इंकार कर दिया था. अपना विरोध प्रकट करने के लिए अफसर ने पदोन्नति अस्वीकार कर दिया और छुट्टी पर चला गया. खुशी की बात है कि बिहार आईएएस अफसर संघ ने इस मामले को हाथ में लिया.

इस संदर्भ में बिहार के मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया था कि नौकरशाही को राजनीतिक शासकों के अधीन होना ही चाहिए, क्योंकि राजनीतिक शासक लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं. यह सही भी है, बशर्ते राजनीतिक मालिक जनता के हित में तथा देश के संविधान व कानून की निहित सीमाओं में अपने सही कर्त्तव्यों की पूर्ति करे, लेकिन यदि वे इसके विपरीत अपने अवैध व स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के तौर पर व्यवहार करते हैं तो नौकरशाही का यह कर्त्तव्य है कि वह उनकी इच्छाओं के आगे न झुके.

किसी लोकतांत्रिक समाज का एक और भी स्तंभ है, जिसकी ओर थोड़ा कम ध्यान जाता है और वह है स्वायत्त व स्वैच्छिक संस्थाएं. किसी सुदृढ़ लोकतंत्र में ऐसे हजारों संगठन होते हैं, जो एक शांतिपूर्ण क्रांति लाने से लेकर खतरनाक अस्त्र–शस्त्रों की समाप्ति, बेरोजगारी या कैंसर की समाप्ति तथा फुटबॉल टीम व वृद्धा स्त्रियों के क्लब तक कोई भी काम हाथ में ले सकते हैं. वे समस्याओं तथा स्वयं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति लोगों की जागरुकता जीवित रखने में सहायक होते हैं. वे अक्सर लोगों के दृष्टिकोण तथा सामाजिक नियमों एवं सरकारी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में सफल होते हैं. वे अक्सर अच्छे से अच्छे सरकारी संगठनों के मुकाबले भी कई काम ज्यादा जल्दी व असरकारक तौर पर करने में सफल होते हैं. बाढ़, तूफान व भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय सरकारी माध्यमों के मुकाबले लोगों को पहले मदद पहुंचाने में ये स्वयंसेवी संस्थाएं ही सफल होती हैं.

राज्य का क्षीण होना स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सरकार के विशिष्ठ कार्यों को हाथ में ले लेने से अधिक जल्दी पूरा होगा. आदर्श सर्वोदय समाज व्यवस्था का निर्माण न केवल स्वायत्त व आत्म–निर्भर गांवों के द्वारा, बल्कि स्वयंसेवी संस्थाओं के एक सुदृढ़ जाल द्वारा होगा.

इसके विपरीत किसी सुदृढ़ रूप से स्थापित तानाशाही में किसी को शायद ही कोई वास्तविक स्वयंसेवी संगठन मिले. साम्यवादी देशों में सभी स्वयंसेवी दिखाई पड़नेवाली संस्थाएं वास्तव में सरकार द्वारा ही संरक्षित व नियंत्रित रहती हैं. प्रत्येक तानाशाही यह आदर्श पाने की कोशिश करती है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रशासन जीवन के मामूली से मामूली लगनेवाले क्षेत्र में भी अपने नियंत्रण के बाहर कार्य व विचार बर्दाश्त नहीं कर सकता.

कल्पना कीजिए किसी तानाशाही में एक स्वयंसेवी संस्था को कुष्ठ रोगियों के बीच काम करने की अनुमति दी जाती है. कौन जानता है कि ऐसा अहानिकर लगनेवाला संगठन भी कभी कुष्ठ निवारण के लिए निर्दिष्ट पैसे के प्रभावशाली लोगों द्वारा हड़प लेने के, जैसा कि ऐसे प्रशासनों में अक्सर होता है, विरुद्ध विरोध प्रकट कर दे. इसलिए सत्तासीन पार्टी द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं को अपनी इच्छा के अनुरूप बनने के लिए बाध्य करने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है. खादी संस्थाएं उन स्वयंसेवी संस्थाओं का अकेला सबसे बड़ा संगठन है, जो गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर बना था. खादी और ग्रामोद्योग गांधी जी के लिए कोई राहत की प्रवृत्तियां नहीं थीं. वे उनकी अहिंसक क्रांति की एक महान योजना की ही अंग थीं, लेकिन खादी कार्यकर्ता उन कई सूक्ष्म तरीकों के प्रति गवाह होंगे, जिनसे खादी संस्थाओं पर जोर डाला जा रहा है कि वे वर्तमान प्रशासन को अप्रिय लगनेवाले किसी भी विचार से दूर रहें. खादी कमीशन के माध्यम से उन्हें मिलनेवाली सरकारी आर्थिक सहायता को उनके विरुद्ध अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्हें अहिंसक शौर्य से घृणित भीरुता में बदल देने की कोशिश हो रही है. चार प्रमुख अखिल भारतीय गांधीवादी संस्थाओं के कार्यों में खोजबीन के लिए स्थापित आयोग से सरकारी इरादों का पता चलता है.

महाराष्ट्र विधानसभा में अभी एक विधेयक पेश है, जो दातव्य न्यासों से संबंधित अधिनियम में संशोधन करना चाहता है. इस संशोधन से राज्य सरकार को किसी भी ऐसे न्यास में अपना प्रशासक नियुक्त करने की छूट मिल जाएगी, जिसके विरुद्ध दो या तीन व्यक्तियों की शिकायतें प्राप्त हों. इसके लिए अन्य कोई भी आधार जरूरी नहीं है. तब तीन वर्षों के भीतर सरकार ट्रस्टी मंडल में स्वयं अपने आदमियों की नियुक्ति कर सकती है और इस तरह हस्तगत करने की प्रक्रिया पूरी कर सकती है. महाराष्ट्र का यह विधेयक बिहार प्रेस विधेयक की तरह सचमुच एक प्रायोगिक परियोजना है. यदि यह महाराष्ट्र में सफल होती है तो उसे प्रत्येक राज्य में लागू किया जाएगा.

जनता शासनकाल में इन्कम टैक्स अधिनियम में एक व्यवस्था की गई थी, जिसके अनुसार व्यापारी संगठनों द्वारा ग्राम विकास के लिए या तो स्वयं या स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किए खर्च पर आयकर छूट की व्यवस्था थी. परियोजन–ाओं को उपयुक्त सरकारी मंत्रालयों से संबद्ध होना था. यह सुविधा इस वर्ष छिन गई है. कई स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी सहायता से काफी अच्छा काम कर रही थीं. अब ग्राम विकास के लिए नये बने हुए प्रधानमंत्री कोष को दान देने पर आयकर में छूट दी जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

किसी लोकतांत्रिक समाज का एक और भी स्तंभ है, जिसकी ओर थोड़ा कम ध्यान जाता है और वह है स्वायत्त व स्वैच्छिक संस्थाएं. किसी सुदृढ़ लोकतंत्र में ऐसे हजारों संगठन होते हैं, जो एक शांतिपूर्ण क्रांति लाने से लेकर ख़तरनाक अस्त्र-शस्त्रों की समाप्ति, बेरोज़गारी या कैंसर की समाप्ति तथा फुटबॉल टीम व वृद्धा स्त्रियों के क्लब तक कोई भी काम हाथ में ले सकते हैं. वे समस्याओं तथा स्वयं अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति लोगों की जागरूकता जीवित रखने में सहायक होते हैं. वे अक्सर लोगों के दृष्टिकोण तथा सामाजिक नियमों एवं सरकारी नीतियों में आवश्यक परिवर्तन लाने में सफल होते हैं.

पाठकों की दुनिया

झूठी है सरकार

चौथी दुनिया में एक लेख पढ़ा. लेख का शीर्षक था आधारहीन आधार कार्ड. इस लेख में लेखक ने सरकार को लेकर जो नजरिया पेश किया है, उसके अपने तर्क हैं. और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मनीष जी अपने लेख में जो तर्क देते हैं, उसे नकारना शायद किसी के लिए भी टेढ़ी खीर साबित होगी, क्योंकि लेखक अपने किसी लेख में हवा–हवाई बातें नहीं करते. वे जो भी कहते हैं, उसमें तथ्यात्मक विश्लेषण छिपा होता है. इस लेख में वे कहते हैं कि सरकार संसद के भीतर कुछ और कहती है और संसद के बाहर कुछ और. सरकार जब अदालत में जाती है तो वहां कुछ और ही बातें बनाने लगती है. यह बात बिल्कुल सही है. आज तक यह बात समझ में नहीं आई कि यह सरकार है या ठेकेदार, जो झूठ बोलने के लिए ठेका ले रखा है. आए दिन सरकार की सुप्रीम कोर्ट में फजीहत होती रहती है, लेकिन इस भ्रष्टाचारी सरकार को तनिक भी शर्म नहीं आती. लेखक ने जायज सवाल उठाया है कि सरकार और सरकार के नुमाइंदों को विदेशी दबाव के अंदर काम करने की लत लग गई है. निजी कंपनियों को फायदा पहुचाना ही सरकार की प्राथमिकता हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता है कि निजी कंपनियों के लिए रास्ता साफ करना ही अच्छी सरकार की निशानी है. लेखक ने ये सवाल बहुत ही सधे हुए अंदाज में उठाया है. उन्होंने सरकार की नब्ज बहुत अच्छी तरह से पहचानी है. लेखक का लेख हमेशा पाठकों के करीब लगता है, क्योंकि वे जो भी कहते हैं, जनता और पाठकों के दिल की बात कहते हैं.

–राहुल, पटना

मोदी परिस्थितियों की देन हैं

पूरे देश में मोदी घूम–घूम कर प्रचार कर रहे हैं और दिल से प्रचार कर रहे हैं. आखिर प्रधानमंत्री भी तो उन्हें ही बनना है. पहले तो भाजपा के नेताओं में जमकर खींचतान हुई. कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ. अब जाकर मोदी के साथ होने का पार्टी नेता दिखावा कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल जनता के मन में आज भी उठ रहा है कि क्या सचमुच मोदी के साथ भाजपा के नेता हैं, क्या पार्टी में मोदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं है. चौथी दुनिया का लेख मोदी के साथ कौन है, पढ़ने के बाद मन में तैरते इस सवाल को और बल मिल जाता है. संपादक ने इस लेख में बहुत ही सही सवाल उठाया है कि मोदी परिस्थितियों की देन हैं या वास्तव में उनका कद इतना बड़ा हो गया है. मेरी नजर में इसका जवाब तो यही होगा कि मोदी का कद उतना बड़ा नहीं हुआ है, जितना कि परिस्थितियों ने बड़ा कर दिया है. गुजरात दंगा का कलंक जिस पर लगा हो, जिसके राज्य में फर्जी एनकाउंटर के मामले चल रहे हों, जिसमें मंत्री और सरकार के आला अधिकारी तक नप गए हों और नप रहे हों, भला उस राज्य के मुख्यमंत्री का कद इतना बड़ा कैसे हो सकता है. मोदी की उम्मीदवारी के लिए जो भी दावे उनके पक्ष में किए जा रहे हैं, उन पर भी अब सवालिया निशान खड़े होते जा रहे हैं. लेखक ने बहुत ही सटीक टिप्पणी की है कि मोदी के विकास पुरुष होने या उनको विकास पुरुष कहने के पीछे हकीकत कम और चालबाजियां ज्यादा हैं. मोदी की ईमानदारी की मिसाल तो उनके भारी–भरकम सिक्योरिटी, रैलियां और मीडिया प्रबंधन से तो मिल ही जाता है. सवाल यह उठता है कि आखिर बचता क्या है, जो मोदी के पक्ष में जाता है. इसका जवाब होगा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ बड़बोलापन. ऐसे में पीएम को चुनने से पहले सोच–समझकर पार्टी को वोट करना जरूरी हो गया है.

–सोनम, भागलपुर

ये सही सलाह है

पेज नम्बर 8 पर चौथी दुनिया में एक लेख प्रकाशित होता है. यह लेख आत्मसात करने वाला होता है. इस लेख की सबसे खास विशेषता यह होती है कि यह घटनाओं की तात्कालिकता को ध्यान में रखकर लिखा जाता है. इस बार मैंने एक लेख पढ़ा, जिसका शीर्षक था–जो बंटवारा चाहते हों, उन्हें मत चुनिए. मुजफ्फरनगर दंगा धर्मनिरपेक्ष भारत के लिए बहुत बड़ा कलंक है. लेखक ने एक बड़ा सवाल यह उठाया है कि इस दंगे में लोगों को सुरक्षा की तलाश में गांवों से बाहर शहरों की ओर भागना पड़ा. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. सचमुच यह चिंता की बात है. एक बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि आखिर लोग अपने गांव छोड़कर क्यों भागे. इसका जवाब मेरी समझ में यही हो सकता है कि गांव वालों को अपने पड़ोसियों से उनकी जान को खतरा रहा होगा या उन्हें यह लगा होगा कि वे किसी कीमत पर अब सुरक्षित नहीं बच सकते. कोई चारा न देखकर वे गांव छोड़कर शहरों की तरफ भाग गए होंगे. लेखक ने नेताओं पर भी सवाल उठाया है, जो सबसे बड़ी चिंता की बात है. नेताओं के ओछे रवैये के कारण ही लोग राजनीति शब्द को निगेटिव अर्थ में लेते हैं. सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों गंदी राजनीति करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते. लेखक ने अपने लेख में यह भी बताने की कोशिश की है कि अवसरवादी राजनीति कैसे बिना स्वार्थ के दो कदम भी नहीं चलती. गंदी और बांटने की राजनीति करने वाले लोगों को कभी भी सत्ता में नहीं लाना चाहिए. लेखक की बात को मैं ध्यान में रखकर लोकसभा चुनाव में वोट डालूंगा, यही मेरा प्रण है.

–रजनीश, समस्तीपुर

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

ई-मेल पता : feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

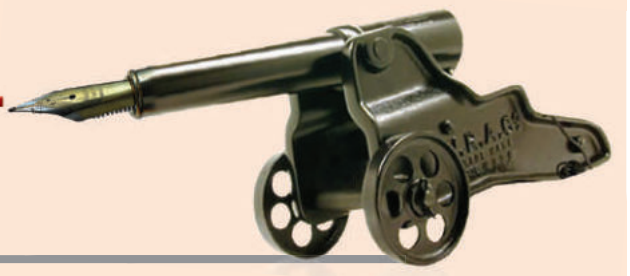

गांधी के सपनों का भारत कहां गया

दो अक्टूबर भी बीत गया. यह दो अक्टूबर हिंदुस्तान के दुख, तकलीफ़, परेशानी और निराशा का दो अक्टूबर है. दो अक्टूबर उस इंसान का जन्मदिन है, जिस इंसान ने न केवल देश को आज़ादी दिलाई, बल्कि आज़ादी के बाद का देश कैसा होगा, इसका सपना भी देखा. महात्मा गांधी संपूर्ण व्यक्तित्व थे, इसलिए उन्होंने एक संपूर्ण सपना देखा. गांधी कैसा समाज चाहते थे, कैसी सरकार चाहते थे, कैसी व्यवस्था चाहते थे, उसका उन्होंने विशुद्ध रूप से वर्णन किया है. गांधी गांवों को अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाना चाहते थे. फ़ैसलों का केंद्र भी वो गांवों को बनाना चाहते थे, लेकिन ये दो अक्टूबर गांधी के सपनों की राख़ के ढेर पर आया हुआ दो अक्टूबर है. आने वाला दो अक्टूबर–2014 हमें फिर से याद दिलाएगा कि हम गांधी के सपनों से कितनी दूर चले गए हैं या दो क़दम भी हम नज़दीक आ पाए हैं.

गांधी के इस देश में गांधी की आलोचना करने वाली एक बड़ी जमात तो है ही, लेकिन ऐसे लोग, जिन्होंने गांधी की विचारधारा का हमेशा विरोध किया, आज वो भी गांधी का नाम लेकर सत्ता में आने की बात कर रहे हैं. उन लोगों ने गांधी को एक प्रदेश का व्यक्ति बना दिया. बापू के गुजरात के नरेंद्र मोदी. शब्द सुनने में अजीब इसलिए लगता है कि आज का गुजरात बापू का गुजरात नहीं है और आज का देश बापू का देश नहीं है. आज गुजरात नरेंद्र मोदी का गुजरात है और नरेंद्र मोदी के गुजरात में प्रचार की भाषा चलती है. आज के गुजरात में गांव को तोड़ने वाली अर्थव्यवस्था चलती है और आज के गुजरात में गांधी के सपनों को खंडित करने वाली विचारधारा चारों तरफ बिखरी दिखाई दे रही है. नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं ज़रूर, लेकिन नरेंद्र मोदी गांधी के कहीं से भी क़रीब नहीं हैं. नरेंद्र मोदी की संपूर्ण विचारधारा, नरेंद्र मोदी की संपूर्ण भाषा और नरेंद्र मोदी का संपूर्ण विचार गांधी के विपरीत खड़ा है.

गांधी के विपरीत खड़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हम गांधी द्वारा देखे गए उस सपने के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं, जहां पर गांवों का कोई अस्तित्व न हो, जहां पर गांव आधारित अर्थव्यवस्था से कोसों दूरी रखी जाए और जहां पर गांधी के सहअस्तित्व, प्यार और भाईचारे के सिद्धांत के ख़िलाफ़ काम किए जाएं, तो वह चीज़ खटकती है. नरेंद्र मोदी का प्रचार अभियान चलाने वाले नरेंद्र मोदी को गांधी का वारिस बताने की योजना बना रहे हैं. उन लोगों का मानना है कि लोग अब गांधी को भूल चुके हैं, गांधी की विचारधारा को भूल चुके हैं, इसलिए गांधी के नाम पर नरेंद्र मोदी वैसे ही चल सकते हैं, जैसे सरदार पटेल के नाम पर चल रहे हैं. नरेंद्र मोदी सरदार पटेल को गुजरात का बता रहे हैं और इस तरह सरदार पटेल के देशव्यापी व्यक्तित्व को बौना कर रहे हैं. सरदार पटेल देश की महान विभूति थे और उन्होंने देश को एक करने में अपनी संपूर्ण समझ और अपनी संपूर्ण कुशलता लगा दी. सरदार पटेल ऐसे व्यक्ति थे, जिन्हें इस देश के लोगों ने संवैधानिक तौर पर प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था. अगर महात्मा गांधी का अतिशय जवाहरलाल नेहरू प्रेम नहीं हुआ होता, तो इस देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल बने होते. उस समय देश में सोलह प्रदेशों में से तेरह प्रदेशों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था और तीन प्रदेशों में से भी सिर्फ़ एक ने जवाहरलाल जी का नाम प्रस्तावित किया था, लेकिन गांधी जी ने सरदार पटेल को यह आदेश दिया था कि आप अपना नाम उम्मीदवारी से हटा लीजिए और सरदार पटेल ने गांधी जी के आदेश का पालन किया. ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी सरदार पटेल को सिर्फ़ गुजरात बना देना, ये करिश्मा नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. आज ये झूठा करिश्मा हम अपनी आंखों से देख रहे हैं. सरदार पटेल की मूर्ति के लिए देश भर से लोहा मंगाने की योजना मूर्खता भरी योजना है. सरदार पटेल की मूर्ति अगर स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से ऊंची बनानी थी, तो बारह साल पहले इसकी योजना बनाई जा सकती थी. सरदार पटेल को भावनात्मक रूप से चुनावी मुद्दा बनाना सरदार पटेल के साथ अन्याय करना है और उनके व्यक्तित्व के साथ खेल करना है.

भाजपा के नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी, दोनों के बारे में बातचीत करनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि इन दोनों का नज़रिया देश को लेकर क्या है. नरेंद्र मोदी ने अभी तक कहीं ये भाषण नहीं दिया कि वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे और अगर भाजपा के सपने के हिसाब से वो प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या करेंगे. न राहुल गांधी ने साफ़ किया है कि वो अगर प्रधानमंत्री बने या उनकी पार्टी सत्ता में आई, तो वो देश के लिए किस तरह की योजनाओं का ख़ाका ज़मीन पर उतारेगी. श्री नरेंद्र मोदी और श्री राहुल गांधी हवा में तलवारें चला रहे हैं और लोगों को उसी तरह उकसाते हैं, जैसे कोई आदमी हवा में गाली देकर दूसरों को उकसाए.

भाजपा के नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के राहुल गांधी, दोनों के बारे में बातचीत करनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि इन दोनों का नज़रिया देश को लेकर क्या है. नरेंद्र मोदी ने अभी तक कहीं ये भाषण नहीं दिया कि वो जब प्रधानमंत्री बनेंगे और अगर भाजपा के सपने के हिसाब से वो प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या करेंगे. न राहुल गांधी ने साफ़ किया है कि वो अगर प्रधानमंत्री बने या उनकी पार्टी सत्ता में आई, तो वो देश के लिए किस तरह की योजनाओं का ख़ाका ज़मीन पर उतारेगी. श्री नरेंद्र मोदी और श्री राहुल गांधी हवा में तलवारें चला रहे हैं और लोगों को उसी तरह उकसाते हैं, जैसे कोई आदमी हवा में गाली देकर दूसरों को उकसाए. हिंदुस्तान को जातियों और संप्रदायों में बांटने का खेल काफ़ी दिनों से चलता रहा है और इस बार भी ये दोनों हिंदुस्तान को बांटने की रणनीति पर चल रहे हैं. अगर दोनों व्यक्ति अपने रस्मी घोषणापत्र से अलग जाएं और जनता को ये बताएं कि उनके दिमाग़ में देश की समस्याओं को सुधारने का कैसा नक़्शा है, तो शायद देश उनके बारे में सही आकलन कर सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर नरेंद्र मोदी और छोटे पैमाने पर राहुल गांधी इस चीज़ से दूर भाग रहे हैं. दोनों सवालों को छूना नहीं चाहते, भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं और यही हमारे लिए सबसे अफ़सोस की बात है. भाजपा के युवा नेता नरेंद्र मोदी हैं और कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी हैं. हालांकि, दोनों की उम्र में बहुत फ़र्क़ है, लेकिन दोनों के सिद्धांतों में बहुत कम फ़र्क़ है और जब हम सिद्धांत की बात करते हैं, तो उसमें हम आर्थिक सिद्धांत जोड़ देते हैं, बेरोजगारी की समस्या का हल जोड़ देते हैं और जोड़ना तो ये भी चाहिए कि हम देश को भविष्य में कैसा बनाना चाहते हैं, पर इन सवालों के जवाब कोई देना नहीं चाहता.

देश में ईमानदार नेताओं की कमी है. ईमानदार मुख्यमंत्रियों की कमी है. देश में ऐसी सरकार चाहिए, जो सरकार ईमानदार भी हो और जो सरकार काम भी कर सके. जनता के प्रति जवाबदेह भी हो. पिछले पंद्रह सालों से ऐसी सरकारें आ रही हैं, जो न जनता के प्रति अपने को जवाबदेह मानती हैं और न समस्याओं के हल की कोई कोशिश करती हैं. उन्होंने देश को बाज़ार के हवाले छोड़ दिया है. ये देश ऐसे नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है, जो बाज़ार के ख़िलाफ़ इंसान को तरजीह दे. ऐसे लोग चाहिए, जो इंसानी समस्याओं को अपनी प्राथमिकता मानें, न कि बाज़ार की समस्याओं को अपनी प्राथमिकता मानें. जो देश को लोगों के सपनों के हिसाब से चलाएं, न कि सेंसेक्स के हिसाब चलाएं. दुर्भाग्य की बात है कि अभी ऐसे लोग सामने आए हैं, जो भारत को स्टॉक मार्केट और सेंसेक्स की नज़र से देखते हैं और वैसी ही नीतियां बनाने में अपनी संपूर्ण कुशलता लगा देते हैं. हिंदुस्तान को आने वाले चुनाव में ऐसे लोगों का और ऐसी पार्टियों का और ऐसी संसद का इंतज़ार है, जो उनकी समस्याओं को हल करने में अपनी प्राथमिकता दिखाए, जिनके लिए वो चुने गए हैं. ये संसद बाज़ार के लोगों के लिए नहीं चुनी जाती, लोगों के लिए चुनी जाती है.■

editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

राहुल ने पार्टी को बदलाव का मौक़ा दिया है

राहुल गांधी ने अचानक या यूं कहें कि बड़े रूखेपन से इस पूरी व्यवस्था को तमाचा मार दिया. सामान्य तौर पर जब वे बोलते हैं, तो उनकी थाह पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे-सीधे बात की और इसे और पुख़्ता करने के लिए उन्होंने अपनी बातचीत को दोहराया भी कि यह अध्यादेश ठीक नहीं, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए.

ब्रिटेन में 1979 के दौर में जो चुनाव हुए, उसके परिणामस्वरूप मिस थ्रेचर का राजनीति में पदार्पण हुआ और लेबर पार्टी अगले 18 वर्षों के राजनीतिक वनवास में चली गई. चुनावों की उस शाम को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिम कैलघन ने कहा कि एक ऐसा समय भी आता है, जब ज्वार अपनी दिशा बदल लेता है और ऐसा कोई भी तरीक़ा नहीं बचता कि आप ऐसा होने से रोक सकें.

कुछ दिनों पहले कांग्रेस नीत यूपीए गठबंधन ने भी ऐसे ही ज्वार का सामना कर रही थी. पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव दूर की कौड़ी होता जा रहा था और यह सरकार एक बूढ़ी सरकार की शक्ल में तब्दील हो रही थी, जिसके मंत्री भी नाकारा होकर जंग खा रहे थे और हम सभी इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द ही इस सरकार का खेल ख़त्म होगा और लोकसभा चुनाव तयशुदा समय से पहले ही हो जाएंगे.

लेकिन अब सब कुछ बदल गया है. कई बार ऐसा होता है कि राजनीति तेज़ी से बदलती है और ऐसी नई संभावनाएं दिखने लगती हैं, जो पहले कहीं दिखाई ही नहीं दे रही थीं. कुछ समय पहले ही अजय माकन अपराधियों को संरक्षण देने अध्यादेश का बचाव करते दिख रहे थे, तब राहुल गांधी आते हैं. मध्यस्थता करते हैं और पूरा खेल उलट जाता है. हम नहीं जानते थे कि वास्तव में कहां खड़े हैं. वह एक अनिच्छुक उत्तराधिकारी हैं, जो कि बेहद संकोची हैं और सत्ता की ताकत उनको सौंप दी गई है. उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य जगहों के चुनाव परिणाम पर गौर करें, तो वे असफल नज़र आते हैं और यही वजह है कि पार्टी में तेज़तर्रार राजनेताओं और बेहतरीन वक्ताओं के बीच से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से पार्टी भी हिचक रही थी.

लेकिन अजय माकन की प्रेस कांफ्रेंस में जिस तरह से राहुल गांधी का पदार्पण हुआ, उसने कांग्रेस के लिए फिर से एक बार संभावनाओं के

द्वार खोल दिए, जो कि जवाहर लाल नेहरू के उस प्रयास के बाद से बंद ही हो गए थे, जब वे कामराज प्लान समर्थन कर कांग्रेस को सुधारना चाह रहे थे. हालांकि यह कांग्रेस का एक पाखंड था, जिसके माध्यम से वे मोरारजी देसाई से छुटकारा पाना चाह रहे थे. तब से लेकर आज तक वास्तव में भारतीय राजनीति पाखंडों के बीच से अपना रास्ता तलाश रही है. जहां कोडवर्ड और इशारों में बात की जाती है, ताकि शर्मसार कर देने वाली सच्चाइयों को छिपाया जा सके. यह अध्यादेश भी उसी कैटिगरी में आता है. राजनीति में अपराधी ख़ुद को क़ानून के लंबे हाथों से बचाने का रास्ता तलाश लेते हैं. घृणित राजनीतिक गतिविधियों को सभी पार्टी ने संरक्षण दिया और राहुल गांधी का कोजी क्लब भी अपने अपराधी सदस्यों का बचाव कर रहा था.

राहुल गांधी ने अचानक या यूं कहें कि बड़े रूखेपन से इस पूरी व्यवस्था को तमाचा मार दिया. सामान्यतौर पर जब वे बोलते हैं, तो उनकी थाह पाना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार उन्होंने सीधे-सीधे बात की और इसे और पुख़्ता करने के लिए अपनी बातचीत को दोहराया भी. यह सही है कि अध्यादेश ठीक नहीं, इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए. भ्रष्ट राजनीति अब अपने आख़िरी छोर पर पहुंच चुकी है और यह इस अध्यादेश को न लागू करने का पर्याप्त कारण है. इसके बाद की कहानी अजय माकन के चौंकाने वाले चेहरे ने पूरी कर दी.

शेख़सपियर के नाटक किंग हेनरी चतुर्थ के दूसरे दृश्य में ऐसा ही एक क्षण आता है, जब उद्दंड और झगड़ालू राजकुमार प्रिंस हाल ने अपने राजा फालस्टाफ से कहा कि हे वृद्ध पुरुष, आज के बाद मैं आपको नहीं जानता. राजा निराश हो गए. बेशक जब राहुल गांधी यहां पर अध्यादेश को बकवास बता रहे थे, तो भारतीय परिदृश्यों में वह ओल्डमैन वॉशिंगटन में अपने विश्वसनीय दोस्त ओबामा के पास शेखी बघार रहे थे. वे अपनी क़द को जी–20 के ज़रिये बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे थे, जबकि इधर उनके पैरों तले की ज़मीन खिसक रही थी. कांग्रेस के उपाध्यक्ष को सामने रखकर देखा जाए, तो उनकी प्रतिक्रिया का तरीक़ा ग़लत था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोई इसको लेकर शिकायत कैसे कर सकता है, जबकि मसला राजनीति से भ्रष्टाचार मिटाने के पक्ष का हो.

अब कांग्रेस के पास यह मौक़ा है कि राहुल गांधी द्वारा पैदा किए गए इस अवसर को अपने हक़ में कर ले और राजनीति को अपराध से मुक्त कराए. सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है. हो सकता है कि प्रधानमंत्री के लिए यह असहज स्थिति होगी, लेकिन चूंकि वे पहले ही यह स्वीकार चुके हैं कि राहुल गांधी को अब नेतृत्व सौंपा जाना चाहिए, इसलिए यह राहुल के लिए ज़मीन तैयार करने का सबसे सही मौक़ा है. अगली पीढ़ी के लिए यह बेहतर संदेश होगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए ख़ुद के लिए बदलाव का रास्ता तैयार करेगी या अपने बूढ़े-थके नेताओं के साथ उसी पुराने ढर्रे पर चलेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

जानें अपना अधिकार

आवेदन का प्रारूप

कार्यों का निरीक्षण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन

महोदय,
कृपया मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी दी जाए:

1. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–2(जे)(1) के अनुसार प्रत्येक नागरिक को किसी भी सरकारी कार्य का निरीक्षण करने का अधिकार है. इसके तहत मैं निम्नलिखित कार्य का निरीक्षण करना चाहता हूं. कृपया मुझे तिथि, समय एवं स्थान बताएं, जबकि मैं आकर इस कार्य की जांच कर सकूं. (कार्य का विवरण)

2. मैं निरीक्षण के दौरान इस कार्य से संबंधित दस्तावेजों का भी निरीक्षण करना चाहूंगा, इसलिए निरीक्षण के समय निम्नलिखित दस्तावेज मुझे उपलब्ध कराएं:

क. मेज़रमेंट बुक
ख. खर्चों का विवरण
ग. रेखाचित्र

इन दस्तावेजों के निरीक्षण के बाद यदि मुझे किसी दस्तावेज की प्रति की आवश्यकता होगी तो कानून के तहत निर्धारित शुल्क लेकर प्रतियां उपलब्ध कराएं.

3. धारा–2(जे)(3) के अनुसार, प्रत्येक नागरिक को सरकारी कार्यों में प्रयोग की गई सामग्री का प्रमाणित नमूना लेने का अधिकार है. इसके तहत मैं उपरोक्त कार्य में प्रयोग की गई सामग्री का विभाग द्वारा प्रमाणित नमूना लेना चाहता हूं. नमूना मेरी उपस्थिति में विभाग द्वारा एकत्र किया जाए और सीलबंद हो तथा विभाग द्वारा यह प्रमाणित किया जाए कि सीलबंद नमूना कार्य की सामग्री का असली नमूना है. कृपया मुझे स्थान, समय एवं तिथि सूचित करें, जबकि मैं प्रमाणित नमूने के लिए आ सकूं.

मैं आवेदन शुल्क के रूप में.....रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बीपीएल कार्डधारक हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बीपीएल कार्ड नंबर.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित न हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों की समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम और पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम.....
पता.....
फोन नंबर.....

संलग्नक.....
(यदि कुछ हो तो)

चौथी दुनिया ब्यूरो

कई बार आपको मांगी गई सूचना के बदले गैर जरूरी सूचना थमा दी जाती है या फिर आपके मोहल्ले या शहर की सड़क बनने के एक महीने के भीतर ही टूट जाती है. फिर सालों तक उसकी मरम्मत नहीं होती. आखिर सरकार ने तो पूरा पैसा दिया था, तब इतनी घटिया सड़क क्यों बनी? सड़कें निर्धारित मापदंड के अनुसार क्यों नहीं बनीं? सड़कों की चौड़ाई निर्धारित सीमा से कम क्यों हो जाती है? मस्टर रोल में भी फर्जी इंट्री की शिकायतें आम हैं. सड़क बनाने के काम पर अक्षम और गांव में न रहने वाले लोगों की इंट्री भी मस्टर रोल में दिखा दी जाती है. आखिर इस सबका उपाय क्या है? सूचना कानून में ऐसी समस्याओं का समाधान है. इसके तहत कई प्रकार के निरीक्षण की व्यवस्था है. निरीक्षण का मतलब है कि आप किसी भी सरकारी विभाग की फाइलों या किसी भी विभाग द्वारा कराए गए कामों का निरीक्षण कर सकते हैं. उदाहरण के लिए आपके क्षेत्र में यदि कोई सड़क बनाई गई है और आप सड़क निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री या सड़क की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं तो आप निरीक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं. आप सरकारी फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं. कई बार जब आप किसी सरकारी विभाग से सूचना मांगते हैं तो आपसे कहा जाता है कि अमुक सूचना हजार पृष्ठों की है और इसके लिए आपको एक खास शुल्क अदा करनी होगी. कुछ मामलों में तो आवेदक से लाखों रुपये तक की मांग की गई है. जाहिर है, एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक होने के नाते आप यह जरूर जानना चाहते होंगे कि इन स्थितियों का मुकाबला कैसे किया जाए? आरटीआई एक्ट की धारा 2(जे)(1) के तहत आप किसी भी सरकारी काम या फाइल के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं. इस अंक में हम इसी से संबंधित एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी समस्या के समाधान या सुझाव के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिए संपर्क कर सकते हैं.■

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं या पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301 ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

राशिफल

आचार्य चंद्रशेखर

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
इस सप्ताह आप बीमारी से बचे रहेंगे और स्फूर्ति से सराबोर रहेंगे. इस सप्ताह बिना उम्मीद का धन प्राप्त होगा. विवादित मामलों से बचकर चलें, अन्यथा किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाएंगे. बच्चों का सहयोग प्राप्त रहेगा. अपने आप पर भरोसा कर कार्य करेंगे और आपके विश्वास का स्तर भी बढ़ेगा. संपत्ति की खरीद-बिक्री भी संभव है. परिवारजनों के साथ आपका और सदस्यों का बर्ताव अच्छा रहेगा.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
इस सप्ताह व्यवसायी बहुत खुश रहेंगे और विस्तार योजना को कार्यरूप देंगे. पैतृक संपत्ति का भी विवाद सुलझेगा. स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा. पारिवारिक सुख भी प्राप्त होगा. किसी यात्रा की सम्भावना बनेगी. किसी राजनीति के शिकार न हों. प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थी अच्छा समाचार प्राप्त करेंगे. किसी को क़र्ज़ देने से बचें. इस सप्ताह वाहन को तेजी से न चलाएं. पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहेगा और आप खुश रहेंगे.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह कोई अनसुलझी समस्या सुलझेगी और आप स्फूर्तिवान रहेंगे. आर्थिक मामलों में भी आप बहुत अच्छा करेंगे. आपके कार्यक्षेत्र का भी विस्तार होगा. संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, इसलिए निराश न हों. व्यवसायी काफी खुश रहेंगे और उन्नति करेंगे. नौकरीपेशा सावधानी से खर्च करें.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
इस सप्ताह आप ज्यादा खुश रहेंगे और उत्साह बढ़ा रहेगा. आपका रुझान आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों पर ज्यादा रहेगा. आप इस वक़्त समझौतावादी रहेंगे. व्यापारियों की व्यापर को लेकर बहुत पैनी नजर रहेगी. नौकरीपेशा उन्नति की राह पर रहेंगे. परिवार और समाज के लोग आपको बहुत स्नेह देंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
इस सप्ताह आप अपने चिड़चिड़े स्वभाव से बचें. आप अपने मूड में बहुत उतार-चढ़ाव देखेंगे. आपके खर्चे बढ़ने की सम्भावना है. इस सप्ताह आपके लिए परिवार का महत्व बहुत ज्यादा रहेगा. भाग-दौड़ के बावजूद आप अपने पारिवारिक प्रबंधन को बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. कानूनी मामलों से बचें.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
इस सप्ताह किसी नाउम्मीद जगह से आपको अच्छी खबर मिलेगी. निवेश सोच-समझ कर करें. सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी. आप धार्मिक कार्यों में भी रुचि लेंगे और किसी जरूरतमंद को मदद करेंगे. व्यापारी वर्ग काफी खुश रहेंगे और आर्थिक रूप से बहुत अच्छा करेंगे. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
इस सप्ताह आप विनम्र होकर चलें. किसी से खफा होकर कोई कार्य न करें. अपने गुस्से को नियंत्रण में रखें. नौकरीपेशा और व्यापारी, दोनों वर्ग काफी अच्छा करेंगे. व्यापारी नये कार्य की तलाश करेंगे और सफल रहेंगे. निवेश की सम्भावना है और आप उससे काफी प्रसन्न रहेंगे. आपके नये-नये मित्र बनेंगे, जो आनेवाले दिनों में आपके लिए मददगार साबित होंगे.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
इस सप्ताह आप आय के श्रोतों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और सफल भी होंगे. इस सप्ताह आपकी खर्च के बढ़ने की संभावना है. व्यावसायियों को फायदे के संकेत हैं. संतान सुख सर्वोतम रहेगा. आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे. नौकरीपेशा वालों के लिए थोड़ी चिंता का समय है, लेकिन व्यापारी अच्छा करेंगे.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
इस सप्ताह आप कोई नई योजना पर कार्य करेंगे और अपने प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपने परिवार और कार्य स्थल में सामंजस्य बना कर चलें. दांपत्य जीवन अच्छा रहेगा. वाहन को थोड़ा धीरे चलाएं. व्यापारी अच्छा प्रदर्शन करेंगे. अपनी व्यस्तता की वजह से परिवार पर कम ध्यान न रखें.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
इस सप्ताह कोई खरीद-बिक्री की योजना बनेगी और आप उसमें व्यस्त रहेंगे. आपके साथ कार्य करने वाले लोगों का सहयोग प्राप्त रहेगा. किसी कानूनी पेचीदगी से बचें. नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छा वक़्त रहेगा. संदेह करने वाले लोगों से बचें. आपसी संबंधों में थोड़ा तनाव अनुभव करेंगे. स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
इस सप्ताह अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखें.किसी संपत्ति के खरीद में कोई जल्दबाजी न करें सोच समझ कर निर्णय लें.थोड़ी भाग दौर करनी पड़ेगी आलस्य न करें .नौकरीपेशा लोग अपनी एकाग्रता और संयम बना कर चलें अन्यथा नुकसान होगा.व्यापारियों को थोड़ी और मेहनत की जरूरत है

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
इस सप्ताह खर्च बढ़ने की सम्भावना है, लेकिन चिंता न करें धन भी आएगा. परिवार के अन्दर आपसी विवाद को न उभरने दें. धन के सदुपयोग पर ध्यान दें और बचत करें. मित्रों या भाइयों से आपसी बात को लेकर विवाद न उभरने दें. आर्थिक रूप से मिलाजुला असर रहेगा. स्वास्थ्य ठीकठाक रहेगा. क्रोध से बचें.

ज़रा हट के

हील वाली जूती पहन कर चले पुरुष

आज तक आपने यही सुना होगा कि अमुक महिला की ऊंची हील वाली जूती बहुत शानदार है या उसकी जूती की हील कुछ ज्यादा ही ऊंची है. अब आपको अगर यह पता चले कि कोई पुरुष महिलाओं की ऊंची हील वाली जूती पहन कर चल रहा है तो आपको दांतों तले उंगली दबानी तो पड़ेगी ही. कुछ ऐसा ही हुआ टोरंटो में. जब वहां वाक ए मील इन हर शूज जुलूस में महिलाओं की ऊंची हील वाली जूतियां पहन कर सैकड़ों पुरुषों ने लोगों को महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूक किया. समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक, यह कार्यक्रम इस विचार पर आधारित था कि आप किसी व्यक्ति का अनुभव तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप उसके जूतों में एक मील न चल लें. यह जुलूस महिलाओं और लड़कियों के प्रति हिंसा खत्म करने के प्रति जागरूकता लाने और इस समस्या के निवारण अभियान के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए किया गया था. टोरंटो में यह कार्यक्रम पांचवीं बार आयोजित हुआ है. इस जुलूस में लोग तीन इंच ऊंची एड़ी की जूतियां पहनकर एक मील तक चले. आयोजकों का कहना है कि यह सिर्फ स्टंट नहीं है. व्हाइट रिबन अभियान, अब एक वैश्विक संगठन है, इसका लक्ष्य महिलाओं के प्रति हिंसा को खत्म करना है. संगठन के सहायक निदेशक टोड माइनरसन ने कहा कि जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान में अधिक से अधिक पुरुषों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

18 लाख डॉलर की पेंटिंग

पिकासो के चित्रकारी की दुनिया दीवानी है. यही कारण है कि उनकी चित्रकारी करोड़ों रुपये में बिकती है. एक बार फिर पिकासो ने अपनी पेंटिंग का लोहा पूरी दुनिया को मानने के लिए बाध्य कर दिया है. स्पेन के मशहूर चित्रकार पाब्लो पिकासो की पेंटिंग चीन में एक नीलामी में 18 लाख डॉलर में बिकी. वस्तुओं की नीलामी आयोजित करने वाली संस्था क्रिस्टी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि होम्मे एसिस शीर्षक वाली इस तैल चित्र पर 21 अप्रैल, 1969 की तारीख अंकित है. यह कलाकृति अपनी अनुमानित मूल्य से दोगुनी कीमत पर बिकी.

क्रिस्टी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीवन मर्फी ने एक बयान में कहा कि हमारे द्वारा आयोजित नीलामी और कार्यक्रम को खरीददारों की अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली.■

ख़ास है यह तलवार

मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू करोड़ों में बिके तो बात समझ में आती है, मकान करोड़ों का हो तो कोई अचरज नहीं होगा, लेकिन जब तलवार की कीमत करोड़ों में हो तो है न ताज्जुब की बात. जी हां, एक तलवार यहां करोड़ों रुपयों में नहीं, बल्कि इतिहास की गवाह बनी शाही तलवार की कीमत नीलामी में चार करोड़ डॉलर लग चुकी है, लेकिन इसके मालिक ने फिलहाल इसे बेचने का मन नहीं बनाया है. राजस्थान के सरहदी इलाके बाड़मेर जिले के लुणु गांव के सांग सिंह के पास मौजूद सुलेमानी शाही तलवार पर सोने की क़लम से उर्दू में इशरत अली इब्ने मेरे मोहम्मद फकीराबाद अंकित है.

सांग सिंह बताते है कि करीब 500 वर्ष पुरानी इस एतिहासिक तलवार की नीलामी में इसकी कीमत चार करोड़ डॉलर लग चुकी है. वह बताते हैं कि यह तलवार आम नहीं खास है. लंबे समय तक यह शाही तलवार फकीराबाद एवं हैदराबाद सिंध के दरबार में रही. सिंध प्रांत निवासी सिद्दीकी के वंशजों को मुगलों ने यह तलवार भेंट की थी. ■

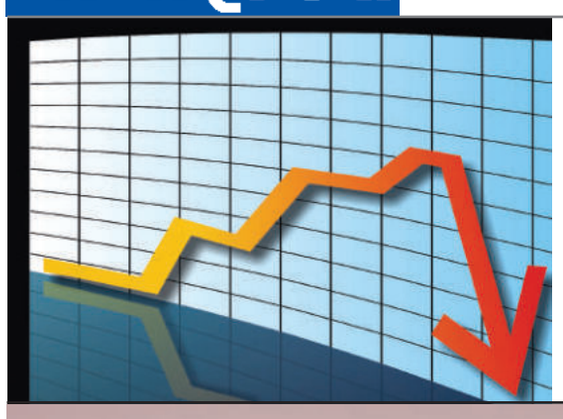

अमेरिका में आईटी कंपनियों और उनके प्रोफेश्नल्स की बहुत संख्या भारत के सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु से है, जो वहां की केन्द्र सरकार के साथ काम करती हैं. कंपनियों को चिंता इस बात से है कि अगर अमेरिका में आर्थिक संकट के बादल छाए रहे, तो उनका भुगतान कुछ समय के लिए लटक सकता है. और अगर ऐसा हुआ, तो कंपनियां बंद होने के कगार पर आ जाएंगी.

अमेरिका में शटडाउन

दिवालिया हुआ दबंग!

अमेरिका क़र्ज़ लो और घी पियो की चार्वाक नीति के सिद्धांतों पर जीने में विश्वास करता है. यही कारण है कि इस देश में 1977 से लेकर अब तक 17 बार शटडाउन हो चुका है. कल तक दूसरों को नौकरियां बांटनेवाले इस देश के नागरिकों के सामने ख़ुद नौकरियों के लाले पड़ गए हैं. अमेरिका में सबकुछ जल्द ही पटरी पर नहीं आया तो इसकी चपेट में वैश्विक अर्थव्यवस्था को आने से कोई नहीं रोक सकता.

राजीव रंजन

सत्तारूढ़ डेमोक्रेट और विपक्षी रिपब्लिकन ओबामाकेयर के नाम से प्रचलित हेल्थ केयर कार्यक्रम को लेकर आमने-सामने हैं और दोनों ही अपनी ज़िद पर अड़े हुए हैं, जिससे क़रीब 17 साल बाद अमेरिका में शटडाउन का संकट पैदा हुआ है. यह शटडाउन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भूचाल ला सकता है, जिसके कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है. डेमोक्रेट की ज़िद है कि वह ओबामाकेयर कार्यक्रम को किसी क़ीमत पर नहीं छोड़ेगा, वहीं रिपब्लिकन का कहना है कि ओबामा को यह कार्यक्रम छोड़ना होगा, तभी बजट पास होगा. विपक्षी रिपब्लिकन का मानना है कि इस हेल्थ कार्यक्रम से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगी.

एक बड़ा सवाल यह है कि हो सकता है कि आनेवाले कुछ दिनों में अमेरिका किसी सर्वमान्य हल पर पहुंच जाए. ये भी हो सकता है कि सेंट्रल बैंक मनी मार्केट को सहारा दे दें, फिर भी पहले ही क़र्ज़ संकट में घिरे यूरोजोन के देशों पर इस शटडाउन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा. ब्रिटेन की हालत और अधिक पतली हो सकती है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था फाइनेंस सेक्टर पर काफ़ी हद तक आधारित है. दक्षिण एशिया सहित पूरे विश्व में इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे, यह तय है. अगर अमेरिका डिफॉल्टर हो जाता है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स समेत दूसरी एजेंसियां उसकी रेटिंग घटा देंगी. देखा जाए तो इन परिस्थितियों में अमेरिका की साख़ लौटने में काफ़ी समय लग सकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित होगा.

अगर डिफॉल्टर हो जाएगा अमेरिका...

ध्यान देने की बात यह है कि अमेरिकी सरकार की क़र्ज़ सीमा 17 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगी. इस समय अमेरिका के क़र्ज़ की सीमा 16,700 अरब डॉलर है. 1977 से लेकर अब तक अमेरिका में 17 बार शटडाउन (कामबंदी) हो चुका है. 16 दिसंबर, 1995 से 5 जनवरी, 1996 तक सबसे लंबा शटडाउन तक चला था. जब तक क़र्ज़ सीमा के विस्तार को इजाज़त नहीं मिलती, ख़र्चों के लिए ज़रूरी 30 अरब डॉलर (करीब 1800 अरब रुपये) की ज़रूरत होगी. क़र्ज़ लेने की सीमा 1600 अरब डॉलर है. अगर बजट पर सहमति नहीं बनती है तो अमेरिका और कर्ज नहीं ले सकेगा और डिफॉल्टर हो जाएगा. इस कामबंदी के कारण अमेरिकी अर्थव्यवस्था को एक हफ्ते में लगभग एक अरब डॉलर (62.46 अरब रुपये) का नुकसान होगा. सरकारी एजेंसियां चाहकर भी इस शटडाउन की अनदेखी नहीं कर सकतीं. संघीय क़ानून के मुताबिक, बिना बजट कानून पास किए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल अपराध की श्रेणी में आ सकता है.

एंटीडेफिशिएंसी एक्ट

संघीय एजेंसियों और कार्यक्रमों के लिए पैसे की कमी होने पर एंटीडेफिशिएंसी एक्ट के मुताबिक, संघीय एजेंसियों को अपना कामकाज रोकना पड़ता है. प्रशासन, बजट न होने के कारण कर्मचारियों की छुट्टी कर देता है. इस दौरान उन्हें वेतन भी नहीं दिया जाता है. यही कारण है कि अमेरिका ने अपने 8 लाख सरकारी कर्मचारियों को बिना वेतन के हटा दिया है.

भारत पर असर

अमेरिका में बजट को लेकर जारी राजनीतिक गतिरोध के कारण वहां आंशिक काम बंदी शुरू हो गई है. अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक बार फिर गोता लगाने लगी है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुगबुगाहट शुरू हो गई है. जानते हैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था की यह संकट भारत को किस रूप में प्रभावित कर सकता है.

अमेरिका में आईटी कंपनियों और उनके प्रोफेश्नल्स की बहुत संख्या भारत के सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु से है, जो वहां की केन्द्र सरकार के साथ काम करती हैं. कंपनियों को चिंता इस बात से है कि अगर अमेरिका में आर्थिक संकट के बादल छाए रहे, तो उनका भुगतान कुछ समय के लिए लटक सकता है. और अगर ऐसा हुआ, तो कंपनियां बंद होने के कगार पर आ जाएंगी. अमेरिकी प्रशासन के एक बड़े तबके के छुट्टी पर होने की वजह से वीजा देने की प्रक्रिया के ठप्प होने का खतरा है. इसका खामियाजा आईटी कंपनियों को उठाना पड़ सकता है. हालांकि आईटी कंपनियों के शीर्ष संगठन नैस्कॉम का कहना है कि अमेरिका की बंदी भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात को बहुत प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि आईटी कंपनियों का ज्यादातर कारोबार निजी क्षेत्र से आता है, लेकिन ऐसा कैसे संभव होगा कि सरकारी क्षेत्र ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित हो और निजी क्षेत्र इस प्रभाव से अछूता रह जाए. यह तय है कि अगर बंदी ज्यादा दिनों तक रही, तो इसका असर पूरी अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर होगा.

अमेरिका में लगभग 7 से 8 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन दिए हटा दिया गया है. कर्मचारियों के पास पैसा नहीं होना उनकी मांग को सीधे तौर पर प्रभावित करेगा, क्योंकि जब उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वे खरीदेंगे कैसे. मांग पर पड़ने वाला यह प्रभाव सीधे तौर पर वस्तुओं की पूर्ति और उत्पादन को प्रभावित करेगा. ये ऐसे लिंक्स हैं, जिसका सीधा असर भारत से निर्यात होने वाले उत्पादों पर होगा.

अमेरिकी फेडरल रिजर्व के पैकेज वापसी के फलस्वरूप भारतीय रुपये की जो स्थिति हुई है, वह किसी से छिपा नहीं है. हालांकि रुपये की स्थिति अब धीरे-धीरे सुधर रही है, लेकिन अमेरिकी संकट एक बार फिर रुपये पर दबाव बना सकती है, यह तय है. रुपये की स्थिति अगर फिर से खराब हुई तो निवेशक पूंजी निवेश करने से बचेंगे, क्योंकि उन्हें पैसे की उचित वापसी नहीं मिल पाएगी.

अमेरिकी डेट प्रतिभूतियों में जो निवेश रिजर्व बैंक ने किया है, उस पर मिलने वाले ब्याज और भुगतान में देरी हो सकती है. पूंजी फंसे होने के कारण रिजर्व बैंक को पूंजी निर्माण के लिए दूसरे मदों पर निर्भर रहना पड़ेगा और उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था में सुस्ती के रूप में दिख सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था की स्थिति डांवाडोल हो सकती है.

अमेरिकी सरकार ने बजट पास नहीं होने के कारण सरकारी कार्यालयों पर तालाबंदी लगा दी है, क्योंकि खर्च करने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं थे और सरकार की कर्ज लेने की सीमा भी समाप्त हो चुकी है. इस वजह से अमेरिकी प्रशासन का एक बड़ा तबका छुट्टी पर चला गया है, जिसकी वजह से वीजा देने की प्रक्रिया के ठप्प होने का खतरा बढ़ गया है. इन कार्यालयों के बंद होने के कारण भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी छुट्टी पर जा सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो नये वीजा मिलने और दूतावास संबंधी कामों पर असर पड़ना तय है.

हालांकि अमेरिका में तालाबंदी के बावजूद एक अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार मसलन, मुंबई और घरेलू शेयर बाजार मजबूती पर बंद हुए, लेकिन इस भ्रम को दूर करने में ही भलाई है कि आगे भी शेयर बाजार मजबूती से छलांग लगाते रहेंगे. जानकारों का मानना है कि अमेरिकी संकट का भारत के शेयर बाजार पर असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन यह तय है कि अगर यह संकट कुछ माह तक ऐसे ही चलता रहा, तो भारतीय शेयर बाजार की हालत खस्ता हो सकती है. मतलब, जब तक अमेरिकी बजट को लेकर अनिश्चितता के बादल नहीं छंटते, तब तक भारतीय शेयर बाजार में भी उथल-पुथल बनी रहेगी.

अगर यह संकट ज्यादा दिनों तक खिंचा तो घरेलू अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित होगी और उसको जल्दी से पटरी पर लाने की कोशिशों को धक्का लग सकता है. इस संकट का सबसे ज्यादा असर सेवा क्षेत्र के निर्यात पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है. हालांकि, परोक्ष तौर पर सर्राफा बाजार भी प्रभावित हो सकता है.

आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम का कहना है कि अमेरिकी संकट का फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा. हालांकि अरविंद की बात कितनी सही साबित होगी, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब रुपये का मूल्य गिर रहा था, तो केंद्रीय वित्त मंत्री, आरबीआई के गवर्नर और यहां तक कि प्रधानमंत्री भी यह दावा कर रहे थे कि सबकुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा. बावजूद इसके, रुपये का मूल्य गिरता जा रहा था. निवेशक पूंजी निवेश से बच रहे थे. गोल्ड की कीमत भागती जा रही थी. शेयर बाजार की हालत पतली हो गई थी. देश में कारें और अन्य लग्जरी वस्तुएं महंगी होती जा रही थीं, जिसका प्रभाव अभी भी देखने को मिल रहा है. इन सब स्थितियों को देखें तो आने वाले दिनों में मन में अर्थव्यवस्था की छवि कुछ और ही उभर कर सामने आती है. उद्योग चैंबर एसोचैम के अध्यक्ष राणा कपूर मायाराम की बातों से सहमत नहीं है. कपूर का कहना है कि अमेरिका के बजट संकट की वजह से वहां के पोर्ट और हवाई अड्डों पर कामकाज प्रभावित होना तय है. इसका खामियाजा भारत के निर्यातकों को उठाना पड़ सकता है.

यह तय है कि इस संकट के कारण भारत में चालू खाता घाटा के आंकड़े किसी कीमत पर अनुमान से कम नहीं रहने वाले. इतना ही नहीं, विनिर्माण प्रभावित होना तय है और अगर विनिर्माण प्रभावित हुआ तो बाजार का औंधे मुंह गिरना तय है. मुद्रा बाजार में रुपये की कीमत पर भी दबाव बन सकता है. इस संकट के कारण कंज्यूमर और कैपिटल गुड्स, रियलिटी, बैंक भी जबरदस्त प्रभावित होंगे. ऑटो उद्योग भी इस संकट के कारण काफी हद तक प्रभावित होगा. अभी हाल ही में रुपये का मूल्य गिरते रहने के कारण प्रमुख ऑटोमोबाइल्स कंपनियों ने अपनी कीमतें 3 से 20 हजार तक बढ़ा दीं थीं. अब इस संकट के बाद कंपनियां कितनी कीमत बढ़ाती हैं, यह जल्द ही पता चल जाएगा. तेल एवं गैस, पावर, धातु और पीएसयू वर्ग के शेयरों में निराशा का माहौल देखने को मिल सकता है. ■

feedback@chauthiduniya.com

शटडाउन का होगा असर

रक्षा विभाग : 4,00,000 कर्मियों पर
वाणिज्य विभाग : 40,200 कर्मियों पर
परिवहन : 18,500 कर्मियों पर
ऊर्जा विभाग : 12,700 कर्मियों पर

ये हैं बंद

स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन से जुड़े 19 म्यूजियम, गैलरी और नेशनल जू, नेशनल पार्क, सटैच्यू ऑफ लिबर्टी.

सेवाएं बेअसर

एयर ट्रैफिक कंट्रोल, राष्ट्रीय सुरक्षा परमाणु हथियार व ऊर्जा

शटडाउन के प्रभाव

- 8 लाख कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजा गया. इन कर्मचारियों को इस अवधि का वेतन बाद में भी नहीं मिलेगा.
- नेशनल पार्क, म्यूजियम बंद रहेंगे.
- बच्चों और महिलाओं के पोषण से जुड़े कार्यक्रम भी खतरे में. डिपार्टमेंट ऑफ लेबर भी होगा प्रभावित होगा.
- पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी सभी एजेंसियों के कार्य रोक दिए गए.
- डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसीज की मॉनिटरिंग कुछ दिनों के लिए रोकी गई.
- शटडाउन से वित्तीय घाटा और ज़्यादा बढ़ जाएगा.
- फूड सेफ्टी इंस्पेक्शन बंद हुए.
- स्टॉक मार्केट में आपातकाल जैसी स्थिति रहेगी.
- अमेरिकी अदलतों पर भी इसका असर पड़ेगा.

साई

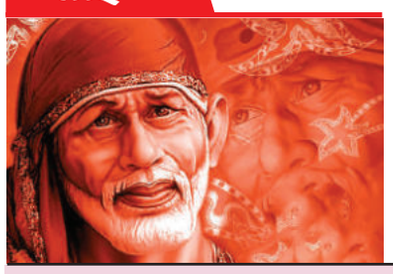

> आधुनिक चिकित्साशास्त्र के वैज्ञानिक चमत्कार से मुझे फिर जीने का मौका तो मिला था, लेकिन रोग मुक्ति नहीं मिली थी. डायबिटीज के मरीजों की एंजियोप्लास्टी हुई, यानी मेरे जैसे तो पांच वर्षों के भीतर उनमें से 35 प्रतिशत मर जाते हैं. ऐसा विज्ञान बता रहा था. गोलियां खाते रहो और 35 फीसद मरने की राह देखते रहो.

डॉ. अभय बंग

बाबा के वचनों में श्रद्धा रखें

चौथी दुनिया ब्यूरो

बाबा ने सच्चरित्र लिखने की अनुमति देते हुए कहा कि सच्चरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमति है. तुम अपना मन स्थिर करके मेरे वचनों में श्रद्धा रखो और निर्भय होकर कर्तव्य पालन करते रहो. यदि मेरी लीलाएं लिखी गईं तो अविद्या का नाश होगा और ध्यान एवं भक्तिपूर्वक श्रवण करने से भक्ति और प्रेम की तीव्र लहर प्रवाहित होगी. जो इन लीलाओं की अधिक गहराई तक खोज करेगा, उसे ज्ञानरूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति हो जाएगी. इन वचनों को सुनकर हेमाडपंत को अति हर्ष हुआ और वह निर्भय हो गए. उन्हें दृढ़ विश्वास हो गया कि अब कार्य अवश्य ही सफल होगा.

विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी. यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और ध्यान करता है, उसे मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं. जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं–लीलाओं का प्रेमपूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञानरूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं. मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं. मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति मिल जाएगी. बाबा ने शामा की ओर देखते हुए कहा, जो प्रेमपूर्वक मेरा नाम स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, उसकी भक्ति में वृद्धि होगी. जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रद्धापूर्वक गायन करेगा, उसकी मैं हर प्रकार से सदैव सहायता करूंगा. जो भक्तगण हृदय और प्राणों से मुझे चाहते हैं, उन्हें मेरी कथाएं श्रवण कर स्वभावत: प्रसन्नता होगी. विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लीलाओं का कीर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी. यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, जो श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन, निरंतर स्मरण और ध्यान करता है, उसे मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं. जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं–लीलाओं का प्रेमपूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञानरूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं. मैं उन्हें मृत्यु के मुख से बचा लेता हूं. मेरी कथाएं श्रवण करने से मुक्ति मिल जाएगी. अत: मेरी कथाओं को श्रद्धापूर्वक सुनो, मनन करो. सुख और संतोष प्राप्ति का सरल मार्ग ही यही है. केवल साई–साई के उच्चारण मात्र से ही उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे.

कृपा से कार्य संपूर्ण

भगवान अपने किसी भक्त को मंदिर–मठ, किसी को नदी के किनारे घाट बनवाने, किसी को तीर्थ भ्रमण और किसी को भगवत कीर्तन एवं भिन्न–भिन्न कार्य करने की प्रेरणा देते हैं, परंतु उन्होंने मुझे साई सच्चरित्र लेखन की प्रेरणा दी. किसी भी विधा का पूर्ण ज्ञान न होने के कारण मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य था. अत: मुझे इस दुष्कर कार्य का दुस्साहस क्यों करना चाहिए. श्री साई महाराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की सामर्थ्य भला किस में है. उनकी कृपा मात्र से ही कार्य संपूर्ण होना संभव है. इसीलिए जब मैंने लेखन प्रारंभ किया तो बाबा ने मेरा अहं नष्ट कर दिया और उन्होंने स्वयं अपना चरित्र रचा. अत: इस चरित्र का श्रेय उन्हीं को है, मुझे नहीं. जन्मत: ब्राह्मण होते हुए भी मैं दिव्य चक्षु विहीन था, अत: साई सच्चरित्र लिखने में सर्वथा अयोग्य था, परंतु श्री हरिकृपा से क्या संभव नहीं है. मूक भी वाचाल हो जाता है और पंगु भी गिरिवर चढ़ जाता है. अपनी इच्छानुसार कार्य पूर्ण करने की युक्ति वह ही जानें. हारमोनियम और बंसी को यह आभास कहां कि ध्वनि कैसे प्रसारित हो रही है. इसका ज्ञान तो वादक को ही है. चंद्रकांत मणि की उत्पत्ति और ज्वार–भाटे का रहस्य मणि अथवा उदधि नहीं, वरन शशिकलाओं के घटने–बढ़ने में ही निहित है.

अमृत से भी मधुर चरित्र

समुद्र में अनेक स्थानों पर ज्योति स्तंभ इसलिए बनाए जाते हैं, जिससे नाविक चट्टानों और दुर्घटनाओं से बच जाएं और जहाज़ को कोई हानि न पहुंचे. इस भवसागर में श्री साई बाबा का चरित्र ठीक उसी भांति उपयोगी है. वह अमृत से भी अति मधुर और सांसारिक पथ को सुगम बनाने वाला है. जब वह कानों द्वारा हृदय में प्रवेश करता है, तब दैहिक बुद्धि नष्ट हो जाती है और हृदय में एकत्रित करने से समस्त कुशंकाएं अदृश्य हो जाती हैं. अहंकार का विनाश हो जाता है और बौद्धिक आवरण लुप्त होकर ज्ञान प्रगट हो जाता है. बाबा की विशुद्ध कीर्ति का वर्णन निष्ठापूर्वक श्रवण करने से भक्तों के पाप नष्ट होंगे. अत: यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है. सतयुग में शम एवं दम, त्रेता में त्याग, द्वापर में पूजन और कलियुग में भगवत कीर्तन ही मोक्ष का साधन है. यह अंतिम साधन चारों वर्णों के लोगों को साध्य भी है. अन्य साधन योग, त्याग, ध्यान–धारणा आदि आचरण करने में कठिन हैं, परंतु चरित्र तथा हरि कीर्तन के श्रवण से इंद्रियों की स्वाभाविक विषयासक्ति नष्ट हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर हो जाता है. इसी फल को प्रदान करने के लिए उन्होंने सच्चरित्र का निर्माण कराया. भक्तगण अब सरलतापूर्वक चरित्र का अवलोकन करें और साथ ही उनके मनोहर स्वरूप का ध्यान करके गुरु और भगवत भक्ति के अधिकारी बनें तथा निष्काम होकर

आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हों. साई सच्चरित्र का सफलतापूर्वक संपूर्ण होना साई की महिमा ही समझें, हमें तो केवल एक निमित्त मात्र ही बनाया गया है.

मां की ममता

गाय का अपने बछड़े पर प्रेम सर्वविदित है. उसके स्तन सदैव दुग्ध से पूर्ण रहते हैं और जब भूखा बछड़ा स्तन की ओर दौड़कर आता है तो दुग्ध की धारा स्वत: प्रवाहित होने लगती है. उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की आवश्यकता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय पर स्तनपान कराती है. वह बालक का श्रृंगार उत्तम ढंग से करती है, परंतु बालक को इसका कोई भान ही नहीं होता. माता का प्रेम विचित्र, असाधारण और नि:स्वार्थ है, जिसकी कोई उपमा नहीं है. ठीक इसी प्रकार सद्गुरु का प्रेम अपने शिष्य पर होता है.

समान प्रेम का उदाहरण

यह कथा श्री साई बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है. एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी आया. वह ऊंचा, सुदृढ़ एवं सुगठित शरीर का था. बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में ही रहने लगा. वह आठों प्रहर अपनी उच्च और कर्कश ध्वनि में कुरान शरीफ पढ़ता और अल्लाह हो अकबर के नारे लगाता था. शिरडी के अधिकांश लोग खेतों में दिन भर काम करने के बाद जब रात्रि में घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकार उनका स्वागत करती. इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम न मिलता. जब यह कष्ट असहनीय हो गया, तब उन्होंने बाबा के पास जाकर रोहिला को मना करके इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की.

बाबा ने लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया. वह गांववालों को ही आड़े हाथों लेते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ध्यान दें और रोहिला की ओर ध्यान न दें. बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है और वह रोहिला को और मुझे कष्ट पहुंचाती है, परंतु वह उसके कलामों के सामने उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण रोहिला शांति और सुख में है. यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी. बाबा का संकेत केवल कुविचारों की ओर था. अन्य विषयों की अपेक्षा बाबा प्रार्थना और ईश आराधना को महत्व देते थे. अत: उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन करके ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया.

बाबा के अति सुंदर उपदेश

एक दिन दोपहर की आरती के बाद भक्तगण अपने घरों को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया. तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा हो, सो करो, परंतु यह सदैव स्मरण रखो कि जो कुछ तुम करते हो, वह सब मुझे ज्ञात है. मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभु और घट–घट में व्याप्त हूं. मेरे ही उदर में समस्त जड़ और चेतन प्राणी समाए हुए हैं. मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रणकर्ता एवं संचालक हूं. मैं ही उत्पत्ति और संहार कर्ता हूं. मेरी भक्ति करने वालों को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता. मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला माया के पाश में फंस जाता है. समस्त जंतु, चीटियां, दृश्यमान, परिवर्तनमान और स्थायी विश्व मेरे ही स्वरूप हैं.

इस सुंदर और अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा न करूंगा. तुझे नौकरी मिल जाएगी, बाबा का यह वचन सुनकर मुझे विचार आने लगा कि क्या सचमुच ऐसा घटित होगा. बाबा का वचन सत्य निकला और मुझे अल्पकाल में ही नौकरी मिल गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

योगासन और नियमित व्यायाम ज़रूरी है

ऑर्निश की उपचार–पद्धति का मूल तर्क है कि हृदय–विकार पूर्ण जीवन पद्धति का परिणाम है. केवल दवाइयों अथवा सर्जरी से हृदयरोग के मूल पर प्रहार नहीं हो सकता. सिर्फ तात्कालिक सतही इलाज होता है. इसलिए, रोग उत्पन्न करने वाले मूल कारणों पर इलाज करने के लिए ऑर्निश योगासन और नियमित व्यायाम जैसे वैकल्पिक उपचार सुझाते हैं.

डॉ. अभय बंग

मेरी एंजियोप्लास्टी हुई 10 मई को और अस्पताल से मेरी छुट्टी हुई 14 मई को. अब आगे कुछ दवाइयां नियमित लेनी होंगी और क्या होगा, इसकी प्रतीक्षा करनी होगी. मैं स्वयं रोगी था, प्रश्न स्वयं मेरे जीने और मरने का था, फिर भी इससे अधिक मैं कुछ नहीं कर सकता था. एंजियोप्लास्टी से खुली हुई वह हृदय की रक्तवाहिनी नलिका पुन: पहले ही वर्ष में बंद हो जाने की 35 फीसद संभावना थी. सिवाय पहले से आधी बंद अन्य दो रक्तनलिकाएं कुंडली मारकर बैठी ही थीं. एंजियोप्लास्टी के बाद पहली रात को मुझे खतरे का संकेत मिल गया था. इसलिए हार्ट अटैक फिर से आने की संभावना भरपूर थी. वैसा होने पर अचानक मृत्यु या पूर्व सूचना मिल सकी तो फिर एंजियोप्लास्टी या बायपास सर्जरी.

आधुनिक चिकित्साशास्त्र के वैज्ञानिक चमत्कार से मुझे फिर जीने का मौका तो मिला था, लेकिन रोग मुक्ति नहीं मिली थी. डायबिटीज के मरीजों की एंजियोप्लास्टी हुई, यानी मेरे जैसे तो पांच वर्षों के भीतर उनमें से 35 प्रतिशत मर जाते हैं. ऐसा विज्ञान बता रहा था. गोलियां खाते रहो और 35 फीसद मरने की राह देखते रहो. उपचार की इस असहायता से मुझे चिढ़ हो रही थी. मुझे जिंदा रहना था, लेकिन भविष्य की संभावना डिप्रेसिंग थी और हृदयरोग की पुस्तकें कह रही थीं कि हृदय–विकार के दौरान डिप्रेशन में आनेवाले रोगी अधिकांशत: मर जाते हैं, आशावादी और प्रसन्न रहने वाले अधिकतर रोगी जी जाते हैं. मुझे जीना तो था, लेकिन आशा के लिए आधार क्या था?

मानो नियति से वादा हुआ हो. अस्पताल में ही एक पुस्तक मुझ तक आ पहुंची. डीन ऑर्निश नामक अमेरिकन डॉक्टर द्वारा लिखी हुई, अमेरिका में इन दिनों बहुत चर्चित रिवर्सिंग हार्ट डिसीज, नाम की यह पुस्तक थी. तीन माह पहले एक डॉक्टर के तौर पर चिकित्सा संबंधी अध्ययन के लिए मैंने यह पुस्तक मंगवाई थी. अब खुद हृदयरोगी बन जाने पर वह मेरे पास पहुंची थी. अस्पताल के बिस्तर से ही मैंने उसे भूखे की तरह पढ़ना शुरू कर दिया. इस पुस्तक ने मुझे दिलासा ही नहीं दी कि मैं हृदय–विकार से मुक्त हो सकता हूं, बल्कि मेरे आगे के उपचार में क्रांति ला दी.

ऑर्निश की उपचार–पद्धति का मूल तर्क है कि हृदय–विकार पूर्ण जीवन पद्धति का परिणाम है. केवल दवाइयों अथवा सर्जरी से हृदयरोग के मूल पर प्रहार नहीं हो सकता. सिर्फ तात्कालिक सतही इलाज होता

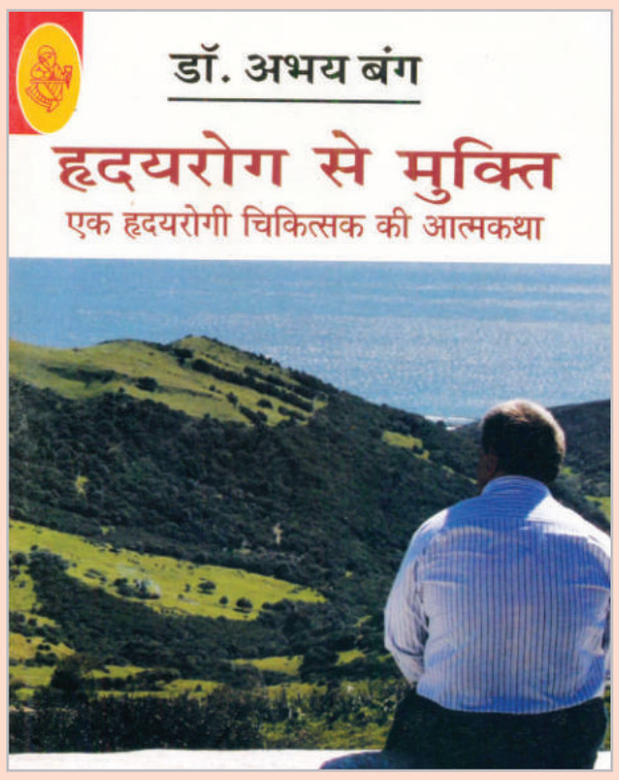

है. रोग होने के मूल कारण जीवन में वैसे ही बने रहने से एंजियोप्लास्टी अथवा बायपास सर्जरी के बाद भी कई बार रक्तनलिकाएं फिर बंद हो जाती हैं. इसके अलावा, वह उपचार बहुत महंगा भी है. इसलिए, रोग उत्पन्न करने वाले मूल कारणों पर इलाज करने के लिए ऑर्निश निम्न वैकल्पिक उपचार सुझाते हैं :

- पूर्ण शाकाहार. आहार में कोलेस्ट्रॉल शून्य करना. अपने आहार में स्निग्ध पदार्थों (फैट) का अनुपात एकदम कम–रोज की कुल कैलोरीज का 10 फीसद से कम हिस्सा स्निग्ध पदार्थों से प्राप्त करना.
- धूम्रपान और एल्कोहल वर्जित करना.
- नियमित व्यायाम व योगासन.
- मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए प्राणायाम, शवासन व मनोवृत्ति में बदलाव.
- अपनी भावनाओं के संपर्क में रहना और दूसरों के साथ भावनात्मक संबंध जोड़ना.
- जीवन में आध्यात्मिक समाधान खोजना और उसके लिए ध्यान करना.

रोग होने के मूल कारण जीवन में वैसे ही बने रहने से एंजियोप्लास्टी अथवा बाइपास सर्जरी के बाद भी कई बार रक्तनलिकाएं फिर बंद हो जाती हैं. इसके अलावा, वह उपचार बहुत महंगा भी है.

अपनी–अपनी उपचार–पद्धति का प्रचार करने हेतु बड़े–बड़े दावे करनेवालों की दुनिया में कमी नहीं है. भारत में तो गली–गली में पूरे आत्मविश्वास से रामबाण उपाय बतानेवाले शौकिया और व्यावसायिक दोनों मिल जाएंगे. ऐसे दावों के अतिरंजित और अप्रामाणिक होने के कारण मैं इनके बारे में सशंकित रहता हूं. ऑर्निश की विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी उपचार–पद्धति को वैज्ञानिक प्रयोगों से जांचकर देखा था व उसके प्रभावी होने का शास्त्रीय प्रमाण उन्हें मिला था. उनकी उपचार–पद्धति आरंभ करने से पूर्व और प्रारंभ करने के एक वर्ष बाद तटस्थ विशेषज्ञों से रोगी की कंप्यूटराइज्ड कॉरोनरी एंजियोग्राफी व पीईटी स्कैनिंग करवाने पर 82 फीसद रोगियों की हृदय की नलिकाओं की रुकावटें कम होने का प्रमाण वैज्ञानिक दृष्टि से मजबूत है और इस उपचार–पद्धति से केवल हृदय की रक्तवाहिनियां ही खुलती हैं, ऐसा नहीं, बल्कि उन्हीं के एक रोगी के शब्दों में, हृदय ही खुल जाता है. जीवन आनंदमय हो जाता है. अन्यथा, रोग तो ठीक हो जाए, लेकिन रोगी दुखी ही रहे तो क्या लाभ? इसलिए ऑर्निश के शब्दों में यह केवल हृदयरोग का उपचार नहीं, पूरी जीवनशैली ही बदल डालने का कार्यक्रम है.

ऑर्निश की स्वयं की कहानी भी दिलचस्प है. अपने स्कूली दिनों में वह होशियार विद्यार्थी था. मेडिकल में जाने का इच्छुक था, लेकिन पढ़ाई और स्पर्धा से उत्पन्न तनाव के कारण उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो गया. वह डिप्रेशन का शिकार हो गया. आत्महत्या के विचार मन में आने लगे. अन्त में हताश होकर कॉलेज छोड़कर घर बैठ गया.

उसकी बहन किसी भारतीय संन्यासी से योग सीखती थी. सहज मन बहलाव के लिए इसने भी सीखना शुरू किया और 15 दिनों में ही उसे खूब अच्छा लगने लगा. तब से योग व भारतीय जीवनपद्धति के विषय में उसके मन में आकर्षण पैदा हुआ. कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके, हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज में उसने प्रवेश लिया. योग नियमित चल ही रहा था. मासांहार और शराब छोड़ दी. कॉलेज के तीसरे वर्ष में पूरे सालभर की छुट्टी लेकर उसने हृदयरोगियों के एक समूह पर महीनेभर शाकाहार व योग का उपचार करके देखा. अच्छे परिणाम प्राप्त हुए. कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके उसने चिकित्सकीय डिग्री ली. दूसरी बार और बेहतर तरीके से वही प्रयोग किया. फिर से अच्छे परिणाम मिले. एम.डी. की पढ़ाई पूरी की.■

राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित

feedback@chauthiduniya.com

एक बार...

तेंदुए की होशियारी

एक जंगल में एक बन्दर था, जो सबसे चालाक था. उसका नाम राजू था. उस जंगल में हाथी और भालू भी रहते थे. वे सभी परेशान थे. उनकी परेशानी यह थी कि जब उनके सगे–संबंधी के नाम से कोई चिट्ठी आती थी, तो चीकू खरगोश काफी समय लगाता था, क्योंकि वह चाहता था कि चिट्ठियां लाने के लिए उसे पैसे मिले. एक दिन सबने बैठकर एकमत से सहमत होकर यह निश्चय किया कि उस वन का डाकिया राजू बन्दर को बनाया जाए. उसी दिन से राजू बन्दर को उस वन का डाकिया बना दिया गया. बन्दर समय पर सभी को डाक लाकर दे देता था. बन्दर ने पैसों की जगह हर एक से सेब लेना शुरू कर दिया. धीरे–धीरे उसने सभी से पैसे लेना शुरू कर दिया. फिर सभी ने राजन भालू को डाकिया बनाने का फैसला किया, लेकिन कीरू तेंदुए को यह मंजूर नहीं था. उसने कहा कि अब शहर में अपने नाते–रिश्तेदारों, दोस्तों, भाई–बहनों और माता–पिता को यह संदेश भिजवा दो कि वे अब चिट्ठी न लिखें, क्योंकि जंगल में जो भी डाकिया बनता है, वह हमारी भावनाओं का नाजायज फायदा उठाने लगता है. कीरू तेंदुए ने कहा कि वह एक ऐसा यंत्र बनाएगा, जिससे किसी को अपने संबंधियों के पास चिट्ठियां लिखने की जरूरत ही नहीं होगी और लोग अपनों से मिल कर चले भी आएंगे, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह यंत्र उसके पास ही रहेगा, ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न करे. सभी खुश हो गए. इसके बाद कीरू ने एक ऐसा यंत्र गाड़ी तैयार किया, जो लोहे का बना था. अब लोग उस यंत्र गाड़ी पर बैठकर जाते और अपने लोगों से मिलकर खुशी–खुशी चले भी आते थे. यंत्र गाड़ी आपातकाल में भी लोगों के काम आता था. जंगल में फिर से प्यार लौटने लगा और सभी जानवर खुशी–खुशी रहने लगे. ■

शिक्षा : जरूरतमंदों की सेवा करो.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

स्त्री विमर्श

हिंदी साहित्य में व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप की कोई जगह होनी नहीं चाहिए और हमें उसका घोर प्रतिवाद भी करना चाहिए. यही फर्क हिंदी और अंग्रेज़ी की मानसिकता का और कुंठा का है. हिंदी का लेखक इतना कुंठित हो गया है कि उसको मर्यादा की परवाह ही नहीं रही. मैं लंबे समय से इस पर लिखता आ रहा हूं, लेकिन राजेंद्र यादव को यह छाती कूटने और मात्र विलाप करने जैसा लगता है. हिंदी के ज़्यादातर लेखक छोटे से लाभ–लोभ के चक्कर में इतने उलझ गए हैं कि वो बड़ा सोच ही नहीं सकते हैं.

साहित्य सम्मान

पुरस्कारों के कारोबार से साख़ गिर रही है

प्रेमचंद के गांव के नाम पर दिया जाने वाला लमही सम्मान इस बार कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया. इसे लेकर उस समय विवाद पैदा हो गया, जब लमही पुरस्कार के संयोजक विजय राय ने एक साक्षात्कार में मनीषा को पुरस्कार देने को एक चूक बताया. हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अर्चना भैंसारे को दिया गया तो उस पर भी ऐसा ही विवाद पैदा हुआ था. दरअसल, आज हिंदी साहित्य के परिदृश्य में हद से ज़्यादा पुरस्कार हो गए हैं. हर दूसरा लेखक कम से कम एक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है. पुरस्कारों की संख्या बढ़ने के पीछे लेखकों की पुरस्कार पिपासा है. इसका फ़ायदा उठाकर साहित्य को कारोबार समझने वाले लोग मुनाफा कमाने में जुटे हैं. इस खेल से पुरस्कारों की गिरती साख़ को बचाने के लिए लेखक संगठन भी कोई ठोस क़दम नहीं उठा रहे हैं.

अनंत विजय

हिंदी साहित्य इन दिनों पुरस्कार विवाद से गरमाया हुआ है. इस गरमाहट की आंच हिंदी से जुड़े लोग अच्छी तरह से महसूस कर रहे हैं. हिंदी के महान साहित्यकार प्रेमचंद के गांव के नाम पर उनके दूर के रिश्तेदार हर साल लमही सम्मान देते हैं. लमही नाम से एक पत्रिका भी निकालते हैं. लमही पुरस्कार पिछले चार सालों से दिया जा रहा है. यह पुरस्कार अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने में जुटा था, अब तक ये पुरस्कार मशहूर अफ़सानानिगार ममता कालिया, पत्रकार साजिश रशीद और कथाकार शिवमूर्ति को दिया जा चुका है. इन तीन वर्षों के चयन पर विवाद नहीं उठा, न ही कोई सवाल खड़े हुए. इसकी वजह पुरस्कार से हिंदी जगत का अनभिज्ञ होना भी हो सकता है. 30 जनवरी, 2013 हिंदी की उभरती हुई लेखिका मनीषा कुलश्रेष्ठ को चौथा लमही सम्मान देने का ऐलान हुआ. निर्णायक मंडल में संयोजक विजय राय के अलावा वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता, फिल्मकार चंद्रप्रकाश द्विवेदी, लेखक सुशील सिद्धार्थ और प्रकाशक महेश भारद्वाज थे. इस साल विश्व पुस्तक मेले के मौक़े पर इस पुरस्कार की ख़ूब चर्चा रही थी. लमही के मनीषा कुलश्रेष्ठ पर केंद्रित अंक की ज़ोरदार बिक्री का दावा किया गया. थोड़ा बहुत विवाद उस वक्त निर्णायक मंडल में प्रकाशक के रहने पर उठा था, लेकिन चूंकि पुरस्कार की उतनी अहमियत नहीं थी, लिहाजा वो विवाद ज़ोर नहीं पकड़ सका. तक़रीबन छह महीने बाद दिल्ली में 29 जुलाई को दक्षिण दिल्ली के मशहूर सेंटर में सम्मान अर्पण समारोह संपन्न हुआ. पत्र–पत्रिकाओं में इस समारोह की ख़ूब तस्वीरें छपीं. ऐसा पहली बार हुआ था कि लमही सम्मान समारोह उत्तर प्रदेश की सरहदों को लांघ कर दिल्ली पहुंचा. माना गया कि लमही सम्मान अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए दिल्ली पहुंचा. इस समारोह को इसी आलोक में देखा समझा गया था. इस पृष्ठभूमि को बताने का मक़सद इतना है कि पाठकों को पूरा माजरा समझ में आ सके.

पुरस्कार अर्पण समारोह तक सबकुछ ठीक रहा. असल खेल शुरू हुआ पुरस्कार अर्पण समारोह के डेढ़ महीने बाद. सोशल नेटवर्किंग साइट पर किसी ने लिखा कि लमही पुरस्कार के संयोजक ने किसी पत्रिका को साक्षात्कार में कहा है कि इस साल मनीषा कुलश्रेष्ठ को पुरस्कार देकर उनसे चूक हो गई. किसी ने पत्रिका को देखने की जहमत नहीं उठाई. किसी ने विजय राय समेत जूरी के सदस्यों से बात करने की कोशिश नहीं की. किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर उनमें से किसी का पक्ष छपा. लेकिन शोर ऐसा मचा कि कौआ कान लेकर भाग गया और बजाए अपने कान को देखने के उत्साही साहित्यप्रेमी कौए के पीछे भागने लगे. फेसबुक की अराजक आज़ादी ने कौए के पीछे भागनेवालों की संख्या बढ़ाने में उत्प्रेरक का काम किया. नतीजा यह हुआ कि मनीषा कुलश्रेष्ठ ने फौरन अपने फेसबुक पेज पर लिखा– मैं यहां जयपुर में हूं. लमही सम्मान की बाबत तमाम विवाद से अनभिज्ञ हूं. विजय राय जी का

बयान अगर सत्य है कि उन्होंने दबाव में पुरस्कार दिया है, तो इस अपमानजनक सम्मान को मैं लौटाने का निर्णय ले चुकी हूं. कौआ के पीछे भागने की एक और मिसाल. फिर लेखिका ने दावा किया उसने पुरस्कार के लिए न तो प्रविष्टि भेजी थी और न ही अपनी क़िताब. उन्होंने जूरी और संयोजक से माफ़ी मांगने की बात भी की. उन्होंने आहत होकर लेखन छोड़ देने का संकेत भी दिया था. एक माहिर राजनेता की तरह चले इस दांव से फिर फेसबुकिया ज्वार उठा और लेखिका ने अपना निर्णय बदल लिया. खैर, यह तो होना ही था. लेखिका का आग्रह था कि पुरस्कार लौटाने के निर्णय को हिंदी में एक परंपरा की शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए, लेकिन वो यह भूल गईं कि हिंदी में पुरस्कार लौटाने की एक लंबी परंपरा रही है. लेकिन ज़्यादातर साहित्यक वजहों से. ज़्यादा पीछे नहीं जाकर अगर हम याद करें तो दो हज़ार दस में आलोचक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने हिंदी अकादमी का पुरस्कार ठुकरा दिया था. उनका विरोध कृष्ण बलदेव वैद के लेखन के समर्थन और हिंदी अकादमी के उस लेखक के एतराज़ पर था. अग्रवाल के पुरस्कार लौटाने के बाद हिंदी अकादमी की साख़ पर सवाल खड़ा हो गया था.

लमही सम्मान पर यह विवाद इतने पर ही नहीं रुका. अब पुरस्कार, लेखक, जूरी सदस्यों के बारे में निहायत घटिया और बेहूदा बातें भी सामने आने लगीं. लोग चटखारे ले लेकर इन व्यक्तिगत बातों से आनंद उठाने लगे. लेकिन वो बातें इतनी घटिया थीं कि उसको पढ़ने के बाद हमको अपने को हिंदी साहित्य से जुड़े होने पर भी शर्म आ रही थी. हिंदी साहित्य में व्यक्तिगत आरोप–प्रत्यारोप की कोई जगह होनी नहीं चाहिए और हमें उसका घोर प्रतिवाद भी करना चाहिए. यही फर्क हिंदी और अंग्रेज़ी की मानसिकता का और कुंठा का है. हिंदी का लेखक इतना कुंठित हो गया है कि उसको मर्यादा की परवाह ही नहीं रही. मैं लंबे समय से इस पर लिखता आ रहा हूं, लेकिन राजेंद्र यादव को यह छाती कूटने और मात्र विलाप करने जैसा लगता है. हक़ीक़त यही है कि हिंदी के ज़्यादातर लेखक छोटे से लाभ–लोभ के चक्कर में इतने उलझ गए हैं कि वो बड़ा सोच ही नहीं सकते हैं. अब देखिए कि पंद्रह हज़ार रुपये के इस पुरस्कार के लिए इतना बड़ा विवाद. इस विवाद के पीछे भी हाय हुसैन हम न हुए की मानसिकता ही है.

दरअसल, आज हिंदी साहित्य के परिदृश्य में इतने पुरस्कार हो गए हैं कि हर दूसरा लेखक कम से कम एक पुरस्कार से नवाजा जा चुका है. पुरस्कारों की संख्या बढ़ने के पीछे लेखकों की पुरस्कार पिपासा है. इसी पुरस्कार पिपासा का फ़ायदा उठाकर हिंदी साहित्य को कारोबार समझने वाले लोग फ़ायदा उठाने में जुटे हैं. पुरस्कारों के खेल पर लेखक संगठनों की चुप्पी भी ख़तरनाक है. हिंदी के तीनों लेखक संगठनों ने अब तक हिंदी में पुरस्कारों की गिरती साख़ को बचाने के लिए कोई भी ठोस क़दम नहीं उठाया है. लेखक संगठन भी पुरस्कृत लेखक या फिर विवादित लेखक की विचारधारा को देखकर ही फ़ैसला लेते हैं. उनके लिए साहित्य प्रथम का सिद्धांत कोई मायने नहीं रखता है. उनके लिए तो विचारधारा सर्वप्रथम है. लमही सम्मान पर भी लेखक संगठनों ने चुप्पी साधे रखी. उसके बाद के अप्रिय प्रसंगों पर भी लेखक संगठनों ने उसको रोकने के लिए कोई क़दम उठाया हो, ये ज्ञात नहीं है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं.)

anant.ibn@gmail.com

कविता

सुनो! मैं गांधारी नहीं हूं

दिव्या शुक्ला

सदियां गुज़र गई समय बदल गया
पर तुम्हारी अपेक्षा वही रही
कहा न मैं गांधारी नहीं हूं
मै सीता भी नहीं हूं
सीता ने नहीं देखा किसी को सिवा राम के
मैंने तो सिनेमा के नायकों की
कितनी तारीफ़ तुमसे ही की
फिर तुम भी तो राम नहीं हो
मुझसे ये अपेक्षा क्यूं?
मै औरत हूं हाड़ मांस बनी
अपना अस्तित्व भी बचाने
की कोशिश कर रही हूं
फिर अपना व्यक्तित्व
भी तो खोजना है मुझे
संबंधों का खेल ही तो है
रिश्तों का जंगल है औरत का जीवन
रोम-रोम पल-पल का हिसाब
मांगा जाता है यहां
अगर नकार दिया तो हंगामा
मीरा को भी विष का प्याला मिला
कोई बोल उठी तो बोल्ड और बेहया कहलाई
फिर क्यूं कहते हो
आजकल सब बराबर हैं
अगर है तो इतना हंगामा क्यूं
अभिव्यक्ति की आज़ादी तो
सब को होनी चाहिए
तुम तो जब चाहो, जब तक चाहो
मुझसे मेरे मन से मेरी आत्मा से
खेल सकते हो, मन न करे तो मौन
अगर यही मैं करूं तो?
थक गई हूं मैं अब और नहीं
मुझे अपने पांव टिकाने को
ठोस ज़मीन चाहिए
एक टुकड़ा ही सही पर
अपना आसमान चाहिए
मुझे थोड़ा समझो तो
मेरे आंचल मे सिर्फ प्रेम है
इसके सिवा कुछ नहीं
पर झूठा नकाब नहीं ओढ़ सकती
अपने मान और अस्तित्व के साथ
मैं तुम्हारी ही हूं लेकिन
मैं गांधारी नहीं हूं.■

किताब मिली

पुस्तक	लेखक
दिनकर अर्धनारीश्वर कवि	नंदकिशोर नवल
प्रकाशक	**मूल्य**
राजकमल प्रकाशन	350 रुपये

राजकमल प्रकाशन से आलोचक नंद किशोर नवल की नई किताब आई है दिनकर अर्धनारीश्वर कवि. इस किताब में आठ अध्यायों में दिनकर जी के कृतित्व, व्यक्तित्व और अन्य पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है. दिनकर आधुनिक हिंदी कविता के उत्तर छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं. उनपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है. ऐसे महत्वपूर्ण रचनाकार के मूल्यांकन में यह पुस्तक एक और अध्याय जोड़ेगी.

लेखक और प्रकाशक इस कॉलम के लिए अपनी किताबें हमें भेज सकते हैं.
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई–मेल: feedback@chauthiduniya.com

पुस्तक चर्चा

बदलते परिवेश में नारी

स्त्री कभी पुरुष नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह पुरुष स्त्री नहीं हो सकता. नारी को पुरुष के समान बनाने की बात करना तो स्त्री के अस्तित्व को मिटाने जैसा ही है. नारी कोमल है, लेकिन कमजोर नहीं. समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों की अलग–अलग भूमिका है.

प्रियंका तिवारी

महिला और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिये हैं. दोनों समान हैं और दोनों को प्रकृति ने अपनी पृथक पहचान दी है. आज जब हम स्त्री और पुरुष में समानता की बात करते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि जो नियम प्रकृति ने बनाए हैं, उसके विपरित आख़िर हम कैसे जा सकते हैं. स्त्री कभी पुरुष नहीं हो सकती, ठीक उसी तरह पुरुष स्त्री नहीं हो सकता. नारी को पुरुष के समान बनाने की बात करना तो स्त्री के अस्तित्व को मिटाने जैसा ही है. नारी कोमल है, लेकिन कमजोर नहीं. समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों की अलग–अलग भूमिका है.

जयति गोयल द्वारा लिखित *आज के बदलते परिवेश में नारी* भी एक ऐसी ही पुस्तक है, जिसमें बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश में नारी की स्थिति और भूमिका पर प्रकाश डाला गया है. इस पुस्तक में वर्तमान की उन सभी समस्याओं पर चर्चा की गई है, जिसमें महिला वर्ग की वास्तविक प्रगति के मार्गदर्शी भाव हैं. हालांकि लेखिका अर्थशास्त्र के लेखन से जुड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने काफी गहन शोध किया है और आज के परिवेश में नारी की स्थिति पर एक सार्थक पुस्तक लिखी है. उन्होंने महिला संरक्षण के विविध प्रावधानों की समीक्षा की है, इस क्षेत्र के अनेक अटकावों और भटकावों को इंगित करते हुए अपने मौलिक विचार रखे हैं. बदलते परिवेश में नारी सफलता के नए आयाम खोजती हुई न जाने किस दिशा में जाने के व्यर्थ प्रयास में तत्पर है. संस्कृति और सभ्यता की लकीर को लांघ कर न जाने किस प्रगति की ओर बह रही है. समाज और परिवार को जोड़ने में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आज की नारी अपने अधिकार और उनके लिए बने कानून का दुरुपयोग कर रही है. वह परिवार को जोड़ने का नहीं, बल्कि परिवार को तोड़ने का काम कर रही है. नतीजतन समाज धीरे–धीरे टूट कर बिखर रहा है. अपनी बात की पुष्टि के लिए जयति ने आधुनिक महिला समाज के समक्ष स्वतंत्रता संग्राम काल की तेजस्विनी महिलाओं का आदर्श चरित्र प्रस्तुत किया है. आज की महत्वाकांक्षी महिला संगठनों की कार्यप्रणाली के गुण दोष बताकर समाज के समक्ष आपने कुछ सुझाव प्रस्तुत किए हैं. यह युग सूचनाओं का युग है, उसे ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के पश्चात हर क्षेत्र की प्रथम महिलाओं की सूची प्रकाशित की है. लेखिका ने स्पष्ट रूप से पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने और भारतीय संस्कृति के संस्कारों को भुलाने के दुष्परिणामों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया है. लेखिका ने तार्किक ढंग से यह बताने का सफल प्रयास किया है कि गांव–देहात में रहने वाली महिलाओं के उत्थान के बिना महिला समाज का सर्वांगीण विकास हो ही नहीं सकता. सारे देश में हो रहे महिला उत्पीड़न के आंकड़े देकर यह सिद्ध किया है कि असुरक्षा का भय प्रगति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है. इन बिंदुओं और परिस्थितियों के मद्देनजर यह पुस्तक पठनीय है. ■

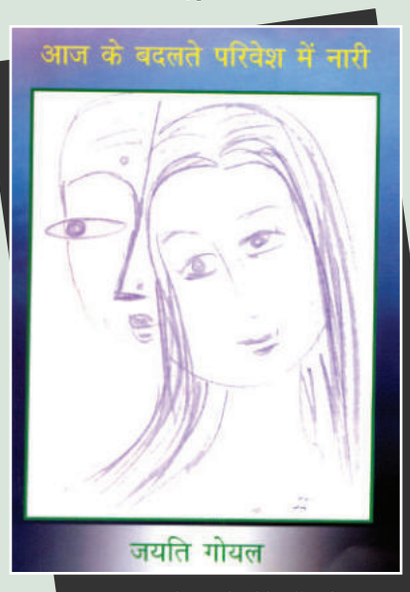

पुस्तक- आज के बदलते परिवेश में नारी
लेखिका- जयति गोयल
प्रकाशन- कश्यप पब्लिकेशन

feedback@chauthiduniya.com

आज स्त्री सफलता के नए आयाम खोजती हुई न जाने किस दिशा में जाने के व्यर्थ प्रयास में तत्पर है. संस्कृति और सभ्यता की लकीर को लांघ कर न जाने किस प्रगति की ओर बह रही है. समाज और परिवार को जोड़ने में स्त्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन आज की नारी अपने अधिकार और उनके लिए बने कानून का दुरुपयोग कर रही है. वह परिवार को जोड़ने का नहीं, बल्कि परिवार को तोड़ने का काम कर रही है.

> नई स्मार्ट वॉच 2 सोनी की स्मार्ट सीरीज का अपग्रेडेड वर्जन है. इसमें कई ग़ज़ब के फीचर्स हैं. इसकी स्क्रीन पहले की तुलना में ज़्यादा बड़ी और डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट है. इसकी ब्राइटनेस तकनीक धूप में भी आपकी घड़ी के डिस्प्ले को ज़्यादा बेहतर बनाती है.

फोटोग्राफी बनी फन

अब आपको फोटोग्राफी के लिए किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की सेवाएं लेने की ज़रूरत नहीं है. आजकल सभी स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन में एप के ज़रिए फोटोग्राफी और सुविधाजनक हो गया है.

फोटो शूट करना भला किसे अच्छा नहीं लगता. टेक्नोलॉजी के इस युग में फोटोग्राफी करना और भी आसान हो गया है. किन्हीं खास पलों को संजोना हो, फोटो कलेक्शन तैयार करनी हो, फैमिली या ग्रुप फोटोग्राफी करनी हो या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट पर फोटो लगानी हो. इन सभी के लिए आपको किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर की सेवाएं लेने की जरूरत नहीं है. आजकल सभी स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फोन में एप के जरिए फोटोग्राफी और सुविधाजनक हो गई है. हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे एप के बारे में, जो आपके फोटोग्राफ्स को और जीवंत बनाएंगे.

इंस्टाग्राम

दुनिया में करोड़ों स्मार्टफोन धारक फोटोग्राफी के लिए इंस्टाग्राम के फैन हैं. मुफ्त डाउनलोड होने वाला यह एप फोटो को चमत्कारी तरीके से सुधारने और इसे शेयर करने की सहूलियत देता है. इंस्टाग्राम की मदद से आप फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए अपने फोटो को बेहतर बना सकते हैं. इसमें प्रकाश, रंग और अन्य संयोजन को सुधार सकते हैं, पर इंस्टाग्राम की सीमाएं भी हैं और कई बार इसमें भी तस्वीरों को एडिट करने में समस्या आती है. ऐसी असुविधाओं से बचने के लिए ही आप इंस्टाग्राम के अलावा दूसरे फोटो एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.■

फोटोसिंथ

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा मुहैया कराया गया यह एप्लीकेशन भी बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन इसे सिर्फ आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही चलाया जा सकता है. आईओएस एपल के आईफोन, आईपैड और आईटच का ऑपरेटिंग सिस्टम है.

फोटोसिंथ से आप 360 डिग्री पैनोरमा में तस्वीरें ले सकते हैं और इसे अपने स्मार्टफोन या कंप्यूटर पर इंटरैक्टिव बना सकते हैं. इस एप की मदद से आप एक ही स्थान पर खड़े होकर सभी दिशाओं में फोटो शूट कर सकते हैं. इस तरह शूट की गई तस्वीरों को आप पैनोरमा के साथ शेयर कर सकते हैं और स्क्रॉल से ऊपर–नीचे और छोटा–बड़ा कर सकते हैं. आप इन तस्वीरों को फेसबुक, ट्विटर या फोटोसिंथ डॉट नेट पर शेयर भी कर सकते हैं. जो लोग किसी प्राकृतिक स्थान जैसे पहाड़, समुद्र आदि देखने जाते हैं, उनके लिए यह काफी कारगर हो सकता है.■

टिल्ट शिफ्ट जेनरेटर

यह एप्लिकेशन कुछ बेसिक फीचर के साथ मुफ्त में और ऊंचे रिजोल्यूशन तथा एलबम अपलोड के लिए पेड है. टिल्ट शिफ्ट असल में एक कैमरा इफेक्ट एप है, जो तस्वीरों के किनारों को ब्लर कर देता है. इससे फोटो मिनिएचर जैसा दिखता है.

यह सुविधा इंस्टाग्राम में भी उपलब्ध है, लेकिन इसमें यूजर को ज्यादा कंट्रोल हासिल होता है. आप यह तय कर सकते हैं कि कितना और कहां ब्लर करना है. आप यह भी कर सकते हैं कि किनारों पर कितना डार्क करना है. इसके बाद आप सैचुरेशन, ब्राइटनेस और कन्ट्रास्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं. यह भी केवल आईओएस पर चलता है.■

फोटो टोस्टर

इस एप का एक मुफ्त वर्जन भी उपलब्ध है, जिसे फोटो टोस्टर जूनियर कहते हैं, लेकिन ज्यादा विशेषताओं वाला पूर्ण वर्जन 1.99 डॉलर में उपलब्ध है. इसमें ज्यादा विकल्प और नियंत्रण उपलब्ध होता है. यह आईओएस और एंड्रॉयड डिवाइस दोनों पर डाउनलोड किया जा सकता है. फोटो टोस्टर में आप फिल्टर जैसे ट्यून अप, प्रो, हैप्पी, चिल आदि को प्रीसेट कर सकते हैं. आप एक बटन के द्वारा एक्सपोजर, कलर टेंप्रेचर, लाइट और दूसरे सेटिंग्स पर ज्यादा नियंत्रण हासिल कर सकते हैं.■

हिपस्टैमेटिक

यह सिंथेटिक एलएलसी द्वारा विकसित किया गया एक फोटो एप्लीकेशन है. इसके बुनियादी फीचर वाला वर्जन पेड, जिसमें कई अतिरिक्त विकल्प आपको मिल सकते हैं. यह केवल आईओएस वाले फोन पर ही डाउनलोड किया जा सकता है.

हालांकि इस एप में कई खामियां भी हैं. इसकी सेंटिंग पर नजर रखना मुश्किल है और इसमें जो गाइड दिया गया है. इससे बहुत मदद नहीं मिलती, लेकिन एक बार जब आप इसके वर्चुअल लेंस को समझ जाते हैं, तो इससे आप बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं.■

गैलक्सी एस 4 गोल्ड एडिशन

सैमसंग ने गैलक्सी एस 4 स्मार्टफोन के 2 गोल्ड एडिशन पेश किए हैं. सैमसंग गल्फ के फेसबुक और ट्विटर पर गैलक्सी एस4 के गोल्ड ब्राउन और गोल्ड पिंक मॉडल की तस्वीर पोस्ट की गई है. अभी इसके कीमत के बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है. कंपनी ने यह भी नहीं बताया है कि गोल्ड एडिशन फोन में 4जी एलटीई है या नहीं, क्योंकि सैमसंग गल्फ में गैलक्सी एस4 के दोनों वर्जन- 4जी और बिना 4जी - बेचती है. सैमसंग गैलक्सी एस4 में 5 इंच का फुल एचडी सुपर एमोलेड स्क्रीन, 13 मेगापिक्सल कैमरा और 2 जीबी रैम है. 4जी एलटीई वर्जन में क्वॉड-कोर स्नैपड्रैगन प्रोसेसर और बिना 4जी एलटीई वाले वर्जन में ऑक्टा-कोर एग्ज़िनॉस प्रोसेसर है. टचस्क्रीन को दस्ताने पहनकर भी यूज किया जा सकता है. कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास3 लगे होने से यह डैमेज रेसिस्टेंस है और पुराने वर्जन से तीन गुना ज्यादा स्क्रैच रेसिस्टेंस है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

बेहतरीन कार हैं ये

कार कंपनियों ने फेस्टिव सीजन की तैयारी शुरू कर दी है. फिएट ग्रुप ऑटोमोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इंट्री लेवल की सेडान सेगमेंट में लीनिया के शानदार वर्जन को लॉन्च किया है. कंपनी ने इस लीनिया को दो इंजन वैरियंट के साथ पेश किया है. नई सेडान 1.4 लीटर (फायर) पेट्रोल और 1.3 लीटर डीजल इंजन पर काम करती है. डीजल इंजन लीनिया क्लासिक की कीमत 6.95 लाख रुपये है, जबकि डीजल इंजन लीनिया क्लासिक+ 7.50 लाख रुपये तय की गई है. फिएट क्राइस्लर इंडिया के प्रेसिडेंट और एमडी नगेश बसवनहल्ली का कहना है कि हमने फेस्टिव सीजन का ध्यान रखते हुई इस कार को लॉन्च किया है. हम कस्टमर्स को हैचबैक की कीमत में शानदार सेडान कार दे रहे हैं. यह कार उन कस्टमर्स को बेहद पसंद आएगी, जो किफायती कीमत में एडवांस फीचर और तकनीक की गाड़ी पसंद करते हैं.■

घड़ी से करें ईमेल और कॉल

आपको अगर घड़ियों का शौक है तो सोनी आपके लिए बढ़िया स्मार्ट वॉच लेकर आया है. ये आपकी कलाई और आपको बना देगी और भी ज्यादा स्मार्ट. ये नई स्मार्ट वॉच 2 सोनी की स्मार्ट सीरीज का अपग्रेडेड वर्जन होगा. इस नई स्मार्ट घड़ी में कई गजब के फीचर्स हैं. नई घड़ी की स्क्रीन पहले की तुलना में ज्यादा बड़ी और डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है. इसकी नई ब्राइटनेस तकनीक धूप में भी आपकी घड़ी के डिस्प्ले को ज्यादा बेहतर बनाती है. इसमें इस्तेमाल की जाने वाली बैट्री लंबा बैकअप देती है. इसमें इनबिल्ड एनएफसी तकनीक इसका यूएसपी है. पिछले मॉडल में एनएफसी तकनीक नहीं थी. इस तकनीक के जरिए आप दूसरी घड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं. ये घड़ियां वाटर प्रूफ क्वालिटी की हैं. इन हाईटेक घड़ियों की मदद से आप फोन कॉल भी कर सकते हैं. आप अपने डाउनलोडेड ईमेल पढ़ सकते हैं. ये रिस्टवॉच स्टेनलैस स्टील से बनी है, जो दिखने में बेहद आकर्षक और यूनिक है. इस घड़ी को एंड्रॉयड स्मार्टफोन सीरीज के साथ भी आसानी से अटैच किया जा सकता है. ये घड़ियां तकरीबन 9 हजार रुपये में बाजार में उपलब्ध हैं.■

जानिए कैसा है नमो स्मार्ट फोन?

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसकों की तरफ से लॉन्च किए गए स्मार्टफोन की हर जगह चर्चा है. 6.5 ईंच के डिस्प्ले स्क्रीन वाले इस स्मार्टफोन में कई ऐसी खूबियां हैं, जो लोगों को इसकी ओर आकर्षित करती हैं. यह एंड्रॉयड पर चलने वाला स्मार्टफोन है.

स्मार्ट नमो की खूबियां

- 6.5 ईंच डिस्प्ले साइज वाला यह स्मार्टफोन फुल एचडी क्वालिटी है.
- इसमें 1.5 क्वाडकोर प्रोसेसर लगा हुआ है, जो इसे तेज चलने में मदद करता है.
- यह डुअल सिम सपोर्टेड स्मार्टफोन है. आप एक साथ दोनों सिम को एक्टिवेट रख सकते हैं.
- कनेक्टिविटी के मामले में ये स्मार्टफोन 3जी, जीपीआरएस, ब्लूटुथ और वाई–फाई जैसे फीचर्स से लैस हैं.
- इस स्मार्टफोन की इंटरनल मेमोरी क्षमता गजब की है. इसकी स्टोरेज क्षमता 32जीबी है.
- कंपनी ने इसमें डुअल कैमरे का इस्तेमाल किया है. रियर कैमरा एलईडी फ्लैश सहित 13 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का है.
- यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड वी 4.2.1 जैली बीन ओएस पर काम करता है.
- इसमें 3150 एमएएच बैट्री का इस्तेमाल किया है, जो लंबा बैट्री बैकअप देता है.
- इस नये स्मार्टफोन में कई अत्याधुनिक फीचर्स भी इस्तेमाल किए गए हैं. इनमें जी सेंसर, मैग्नेटिक एवं डिजिटल कंपास आदि लगे हैं.
- इस नये स्मार्टफोन में प्री लोड ऐप, जैसे सोशल नेटवर्किंग और गूगल डाउनलोड किया जा सकता है.

पुराना टीवी बनेगा एंड्रायड वर्जन

जानी मानी कंपनी माइक्रोमैक्स आपके लिए एक ऐसा डिवाइस लेकर आई है, जो पुराने टीवी को बना देगा नया एंड्रॉयड टीवी. इसके नये शानदार फीचर्स आपके पुराने टीवी में जान डाल देंगे. माइक्रोमैक्स ने टीवी की डिस्प्ले क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए 1 जीबी डीडीआर3 रैम का इस्तेमाल किया है. इसका जबरदस्त 3डी ग्राफिक्स डिस्प्ले क्वालिटी को एक नया आयाम देगा. इस नई डिवाइस को खरीदने के बाद आपको नये हाई डेफिनेशन टीवी पर पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. इसमें इस्तेमाल किया गया एंड्रॉयड आईसक्रीम सैंडविच ओएस आपके टीवी की परफॉर्मेंस को और तेज बना देता है. इस ओएस से आपके टीवी देखने का अनुभव कई गुना बेहतर हो जाएगा. ■

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

> इस मैराथन की ब्रांड ऐम्बेस्डर ऐक्ट्रेस बिपाशा बासु हैं. बिपाशा लगातार चौथे साल इस आयोजन से जुड़ी हुई हैं. इस साल 30,000 से अधिक धावकों के इस मैराथन में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जिसमें प्रोफेशनल रनर्स के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्र के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है.

बदलाव के दौर से गुज़रता घरेलू क्रिकेट

आईपीएल भारतीय घरेलू क्रिकेट की परेशानियों की जड़ है. रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्राफी, विजय हजारे ट्राफी में खेलने वाले खिलाड़ी ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पूल हैं. यदि भारतीय क्रिकेट की जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, तो हम खेल के फलने–फूलने की आशा कैसे कर सकते हैं.

नवीन चौहान

आईपीएल की चकाचौंध में भारत का घरेलू क्रिकेट अपनी पहचान खोने लगा है. अब प्रशंसक खिलाड़ियों को उनकी घरेलू रणजी टीम से ज्यादा आईपीएल टीम के नाम से जानते हैं. भारत में कितनी टीमें रणजी ट्रॉफी में खेलती हैं, इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को होगी. घरेलू क्रिकेट में फिर से नई जान फूंकने के उद्देश्य से बीसीसीआई ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली की अध्यक्षता में 2012 में एक कमेटी गठित की थी. कमेटी ने जो सिफारिशें की थीं, उन सिफारिशों को बीसीसीआई की टेक्निकल कमेटी ने जून 2012 में हरी झंड़ी दिखा दी थी और 2012–13 और 2013–14 के घरेलू क्रिकेट सत्र में उन सिफारिशों को लागू करने की घोषणा भी की थी.

उन्हीं सिफारिशों के आधार पर मैजूदा क्रिकेट सीजन की शुरुआत एन पी के साल्वे चैलेंजर ट्राफी के साथ इंदौर में हुई. पूर्व में इस ट्रॉफी में इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन और इंडिया रेड नाम की तीन टीमें आपस में खेलती थीं, लेकिन इस बार इंडिया ब्लू, इंडिया रेड और पिछले सीजन की घरेलू एकदिवसीय टूर्नामेंट विजेता दिल्ली की टीम भिड़ती दिखीं. यह तो एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन सौरव गांगुली कमेटी ने रणजी ट्रॉफी में व्यापक स्तर पर बदलाव किए जाने की सिफारिश की थी और उन बदलावों को पिछले सीजन से ही लागू कर दिया गया.

लंबे समय तक भारतीय घरेलू क्रिकेट अप्रभावी और अप्रतिस्पर्धी बना रहा. पूर्व भारतीय बल्लेबाज आकाश चोपड़ा ने घरेलू क्रिकेट में किए गए बदलावों को सही बताया और कहा कि यह बीसीसीआई द्वारा सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है. कम से कम इसे यह एहसास तो हुआ कि वर्तमान स्ट्रक्चर में कोई न कोई खामी जरूर है. आखिरकार बीसीसाई ने इसे स्वीकार किया. कोई भी बदलाव तब तक नहीं लाया जा सकता है, जब तक उसे स्वीकार न किया जाए. नए फॉर्मेट में 27 रणजी टीमों को 9–9 टीमों को तीन–तीन के ग्रुपों में बांटा जाने लगा है. पहले दौर में सारी टीमें आठ–आठ मैच खेलती हैं, जिनमें से आधे मैच घरेलू मैदान पर और आधे मैच विपक्षी टीम के मैदान में खेले जाते हैं. पुराने फॉर्मेट में सभी टीमों को पांच से छह मैच पहले राउंड में खेलने होते थे. भारत जैसे बड़े देश में 27 टीमों के बीच होने वाले मुक़ाबलों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है. हालांकि अब जो बदलाव किए गए हैं, वे सभी टीमों के लिए फायदा पहुंचाते दिख रहे हैं. नये फॉर्मेट में सीधे तौर पर मैच जीतने वाली टीम को अब पांच की जगह छह अंक दिए जाते हैं. इस वजह से अब टीमें पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीतने की बजाए सीधे मैच जीतने की कोशिश करती हैं. इस वजह से परिणाम निकलने वाले मैचों की संख्या में इजाफा हुआ है. मैच रोचक हुए हैं. जब बदलाव की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की गई थी, उस समय दिल्ली के पूर्व कप्तान और पूर्व टेस्ट क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने रणजी मैचों में सीधी जीत दर्ज करने वाली टीमों को 10 लाख रुपये ईनाम के रूप में दिए जाने की पैरवी की थी. ऐसा करने पर दोनों ही टीमें मैच की शुरुआत से जीत दर्ज करने के लिए ही मैदान में उतरेंगी. इसके साथ ही टीमों को सीधे–सीधे जीत दर्ज करने पर पांच की जगह छह अंक दिए जाने लगे हैं. दस विकेट या पारी की जीत हासिल करने पर एक अतिरिक्त बोनस अंक भी दिया जाने लगा है, जबकि पहले पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत दर्ज करने पर टीमों को तीन अंक हासिल होंगे. अब जीत के तरीके का अंतर टीम को चार अंकों की बढ़त दिला देता है. एक लीग मैच में चार अतिरिक्त अंक की बढ़त अगले चरण में फायदेमंद साबित हो सकता है.

अभी तक घरेलू क्रिकेट मैच पहली पारी के इर्द–गिर्द घूमते नजर आते थे. यदि हमें नई पीढ़ी के खिलाड़ी पैदा करने हैं तो हमें इस तरह के बदलाव करने होंगे. समय के हिसाब से हमें खुद को बदलना होगा. घर और घर के बाहर खेले जाने वाले मैचों की संख्या बराबर होने की वजह से अब मैच अच्छी पिचों पर खेले जाने की संभावना है. जाहिर है कि हर टीम अपनी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहती हैं. किए गए बदलाव इस बात की गारंटी नहीं देते हैं कि निश्चित तौर पर इस तरह के निर्णय से घरेलू टीमें अपनी सहूलियत के हिसाब से पिचें नहीं बनाएंगी और पिचों की क्वालिटी में सुधार हो जाएगा. पिचों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बीसीसीआई को स्वयं इसे मॉनीटर करना होगा और इसके लिए पिच क्यूरेटरों पर दबाव बनाना होगा, क्योंकि सारे क्यूरेटर बीसीसीआई की पिच कमेटी के दायरे में आते हैं.

यदि हम पिच की क्वालिटी में सुधार नहीं करेंगे तो हम अच्छे क्रिकेटर भी पैदा नहीं कर पाएंगे. न ही विदेशी धरती पर टेस्ट मैचों में जीत हासिल कर पाएंगे. कुछ पूर्व खिलाड़ियों की राय में तो मैचों को न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से दर्शकों की संख्या में बहुत कमी आ जाती है. ऐसे भी आईपीएल को छोड़कर घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताओं में दर्शकों का कमी ही रहती है. नॉकआउट मैचों को चार से पांच दिन का करने का फैसला भी अच्छा साबित हो रहा है. अब नॉकआउट मैचों में पहले के फॉर्मेट से ज्यादा समय मिल पा रहा है. पहली पारी में मामूली बढ़त हासिल करने वाली टीम को आगे बढ़ने का मौका मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि एक अतिरिक्त दिन बेहतर टीम को सामने आने का मौका देता है.

आईपीएल भारतीय घरेलू क्रिकेट की परेशानियों की जड़ है. रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्राफी, विजय हजारे ट्राफी में खेलने वाले खिलाड़ी ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का पूल है. यदि भारतीय क्रिकेट की जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी, तो हम खेल के फलने–फूलने की आशा कैसे कर सकते हैं. भारतीय टीम एक बेहतरीन स्पिनर की तलाश लंबे समय से कर रही है, बेहतर स्पिनर न मिलने का कारण यह है कि टी–20 मैचों में गेंदबाजी करने की वजह से स्पिनर गेंद को फ्लाइट कराने की बजाए फ्लैट गेंदबाजी करते हैं, जिससे उनकी गेंदों में बल्लेबाज ज्यादा रन न बना सकें. गेंदबाजों और गेंदबाजों की असली परीक्षा टेस्ट मैचों में ही होती है और भारत में घरेलू स्तर पर यह काम रणजी ट्रॉफी लंबे समय से कर रही है.

पिछले सीजन में ही घरेलू क्रिकेट में बदलाव किए गए. पिछले रणजी सीजन में कुल 115 मैच खेले गए, जिनमें 46 मैचों के ही स्पष्ट परिणाम निकले. हालांकि ये परिणाम बहुत ही उत्साहजनक नहीं हैं, जबतक करीब 60 से 70 फीसद मैचों के परिणाम नहीं निकलेंगे, तबतक जो बदलाव किए गए हैं, उसके बदलाव सार्थक नहीं कहे जा सकते. यह सीजन बदलाव का दूसरा सीजन होगा पिछले सीजन में खिलाड़ियों को नए फॉर्मेट के साथ ताल मेल बैठाने में लगा हो, लेकिन इस सीजन सभी टीमें नये फॉर्मेट से अच्छी तरह परिचित हैं. आईपीएल में राहुल द्रविड, माइकल हसी जैसे उम्र दराज खिलाड़ियों की सफलता से यह बात अच्छी तरह साबित हो गई है कि तकनीकी रूप से सुदृढ़ हुए बिना कोई भी खिलाड़ी लंबे समय तक आईपीएल या कहें टी–20 फॉर्मेट में सफल नहीं हो सकता है. अपने को हर परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए खिलाड़ियों और टीमों को घरेलू क्रिकेट की कसौटी पर खरा उतरना होगा. ■

navinchauhan@chauthiduniya.com

अफगानिस्तान विश्व कप 2015 के लिए क्वालीफाई

अफगानिस्तान ने पिछले दिनों कीनिया को सात विकेट से हराकर आईसीसी विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है. कीनिया को हराकर विश्व क्रिकेट लीग चैंपियनशिप में अफगानिस्तान दूसरे स्थान पर रहा. अफगानिस्तान ने विश्व कप 2015 के पूल ए में जगह बनाई है, जिसमें सहमेजबान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अलावा बांग्लादेश, इंग्लैंड, श्रीलंका और तीसरा क्वालीफायर हैं. अफगानिस्तान आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का अपना पहला मैच 18 फरवरी को कैनबरा के मनुका ओवर में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा, जबकि 22 फरवरी को डुनेडिन में श्रीलंका, 26 फरवरी को डुनेडिन में ही तीसरे क्वालीफायर, चार मार्च को पर्थ में ऑस्ट्रेलिया, आठ मार्च को नेपियर में न्यूजीलैंड, जबकि 13 मार्च को सिडनी में इंग्लैंड से भिड़ेगा. ■

International Cricket Council

दिल्ली हाफ मैराथन दिसंबर में

एअरटेल दिल्ली हाफ मैराथन के छठे संस्करण का आयोजन 15 दिसंबर को होना है, जिसके लिए पिछले दिनों रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया. इस मैराथन की ब्रांड ऐम्बेस्डर ऐक्ट्रेस बिपाशा बासु हैं. बिपाशा लगातार चौथे साल इस आयोजन से जुड़ी हुई हैं. इस साल 30,000 से अधिक धावकों के इस मैराथन में हिस्सा लेने की उम्मीद है, जिसमें प्रोफेशनल रनर्स के साथ–साथ विभिन्न क्षेत्र के लोगों के भाग लेने की उम्मीद है. रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम तीन अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलेगा. इसके लिए वेबसाइट–प्रोकैमरनिंग डॉट इन/एडीएचएम पर लॉग इन किया जा सकता है. विशेष जानकारी के लिए मोबाइन नंबर–96500 3333 पर भी संपर्क किया जा सकता है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

युवाओं को ट्रेनिंग देने वाली क्रिकेट-एकेडमी बंद होगी

उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (यूपीसीए) के कमला क्लब ग्राउंड पर युवाओं को क्रिकेटरों के गुर और बारीकियां सिखाने वाली क्रिकेट प्रशिक्षण एकेडमी को अचानक यूपीसीए ने बंद करने का फैसला किया है. इस एकेडमी को प्रदेश की रणजी टीम के पुराने धुरंधर खिलाड़ी चलाते थे और इसमें बहुत ही कम फीस पर आठ साल से 22 साल तक के युवाओं को क्रिकेट की ट्रेनिंग दी जाती थी. इस एकेडमी के बंद होने से यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे करीब 120 युवा क्रिकेटर बहुत आहत और परेशान है. पिछले कई सालो से सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, पीयूष चावला बनने का सपना देख रहे इन बच्चों को अब अपना भविष्य अंधकारमय लग रहा है. यूपसीए के उपाध्यक्ष एम एम मिश्रा का एकेडमी बंद करने पर कहना है कि अब यूपीसीए अगले साल से एक नई एकेडमी खोलने का विचार कर रहा है, इसलिए पूर्व रणजी खिलाड़ियों द्वारा चलाई जा रही इस क्रिकेट प्रशिक्षण एकेडमी को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया
जगमग दुनिया
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467
14 अक्टूबर–20 अक्टूबर 2013

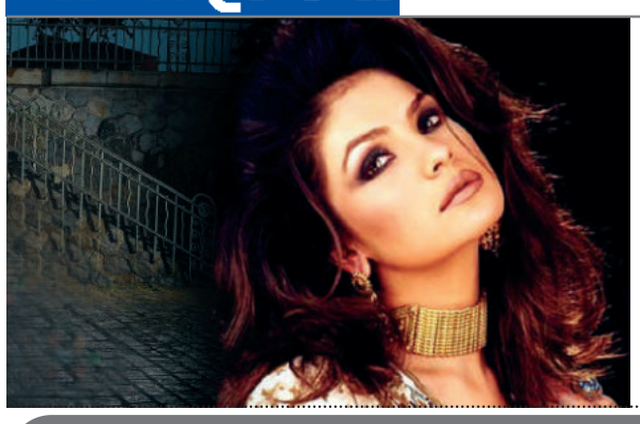

जैकलीन ने जर्नलिज़्म की पढ़ाई की है. वह जर्नलिस्ट बनना चाहती थीं. कुछ टाइम के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया है. उनकी आंटी, फ्रेडरिका जॉर्ज श्रीलंका की नामी जर्नलिस्ट हैं और जैकलीन की शुरुआत उनकी आंट के पास से ही इंटर्नशिप से हुई थी. वह कहती हैं कि शायद उनकी क़िस्मत में कुछ और ही लिखा था.

पूजा की वापसी

प्रियंका तिवारी

डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और अभिनेत्री पूजा भट्ट एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करने वाली हैं. जी हां, असमिया-हिंदी गायक भूपेन हजारिका के जीवन पर आधारित फिल्म में पूजा भट्ट फिल्मकार कल्पना लाजमी की भूमिका निभा सकती हैं. दरअसल, पूजा इस फिल्म को प्रोड्यूस भी कर रही हैं. हजारिका और लाजमी के बीच 40 साल तक प्रगाढ़ रिश्ता रहा है. धुमुहाः द स्टॉर्म नाम से इस फिल्म को लाजमी व पूजा के पिता महेश भट्ट मिलकर लिख रहे हैं. कल्पना लाजमी फिल्म को डायरेक्ट करेंगी. पूजा ने बताया कि कल्पना ने उन्हें फिल्म में भूमिका निभाने का ऑफर दिया और वह इतने समय बाद यह प्रस्ताव पाकर काफी खुश हैं. हालांकि वह यह भी मानती हैं कि लंबे गैप के बाद फिल्म के लिए उन्हें अपनी बॉडी को शेपअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा. उन्हें इसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करना होगा. फिल्म की स्क्रिप्ट अभी लिखी जा रही है और हजारिका के किरदार का चुनाव अभी चल रहा है. हजारिका एक कवि, संगीतकार, गायक, ऐक्टर, जर्नलिस्ट, लेखक और फिल्मकार थे. वे असमिया फिल्मोद्योग के अग्रदूतों में से एक थे और पूर्वोत्तर संस्कृति के बेताज बादशाह थे. हजारिका का 2011

में निधन हो गया था. फिल्म में भूपेन हजारिका और कल्पना लाजमी के बीच प्रेम संबंधों को दिखाया जाएगा. पूजा इस फिल्म को लेकर काफी उत्सुक हैं. 90 के दशक में पूजा भट्ट की गिनती बॉलीवुड की हॉटेस्ट ऐक्ट्रेसेज में होती थी. गौरतलब है कि पूजा भट्ट की आखिरी फिल्म थी 2001 में एवरीबडी सेज आई एम फाइन. इस फिल्म में उनके किरदार का नाम तान्या था. इसके बाद वह पूरी तरह से फिल्म निर्माण में उतर आईं. वर्ष 1997 में फिल्म तमन्ना, 1998 में दुश्मन, जख्म, 2002 में सूर: द मेलोडी ऑफ लाइफ, 2003 में जिस्म और पाप, 2005 में रोग, 2006 में हॉलीडे, 2007 में धोखा, 2010 में कजरारे, 2012 में जिस्म 2 जैसी फिल्में उन्होंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया. दिल है कि मानता नहीं, तमन्ना और जख्म जैसी फिल्मों के लिए उन्हें कई अवॉर्ड्स भी मिले. पूजा अपने पिता महेश भट्ट को फौलो कर रहीं हैं और उन्हीं मानकों पर फिल्में बनाती हैं, जिन पर उनके पिता महेश भट्ट बनाते रहे हैं. उनकी फिल्में आम फिल्मों से कुछ अलग होती हैं, लेकिन व्यावसायिक तौर पर हिट के फॉर्मूला पर जोर दिया जाता है, क्योंकि मुख्य मकसद पैसा कमाना ही होता है.

पूजा अपनी फिल्मों की तारिकाओं की खूबसूरती पर भी खासा ध्यान देती हैं. हालांकि अब उनका कहना है कि वह खुद को पहले सी देखना चाहती हैं. वह कहती हैं कि पिछले दो सालों से उनका खुद पर ध्यान नहीं था. उनकी प्राथमिकता में उनकी फिल्मों की अभिनेत्रियां सनी लियोन, बिपाशा बसु थीं और पूजा भट्ट पीछे रह गई थी. हालांकि पूजा को साइज जीरो फिगर पसंद नहीं है. वह कहती हैं कि साइज जीरो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता. न तो मानसिक रूप से और न ही शारीरिक रूप से. ■

feedback@chauthiduniya.com

द बॉस

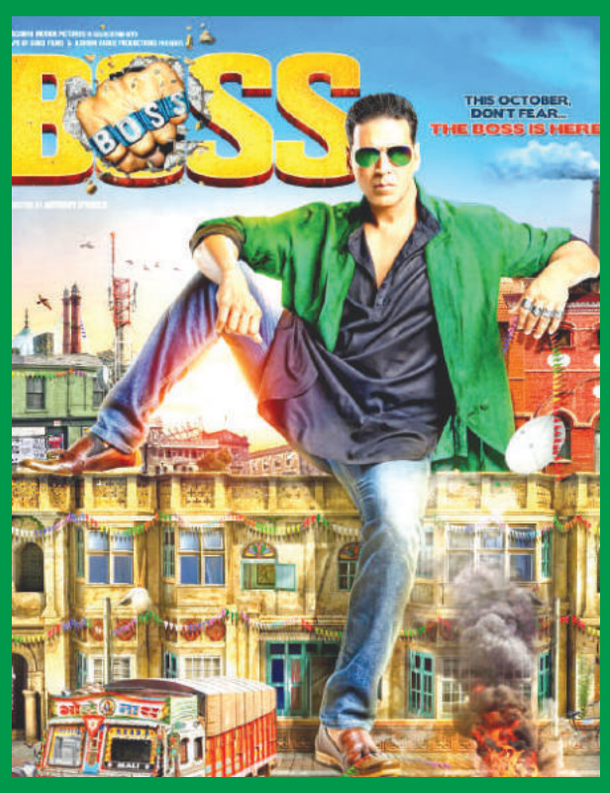

डायरेक्टर	:	एंथनी डिसूजा
प्रोड्यूसर	:	अश्विन वार्डे
स्टोरी, स्क्रीनप्ले ऐंड डायलॉग	:	फ़रहाद साजिद
बेस्ड ऑन	:	पोकिरी राजा
कलाकार	:	अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अदिति राव हैदरी, शिव पंडित, रॉनित रॉय, डैनी डेनजोनगप्पा, जॉनी लीवर, परीक्षित साहनी
डिस्ट्रीब्यूटर	:	वॉयकॉम 18
रिलीज डेट	:	16 अक्टूबर, 2013
भाषा	:	हिंदी

यह एक ऐक्शन कॉमेडी फिल्म है. यह फिल्म मम्मोती, पृथ्वीराज और श्रिया सरन स्टारर मलयाली फिल्म पोकिरी राजा की रिमेक है. फिल्म में अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, अदिति राव हैदरी और रॉनित रॉय मुख्य भूमिका में हैं. सोनाक्षी सिन्हा और हनी सिंह ने स्पेशल अपियरेंस दिया है. अक्षय कुमार एक दयालु हरियाणवी गैंगस्टर की भूमिका में हैं, जिसे सभी बॉस के नाम से जानते हैं. मिथुन चक्रवर्ती बॉस के पिता की भूमिका में हैं. शिव पंडित अक्षय कुमार के भाई की भूमिका में हैं. वहीं अदिति फिल्म में उनके अपोजिट हैं. अदिति ने इस फिल्म में पहली बार बिकनी पहना है. डैनी इस फिल्म में अक्षय के विश्वसनीय सलाहकार की भूमिका में हैं. वहीं रॉनित रॉय एक पुलिस ऑफिसर आयुष्मान ठाकुर की भूमिका में हैं. इस फिल्म में बॉलीवुड का बिगेस्ट क्लब डांस गाना फिल्माया जाएगा. अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा पर क्लब डांस गाना पार्टी ऑल नाइट... फिल्माया गया है. इस गाने में हनी सिंह भी नजर आएंगे. इस गाने का निर्देशन सुमित दत्त ने किया है, जबकि डांस डायरेक्टर राजू खान ने की है. सुमित दत्त इस तरह के गानों के लिए काफी पसंद किए जाते हैं. सुमित दत्त ने सलमान के लिए कैरेक्टर ढीला और ढिंकाचिका जैसे गानों का डायरेक्शन किया था, जिसे काफी पसंद किया गया था. फिल्म का प्रोडक्शन अक्षय कुमार, अश्विनी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कर रहे हैं. इस फिल्म में ऐक्शन, कॉमेडी, ड्रामा सबकुछ है. माना जा रहा है कि अक्षय की अन्य साउथ की रिमेक फिल्मों की तरह यह फिल्म भी काफी पसंद किया जाएगा. ■

जर्नलिस्ट जैकलीन

जैकलीन फर्नांडीज ने बॉलीवुड में अपने पैर जमा लिए हैं. रेस 2 में उनके काम की काफी सराहना हुई. इसके बाद हाल ही में रिलीज हुई फिल्म रामइया वस्तावइया में जादू की झप्पी... पर आइटम डांस किया. उनके परफॉरमेंस को काफी सराहा गया. परिवार से दूर रह कर वह बॉलीवुड में अपना करियर बना रही हैं. उनके पिता श्रीलंका के हैं और मां मलयेशिया की और उनका पूरा बचपन बहरीन में बिता. वह अलग-अलग कल्चर में रहीं. वह मानती हैं कि तभी से उन्हें डिफरेंट कल्चर और लैंग्वेजेज को समझने का शौक लगा और इंडिया के लिए तो उनके मन में एक खास जगह है. उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है. वह जर्नलिस्ट बनना चाहती थीं. कुछ टाइम के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में काम भी किया है. उनकी आंटी, फ्रेडरिका जॉर्ज श्रीलंका में नामी जर्नलिस्ट हैं और उनकी शुरुआत उनकी आंट के पास से ही इंटर्नशिप से हुई थी. वह कहती हैं कि शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था. अपनी शादी के बारे में वह कहती हैं कि उनके मन में शादी को लेकर कई तरह के सवाल हैं. आज के दौर में शादी के परसेंटेज से ज्यादा रेट तलाक का है. उन्हें शादी को लेकर डर है, लेकिन वह यह भी कहती हैं कि उनके पैरेंट्स की शादी को 30 साल हो चुके हैं और वे साथ में आज भी बेहद खुश हैं. वह अपने माता-पिता को आइडियल मानती हैं, लेकिन वह यह भी कहती हैं कि आज के समय में शायद यह बात फिट नहीं होती. उन्हें बच्चों से बेहद प्यार है और वह कहती हैं कि उनकी शादी हो या न हो, लेकिन इतना तय है कि उनके बच्चे जरूर होंगे. ■

पहले एलियन अब बाइकर

हॉलीवुड की एक्शन फिल्मों में शुमार एवेंजर्स का सीक्वल एवेंजर्स 2 बन रहा है. इस फिल्म में अभिनेत्री स्कारलेट जॉनसन बाइक चलाती हुई नजर आएंगी. इसे लेकर वह काफी उत्सुक हैं. फिल्म की पूरी शूटिंग सड़कों पर होगी. उन्होंने यह भी बताया कि सीक्वल में उन्हें शहर की सड़कों पर बाइक चलाने का मौका मिलेगा, जिसके लिए वे रोमांचित महसूस कर रही हैं. फिल्म के डायरेक्टर जॉस व्हीडोन हैं. उन्होंने ही इसका स्क्रीनप्ले लिखा है. इसमें अल्ट्रॉन, आयरन मैन, ब्लैक विडो, मारिया हिल, टोनी स्टार्क, नताशा रोमानोफ जैसे किरदार हैं. स्कारलेट की फिल्म अंडर द स्किन भी चर्चा में है. इसी महीने इस फिल्म का टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुआ है और इसे जबरदस्त सराहना भी मिली है. स्कारलेट का मानना है कि उनके द्वारा आज तक निभाए गए किरदारों में यह सबसे ज्यादा रिवीलिंग और चैलेंजिंग रहा है. जोनाथन ग्लेजर की इस साई-फाई थ्रिलर फिल्म में स्कारलेट मानवों को खाने वाली एलियन की भूमिका निभा रही हैं. ■

अदिति को पसंद नहीं आइटम डांस

अदिति राव हैदरी आइटम डांस के पूरी तरह से खिलाफ हैं. वह कहती हैं कि उन्हें आइटम का हिस्सा बनने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह अच्छा होना चाहिए. सच तो यह है कि उन्हें आइटम सॉन्ग्स शब्द से ही नफरत है. उनके लिए आइटम गाना वह होता है, जिसमें लड़की छोटे कपड़े पहनती है और सेक्सी दिखती है, लेकिन वह घटिया नहीं दिखना चाहतीं. वे कहती हैं कि उनके लिए डिग्निटी सबसे पहले है. वह आइटम सॉन्ग करेंगी, लेकिन यह एक डांस नंबर होगा तो. अक्षय कुमार के लीड रोल वाली इस फिल्म में अपने बोल्ड अंदाज पर मिल रहे पॉजिटिव रिएक्शन से अदिति काफी खुश हैं. इससे पहले वह रॉकस्टार, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी फिल्मों में काम कर चुकीं हैं. अदिति को द बॉस के लिए वजन कम करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें फिल्म के सीन में बिकिनी पहनना था. वह खुश हैं कि लोगों से उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. अदिति आमिर खान की पत्नी किरण राव की कजन हैं, लेकिन वह कहती हैं कि इंडस्ट्री काफी कठिन जगह है, जहां आपको संघर्ष करना पड़ता है. ■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

14 अक्टूबर–20 अक्टूबर 2013

बिहार – झारखंड

बंधन में गठबंधन

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

चारा घोटाले में लालू प्रसाद के जेल जाने और इसी मामले में नीतीश कुमार पर जांच को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बिहार में सियासी गठबंधन का पेच पूरी तरह फंस गया है. लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए हर दल अपने हिसाब से अपने साथी की तलाश में जुटा हुआ था, पर इस बदलते घटनाचक्र ने सभी दलों को एक बार फिर से नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है.

सरोज सिंह

बिहार में इन दिनों केवल एक यानी राजद व लोजपा का गठबंधन है, लेकिन सभी जानते हैं कि आज की तारीख में यह गठबंधन जमीनी कम और कागजी ज्यादा है. पिछले विधानसभा चुनाव के बाद शायद ही कभी ऐसा मौका आया, जब जनता के सवाल पर दोनों पार्टियों ने मिलकर संघर्ष किया हो. हां इतना जरूर है कि राजद तो नहीं, पर लोजपा के नेता बार-बार यह जरूर कहते रहे कि राजद के साथ हमारा गठबंधन अटूट है. राजद ने इस गठबंधन को लेकर कभी गर्मजोशी नहीं दिखाई.

इधर, जब रामविलास पासवान हर जगह अपने उम्मीदवारों की घोषणा करने लगे तो लालू प्रसाद ने नाराजगी भी जताई. जानकार बताते हैं कि जेल जाने से पहले लालू प्रसाद ने रामविलास पासवान से साफ कर दिया कि पहले की शर्तों पर अब गठबंधन की उम्मीद नहीं रखें. बहुत हुआ तो राजद लोजपा को पांच से छह सीटों का ऑफर कर सकती है. राजद के बड़े नेता अब जुगत में हैं कि सीट बांटकर हारने से अच्छा है कि सीट लड़कर हारा जाए या जीता जाए. राजद के सूत्र बताते हैं कि रामविलास पासवान अपने पुत्र चिराग पासवान के लिए किसी भी हद तक जाकर समझौता राजद के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हाजीपुर में जीत के लिए उन्हें

जब रामविलास पासवान हर जगह अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहे थे तो लालू ने नाराजगी जताई. जानकार बताते हैं कि जेल जाने से पहले लालू ने रामविलास पासवान से साफ कहा कि पहले की शर्तों पर अब गठबंधन की उम्मीद न रखें. बहुत हुआ तो राजद लोजपा को पांच से छह सीटों का ऑफर दे सकती है.

हर हाल में लालू प्रसाद का साथ चाहिए. जहां तक इस गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने का सवाल है, तो लालू और रामविलास दोनों यह तहेदिल से चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, पर यह गठबंधन भी कई तरह के बंधनों में फंस कर रहा गया है.

कांग्रेस में लालू के साथ गठबंधन को लेकर तीन धाराएं बह रही हैं. पहली धारा का नेतृत्व सोनिया गांधी करती है. सोनिया की राय है कि लालू प्रसाद हमेशा भरोसे के साथी रहे हैं और बिहार में आज भी उनका व्यापक आधार है, इसलिए राजद से तालमेल में ही भलाई है. दूसरी धारा का नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं और राहुल की राय है कि बिहार में रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के साथ कोई तालमेल बैठाया जाए. दागी होने के कारण लालू से दूर ही रहा जाए तो बेहतर होगा. इधर, चारा घोटाले में नीतीश कुमार का नाम आने और उनके जेल जाने से इस धारा के लोग दुविधा में फंस गए हैं. कांग्रेस में एंटोनी के नेतृत्व में जो तीसरी धारा है, उसका मानना है कि बिहार में कांग्रेस को अकेले ही चुनाव मैदान में उतरना चाहिए. इसके पीछे तर्क यह है कि गठबंधन की स्थिति में भी कांग्रेस को चार से पांच सीटें ही मिलेगी, इसलिए क्यों ना अकेले ही सभी सीटों पर उतरा जाए और संगठन को मजबूत किया जाए. चुनाव के बाद वैसे भी सांप्रदियकता के खिलाफ मुलायम और मायावती की तरह लालू व नीतीश भी कांग्रेस को बाहर या भीतर से समर्थन करने के लिए बाध्य होंगे. इधर, नीतीश कुमार का मानना है कि अगर कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो पाता है, तो फिर माले को छोड़कर शेष वाम दलों के साथ चुनाव में उतरा जाए. जदयू का एक तबका लोजपा को भी इसमें शामिल कराने की पैरवी कर रहा है. भाजपा का हौसला तो इन दिनों उफान पर है. भाजपा को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के बाद पूरा बिहार भाजपामय हो जाएगा.

इस रैली में जदयू के कम से कम छह सांसदों के भाजपा में शामिल होने की संभावना है. चर्चा है कि अगर बात बन गई तो इसी रैली में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए का हिस्सा बन सकती है. हालांकि भाजपा का एक तबका उपेंद्र कुशवाहा को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं है. यह तबका चाहता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का भाजपा में विलय हो जाए. यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा ने गठबंधन को लेकर अपने सारे विकल्प खुले रखे हैं. वह अब हर जगह कह रहे हैं कि जो भी दल नीतीश को हराने की हैसियत रखेगा, हम उससे गठबंधन कर सकते हैं. लालू के जेल जाने पर उपेंद्र कुशवाहा ने दुख का भी इजहार किया था. राजद में भी एक खेमा ऐसा है, जो चाहता है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से तालमेल की स्थिति बन जाए, लेकिन इसकी संभावना तब ज्यादा बनेगी, जब लोजपा और राजद का गठबंधन नहीं होगा. देखा जाए तो हर दल गठबंधन को लेकर एक किसी न किसी तरह से बंधन में बंधा दिखता है. नए राजनीतिक हालात ने उनकी उलझनों को बढ़ा दिया है. अब देखना यह है कि तालमेल की यह गाड़ी कैसे और कब अपने स्टेशन तक पहुंचती है.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय मामला

मर्ज़ी चली केंद्र सरकार की

सुनील सौरभ

वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया था. तब तमाम सियासी दलों तथा नेताओं ने इसका स्वागत किया था, लेकिन जब इसके लिए केंद्र सरकार की पहली पसंद तथागत की ज्ञान भूमि तथा भगवान विष्णु की नगरी गया को चयन किया गया, तब राजनीति शुरू हो गई. बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने ही गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर विरोध कर दिया. इसके लिए मुख्यमंत्री की पहली पसंद पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय मोतिहारी था. वहां जमीन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने आनन-फानन में जिला प्रशासन से रिर्पोट भी मंगा ली, लेकिन केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने गया के पंचानपुर के पास रक्षा मंत्रालय के सैकड़ों एकड़ बेकार पड़ी भूमि को केंद्रीय विश्वविद्यालय को देने के लिए अनुरोध किया. इसे रक्षा मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद भी मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय बनेगा तो मोतिहारी में ही. इसके बाद केंद्र सरकार ने एक रणनीति के तहत दोनों स्थानों पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर विवाद को रोका. राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद 2009 में बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय का काम शुरू कर दिया गया. इस वर्ष अप्रैल में गया शहर के न्यू एरिया नूतन नगर में एक बड़े कैंपस स्थित बहुमंजिले भवन में केंद्रीय विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई और गत अगस्त माह के मध्य से यहां पढ़ाई भी शुरू हो गई है. बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी प्रतीश कुमार दास ने बताया कि गया में स्थापित बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में फिलहाल चार यूजी कोर्स बीए-बीएड, बीएससी-बीएड, बीए-एलएलबी, बीएससी-एलएलबी तथा स्नातकोत्तर में चार विषयों हिंदी, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र में पढ़ाई आरंभ की गई है. इन सभी विषयों में कुल 140 छात्र-छात्राओं का नामांकन किया गया है. इसके लिए 30 फैकल्टी तथा 16 शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की पदस्थापना की गई है. उन्होंने बताया कि बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के पटना कैंपस में यूजी के 12 कोर्स तथा स्नातकोत्तर के 12 विषयों की पढ़ाई हो रही है. सुविधा के अनुसार गया में धीरे-धीरे बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को शिफ्ट किया जाएगा. गया कैम्पस में समृद्ध लाईब्रेरी, लेबोरेटरी तथा आधुनिक कम्प्यूटर लैब बनाया गया है. बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय का गया में जब गत अप्रैल को उद्घाटन हुआ था तो बिहार सरकार का कोई भी मंत्री या विधायक या सरकारी पदाधिकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे. यहां तक कि तब सत्ता में साथ रहे भाजपा समेत जदयू का कोई भी जिला स्तर का नेता इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था. तब तक भी लोगों को विश्वास नहीं था कि गया में बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई होगी, क्योंकि उद्घाटन समारोह का एक तरह से बिहार सरकार ने बहिष्कार किया था. उस समय इसका उद्घाटन सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी के लेफ्टिनेंट जनरल जीएस विष्ट ने किया था. मगध विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉ. चक्रधर प्रसाद सिंह विशिष्ट अतिथि थे. उद्घाटन समारोह में बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. जनक पांडेय ने बताया था कि यह विश्वविद्यालय तीन चरणों से होता हुआ गया तक पहुंचा है. सबसे पहले 2009 में पटना के हिन्दी भवन में यह विश्वविद्यालय खुला, फिर बीआईटी के परिसर में और अब गया में आ गया है. कुलपति ने बताया कि गया में आये केन्द्रीय विश्वविद्यालय को लाने में पूर्व मानव संसाधन मंत्री अर्जुन सिंह का प्रारंभिक योगदान रहा तथा वर्तमान केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री कपिल सिब्बल और रक्षा मंत्री एके एंटोनी की भूमिका अभूतपूर्व रही. कुलपति ने कहा कि कोई भी विश्वविद्यालय जब तक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से नहीं जुड़ेगा वह किसी भी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाएगा. उन्होंने लोगों से क्षेत्रीय स्तर से उठने की बात की और इसे बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य बताया. अब जबकि बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो गई है तो केन्द्र सरकार को इसके लिए बधाई देते हुए गया में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आंदोलन से जुड़े बुद्धिजीवियों ने कहा है कि केन्द्र सरकार का सही निर्णय है. ■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

आम आदमी पार्टी ने अनशन किया

सीतामढ़ी में वर्षों से मृतप्राय बनी लक्ष्मणा नदी सीतामढ़ी ज़िले के सामाजिक कार्यकर्ता व राजनीतिक दल के नेताओं के लिए राजनीति का केंद्र बन गया है. प्रशासनिक उदासीनता एवं जनप्रतिनिधियों की लापरवाही का आलम यह है कि लगातार हो रहे धरना–प्रदर्शन के बाद भी नदी की धारा में जल प्रवाह शुरू कराने की दिशा में अब तक प्रयास नहीं किया गया. हालांकि इस मामले में विधान परिषद व विधान सभा के सत्र में भी कुछ प्रतिनिधियों द्वारा पहल की गई है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया जा सका है. दुर्गा पूजा का समय करीब आने के साथ ही जहां एक ओर प्रतिमा विसर्जन की समस्या गंभीर बनी है, वहीं दूसरी ओर आस्था का पर्व छठ को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है. इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक ओम प्रकाश नदी किनारे आमरण अनशन करने जा रहे हैं. कार्यक्रम में पार्टी के उत्तर बिहार क्षेत्रीय संयोजक शत्रुघ्न साहू, हरि नारायण प्रसाद, धनीराम भगत, जीवनाथ साफी समेत दर्जनों लोग थे.

अनुशंसा पर मिलेगा टिकट : अध्यक्ष

सीतामढ़ी शहर स्थित कांग्रेस कार्यालय ललित आश्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि अब बिचौलियों का प्रभाव पार्टी से खत्म हो गया है. चुनाव का समय आने पर बिचौलियों की मदद से टिकट पाने की लालसा रखने वालों का अरमान कभी पूरा होने वाला नहीं है. जिलाध्यक्ष विमल शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान शिवहर व सीतामढ़ी जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि पार्टी का टिकट अब प्रखंड व जिलाध्यक्ष की अनुशंसा पर ही किसी को मिलेगा. जनता भी कांग्रेस के कार्यों के आधार पर ही पार्टी प्रत्याशी को अपना मत देगी. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पार्टी के बिहार प्रभारी किशोरी लाल शर्मा, परेश धनानी, डॉ. मदन मोहन झा, अखिलेश प्रसाद सिंह, एआईसीसी सदस्य मनीष सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सरवत जहां फातमी, डॉ. भुवनेश्वरी मिश्र, सत्येंद्र तिवारी, परवेज आलम अंसारी, मधुरेंद्र कुमार सिंह, राम कृपाल शर्मा, अमित कुमार टुन्ना, सीताराम झा, राम बली महतो, विजेंद्र यादव, मो असद समेत अन्य थे. **– ब्रजेश**

वेतन पर रोक

चतरा जिला में मतदाता पुर्ननिरीक्षण का काम चल रहा है, लेकिन बीएलओ की सुस्ती के कारण मतदाताओं को परेशानी हो रही है. मतदाताओं को हो रही परेशानी और काम की धीमी गति को देखते हुए चतरा उपायुक्त ने बीएलओ के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है. उपायुक्त द्वारा सभी बीएलओ को अलग–अलग बुलाकर काम में तेजी लाने के तरीके बताये जा रहे है. **– अमरेंद्र सिंह**

इंदिरा आवास योजना में धांधली

शशि शेखर सिंह

सरकार इंदिरा आवास लाभार्थियों को शिविर के माध्यम से बैंक का प्रविष्ट खाता उपलब्ध करा रही है, ताकि लाभार्थी दलाल व बिचौलियों से दूर रहें, लेकिन सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में बिचौलियों का बोलबाला है. पैसे के बल पर बिचौलियों ने पदाधिकारियों की मिलीभगत से इंदिरा आवास मिल चुके लाभार्थियों को दुबारा इंदिरा आवास का लाभ दिला दिया. इतना ही नहीं सरकारी सेवा में कार्य कर रहे लोगों को भी इसका लाभ दिला दिया गया. और तो और कई लाभार्थियों की पहचान को बदलकर इंदिरा आवास का लाभ दिलाने का मामला भी उजागर हुआ है. इतना ही नहीं एक ही घर के दो लोगों को इंदिरा आवास आवंटित कर दिया गया है. अविवाहित लोगों को भी आवास आवंटित कर दिया गया है. उन परिवारों को भी जो सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और पहले से ही उनके पास बड़े मकान हैं. यह हाल है अलीगंज प्रखंड के मिर्जागंज पंचायत का. पिछले दिनों समाजसेवी नवल किशोर महतो ने जिलाधिकारी के जनता दरबार में आवेदन देकर जांच कराने की मांग की है. उक्त सूची में कईयों को दोबारा इंदिरा आवास दिया गया है. महतो ने कहा कि बीडीओ, प्रखंडकर्मी और पंचायत सचिव आदि ने बिचौलियों से मिलकर सूची की फेरबदल की है और लूट–खसोट कर रहे हैं. जिले में इंदिरा आवास के अलावा अन्य योजनाओं में भी बिचौलियों का बोलबाला साफ दिखता है.

दोबारा लाभ लेने वालों की सूची...

1. सवो देवी, पति बालेश्वर रविदास, ग्राम मिर्जागंज पूर्व में मिला 1997–98, वर्तमान में 2013–14.
2. रघु पासवान, पिता ब्रह्मदेव पासवान, ग्राम मिर्जागंज पूर्व मे मिला 1997–98, वर्तमान में 2013–14.
3. सहोद्री देवी, पति बासो मांझी, ग्राम मिर्जागंज पूर्व में मिला 2007–08, वर्तमान में 2013–14.
4. मालती देवी, पति रामजतन पासवान, ग्राम दिघौत वर्ष उपलब्ध नहीं.
5. सुलो देवी, पति नरेश चौधरी, ग्राम मिर्जागंज पूर्व में मिला 1997–98, वर्तमान में 2013–14.
6. शिवनंदन चौधरी, पिता छोटू चौधरी, ग्राम मिर्जागंज पूर्व में मिला 1997–98, वर्तमान में 2013–14.
7. कौशल्या देवी, पति ब्रह्मदेव पासवान, ग्राम मिर्जागंज पूर्व में मिला 1997–98, वर्तमान में 2013–14

दो भाईयों को भी आवास मिला

1. श्रवण कुमार पासवान, पिता जर्नादन पासवान
2. राम विलास पासवान, पिता जर्नादन पासवान

मिर्जागंज गांव की रेशमा देवी और उनके पति शिवसागर चौधरी को भी अलग–अलग इंदिरा आवास आवंटित किया गया है. शिवसागर चौधरी ने नाम बदलकर छोटू चौधरी के नाम पर आवास का लाभ लिया. जिलाधिकारी से उनके नाम पर भी की गई अनियमितता के जांच की मांग की गई है. सूत्र बताते हैं कि लूट खसोट का यह खेल मिर्जागंज पंचायत के अलावा कई और पंचायतों में भी चल रहा है. प्रखंड विकास पदाधिकारी मीर सलाहुद्दीन ने बताया कि दोबारा किसी को लाभ नहीं दिया गया है और अगर गड़बड़ी पाई जाती है, तो दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी

जदयू पाठशाला में बवाल आपस में भिड़े कार्यकर्ता

वाल्मीकि कुमार

बिहार में गठबंधन की राजनीति पर लगी विराम के बाद विश्वासघात के आरोपों का दौर शुरू है. कुछ माह पूर्व तक एक दूसरे के कारगुजारियों में हामी भरने वाली भाजपा एवं जदयू अब खुलकर दो-दो हाथ करने को तैयार हैं. इस कड़ी में कभी भाजपा तो कभी जदयू सम्मेलन का आयोजन कर अपने-अपने कार्यकर्ताओं को राजनीति का पाठ पढ़ाने में लगी हैं.

मंचासीन मंत्री, सांसद व विधायक

मंच पर भिड़े पार्टी कार्यकर्ता

गुस्से में कुर्सी उठाये कार्यकर्ता

सीतामढ़ी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन यानी पार्टी की पाठशाला में बिहार जदयू के गुरू वशिष्ठ की अनुपस्थिति ने तो पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक के अंतर्मन को सामने लाकर रख दिया है. पार्टी भले ही आगामी लोकसभा चुनाव में अपने पुराने यार को मात देने को हुंकार भर रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि अब पार्टी के संभावित प्रत्याशियों ने इसे अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बना लिया है. सम्मेलन स्थल पर सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र के एक पूर्व सांसद के समर्थकों का वर्तमान सांसद समर्थकों के साथ मंच पर ही हाथापाई तक हो गई. बताते चलें कि सीतामढ़ी जिला मुख्यालय डुमरा स्थित परित्यक्त हवाई अड्डा मैदान में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. उमस भरी चिलचिलाती धूप के बाद भी जिले के विभिन्न प्रखंडों से हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं का समूह कार्यक्रम में पहुंचे. पुरूषों के अलावा भारी संख्या में ग्रामीण महिलाओं का भी यहां आना हुआ. कारण कि बताया गया था कि सम्मेलन के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह, आरसीपी सिन्हा, दामोदर रावत, रंजन यादव, जगदीश शर्मा, अरुण माझी व ललन सर्राफ समेत दर्जनों नेता कार्यकर्ताओं को चुनावी घुट्टी पिलाने आ रहे हैं.

कार्यक्रम स्थल पर सुख-सुविधाओं का सपना संजोये कार्यकर्ता पहुंचे और वृहद पार्टी पाठशाला के पंडाल में अपना स्थान लेकर चुनावी गुरू जी का इंतजार करने लगे, लेकिन कतिपय कारणों से उक्त में से एक भी बड़े नेता नहीं आ सके. निर्धारित समय से तकरीबन एक घंटा बाद मंच पर स्थानीय के साथ गिने-चुने बाहरी जदयू नेताओं का आगमन हुआ. इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की परेशानियों से बेखबर जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद की अध्यक्षता में विधिवत सम्मेलन का श्रीगणेश किया गया. जिला उपाध्यक्ष अरुण कुमार गोप संचालन का कमान थामते हुए कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाया जा रहा था. जैसे ही मो. शफी अहमद का संबोधन शुरू हुआ, तभी स्थानीय सांसद अर्जुन राय के समर्थन में नारेबाजी का कमान थामने वाले छात्र जदयू नेता आनंद बिहारी सिंह का काफिला मंच के पास पहुंच कर पुन: पुराने अंदाज में नारेबाजी शुरू कर दी. बार-बार उनकी ऐसी हरकतों से तंग आ चुके पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता जहां अपनी जुबान को समेट कर चुप्पी साधे रहे. वहीं तमाशा बन रहे माहौल से खफा कार्यकर्ताओं ने देखते ही देखते तेवर कड़ा करना शुरू कर दिया. इसी बीच छात्र नेता बिहारी मंच पर पहुंच गए, जहां पिछली कतार में बैठे पूर्व सांसद नवल किशोर राय के करीबी माने जाने वाले पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन कुमार सिंह व युवा जदयू कार्यकर्ता अमित सहाय समेत अन्य से तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई. बात इतनी बढ़ गई कि मंच पर ही हाथापाई तक होने लगी. कार्यकर्ताओं ने संयम का घेरा तोड़ कर पंडाल में कुर्सी तक उठा ली और जोरदार अंदाज में कार्यक्रम स्थगित करने की मांग करने लगे. कार्यकर्ताओं का कहना था कि सम्मेलन में नेता की बातों को सुनने आए थे.

अगर इस समय कोई पार्टी कार्यकर्ता किसी खास नेता के पक्ष में ऐसा माहौल बनाने का प्रयास करेगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा. बात बिगड़ती देख राज्य परिषद सदस्य उमेशचंद्र झा, बेलसंड विधायक सुनीता सिंह चौहान के पति राणा रंधीर सिंह चौहान समेत अन्य ने मामले को शांत कराया. इससे पूर्व ही आनंद बिहारी ने अपने संबोधन में मौजूद पार्टी नेताओं को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं को कार्यकर्ता की बात को सुन कर मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करना होगा. अन्यथा कार्यकर्ताओं की भावना की अनदेखी का खामियाजा भुगतने को तैयार रहना होगा. कुल मिला कर वे मंच से अपनी मजबूती का अहसास पार्टी नेता से लेकर कार्यकर्ता तक को कराने का हर संभव प्रयास करते रहे. उहापोह के माहौल में बैठे कार्यकर्ताओं से मुखातिब विधान पार्षद रुदल राय ने मुख्यमंत्री बनने से पूर्व नीतीश कुमार द्वारा किये गये वादों पर चर्चा शुरू की. कहा कि सूबे की पिछली सरकारों ने गरीब व दलितों की लाश पर राजनीति करने का काम किया, जबकि नीतीश सरकार ने सभी को समान अधिकार देने का काम किया है. सूचना प्राद्यौगिकी मंत्री शाहिद अली खान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूबे की तरक्की के लिए हर संभव प्रयास किया है. लाठी में तेल पिलाने की बजाये अब लोगों ने कलम में स्याही भरना शुरू कर दिया है.

कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र प्रसाद सिंह, मोहन कुमार सिंह, उपाध्यक्ष भरत प्रसाद, अनिल कुमार सिंह, उमेशचंद्र झा, प्रो. अमर सिंह, किरण गुप्ता, महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष शोभा गुप्ता, आरती प्रधान, रमेश कुमार, मो जुनैद, हेमराज राम, युवा जदयू के निवर्तमान अध्यक्ष सादाब अहमद खान, पंकज कुमार, राम स्नेही पांडेय, मो जियाउद्दीन खां एवं शंकर बैठा समेत अन्य थे. प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति पर कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं का गुस्सा पार्टी नेताओं के प्रति साफ झलक रहा था. दिल्ली की सत्ता पर भाजपा के नरेंद्र मोदी को काबिज होने से रोकने का दंभ भरने वाली जदयू के जिला पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उत्पन्न तनाव अब दिशा बदलता प्रतीत होने लगा है.

मतलब साफ है कि चुनाव में हितैशी प्रत्याशी के लिए कार्यकर्ता किस हद तक जा सकते हैं. वैसे सूखते हलक से परेशान रहे सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता जिस प्रकार पंडाल से पानी-पानी चिललाते रहे और अंतत: अपनी कुर्सी छोड़ निकल पड़े. अगर यही आलम रहा तो जिले में जदयू का चुनावी नौका मिशन 2014 को पूरा करने से पूर्व ही आपसी कलह के गर्त में समा जाएगा. वैसे चुनाव का समय अभी कुछ दूर है, लेकिन जदयू की आहूत पाठशाला ने साफ कर दिया है कि सम्मेलन को अब पार्टी के वसूलों से नही, बल्कि संभावित प्रत्याशियों से रह गया है. कार्यक्रम के दौरान मचे धमाल को भी इसी नजरिये से देखा जाने लगा है. युवा जदयू के पूर्व जिला महासचिव ठाकुर चंदन कुमार सिंह ने तो प्रदेश नेतृत्व से धमाल मचाने वाले कार्यकर्ता पर अनुशासनिक कार्रवाई तक की मांग की है. वैसे कुछ लोग इसे पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा भी दबी जुबान से मान रहे है.■

feedback@chauthiduniya.com

मोतिहारी

केंद्रीय विश्वविद्यालय आखिर कब बनेगा?

इंतेजारुल हक़

पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में प्रस्तावित केंद्रीय विश्व विद्यालय खुलने में देर होने से मामला एक बार फिर तुल पकड़ने लगा है. केंद्र सरकार की दोहरी नीति व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की चुप्पी के कारण लोगों में आक्रोश दिखने लगा है और सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने की योजना बन गई है. विधेयक अभी भी पारित नहीं हुआ और घोषणा को 15 माह गुजर जाने के बाद भी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी धीमी है. पिछले दिनों चंपारण विकास संघर्ष मोर्चा के बैनर तले स्थानीय लोगों की एक बैठक हुई. राय सुदेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में आंदोलन को और धारदार बनाने का संकल्प लिया गया. बताते चलें कि मोतिहारी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई थी. इसके बाद ही जिला प्रशासन द्वारा भूमि चिन्हित कर ली गई तथा राजस्व कर्मचारी द्वारा भूमि का नजरी नक्शा तैयार कर अंचलाधिकारी के माध्यम से जिला प्रशासन को

प्रस्ताव उपलब्ध करा दिया गया. इसके बावजूद किसानों को उनकी भूमि का मूल्य भुगतान करने की प्रक्रिया बाधित है. बैठक में चंपारण के सांसदों व राजनेताओं द्वारा उचित पहल नहीं किये जाने पर खेद जताया गया और उनकी निंदा की गई. बैठक में मोर्चा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए युवा मोर्चा गठित की गई है, जिसमें चुन्नू मिश्रा को अध्यक्ष तथा कृष्णा कश्यप को प्रधान महासचिव बनाया गया.

बैठक में पूर्व सांसद ब्रह्मदेव राम शास्त्री, कुमार शिव शंकर, बजरंगी नारायण ठाकुर, अरुण यादव, अमरेंद्र सिंह, रत्नेश्वरी शर्मा, अब्दुल हमीद कैप्टन, सुरेश साहनी, डॉ. शंभू शरण सिंह, साजिद रजा, बबन कुशवाहा, ब्रजेश श्रीवास्तव, हरेंद्र कुमार पंडित, हृदयनारायण झा, शिव प्रसाद, पंकज द्विवेदी, प्रभाष प्रताप सिंह, अशोक जायसवाल, अरुण कुमार, सहदेव प्रसाद, पवन कुमार सिंह, निलेश कुमार मिश्र, राज कुमार सिंह, संजीव सिंह, मो. रोजराही, आलोक चंद्र, भरत कुमार दास, रामवचन सिंह, डॉ. उमेश चंद्र आदि प्रमुख थे. ■

feedback@chauthiduniya.com

बेगूसराय में जदयू का घटता जनाधार

पंकज कुमार/जनार्दन दास

पिछले दिनों बेगूसराय में जदयू का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ. इस सम्मेलन से कई प्रश्न उभर कर सामने आए. जदयू का घटता जनाधार और क्षीण होती लोकप्रियता दिखी. मंत्री, विधान पार्षद एवं कई नेताओं का सम्मेलन में भाग नहीं लेना चर्चा का विषय बना रहा. जिलाध्यक्ष बनने के महीनों बाद जिला कार्यसमिति का गठन नहीं किए जाने से प्रमोद कुमार शर्मा की पार्टी पर पकड़ कमजोर होती जा रही है. वहीं जिले के प्रमुख विधायक बोगो सिंह को मंच पर पीछे की कुर्सी पर बैठाया जाना बना चर्चा का विषय बना हुआ है. स्थिती यह हो गई कि सम्मेलन प्रारम्भ होने से पूर्व ही प्रखंड से लाए गए कार्यकर्ता वापस लौटना प्रारंभ कर दिए थे.

गांधी स्टेडियम में आयोजित जदयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में सूबे के मंत्री वृषिण पटेल, भीम सिंह, गौतम सिंह, सांसद मोनाजिर हसन, विधायक नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, पार्टी नेता राजवंशी महतो, नित्यानंद सिंह, जवाहरलाल भारद्वाज, जिला प्रवक्ता एवं महापौर संजय कुमार, नरेन्द्र कुमार धनकू सहित अन्य नेताओं ने लगभग एक जैसे संबोधन में भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए नीतीश कुमार की प्रशंसा का पुल बांधा. वृषिण पटेल ने तो नीतीश की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री बनने लायक बताया. सभी ने पार्टी संगठन को मजबूत बनाने एवं लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया. सम्मेलन में जिले के साहेबपुरकमाल की विधायक एवं समाज कल्याण मंत्री परबीन अमानुल्लाह तथा विधान पार्षद रूदल राय के भाग नहीं लेने पर कार्यकर्ताओं में उदासी देखी गई. कार्यकर्ता आपस में बातचीत करते हुए तरह-तरह के कयास लगा रहे थे. वहीं पूर्व जिलाध्यक्ष भोलाकांत झा की अनुपस्थिति एवं नाराजगी की चर्चा हो रही थी. पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रतन सिंह का सम्मेलन से अनुपस्थित रहना भी खास संकेत दे गया. दूसरी ओर जिलाध्यक्ष मनोनीत होने के महीनों बाद प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा जिला कार्यकारिणी समिति का गठन नहीं, किए जाने से पार्टी नेताओं में असंतोष व्याप्त है, जो पार्टी के सांगठनिक सेहत के लिए शुभ नहीं कहा जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

» एक नज़र «

चुनावी तैयारी में जुटी बसपा

सीतामढ़ी के लोकसभा चुनाव का समय करीब आने के साथ ही अन्य दलों के साथ बसपा कार्यकर्ताओं ने भी चुनावी गतिविधि को बढ़ा दिया है. सीतामढ़ी जिले के विभिन्न स्थानों पर पार्टी के घोषित प्रत्याशी डॉ. महेश कुमार ने मतदाताओं की गोलबंदी शुरू कर दी है. शहर से लेकर गांव की गलियों तक पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने को लेकर अभियान जारी है. पिछले दिनों शहर के रेडक्रॉस भवन व नानपुर के रायपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डॉ. कुमार ने कहा कि वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दलों के संभावित प्रत्याशियों द्वारा झूठी घोषणाओं का अंबार लगाया जा रहा है, लेकिन अब बिहार की जनता उनकी झांसे में आने वाली नहीं है. आगामी लोकसभा चुनाव में बसपा के पक्ष में लोग एकजुटता के साथ मतदान करने को तैयार है. कार्यक्रम में राम एकबाल साहपूर्व सांसद घनश्याम चंद्र खरवार, लालबाबू साह, मुनी राम, हरि नारायण साह, रामाश्रय राम, जिला प्रभारी अशोक मुखिया, रामबाबू कुमार व शिव शंकर भगत समेत अन्य थे. *– ब्रजेश*

भाकपा की जनसभा

सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर कार्यालय परिसर में सीपीआईएम की केंद्रीय कमेटी की सदस्य व पूर्व सांसद सुभाषिनी अली सहगल ने कहा कि पार्टी गरीबों की लड़ाई लड़ने को तैयार है. उन्होंने लोगों से लाल झंडे के तले एकजुट होकर संघर्ष तेज करने की अपील की. कहा कि वर्तमान में लाल झंडे को छोड़ देश की सभी पार्टियां जाति-धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती हैं. सामंतों के इशारे पर काम करने वालों को पहचानना जरूरी है. चुनाव पर चर्चा करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव की तिथि करीब आते ही नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी को चुनावी अखाड़ा का पहलवान बताया जाने लगा है, जबकि उक्त दोनों ही सामंतों के पोषक हैं. कार्यक्रम में किसान सभा के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने सरकार से किसानों का ऋण माफ करने एवं 12 सौ रुपये प्रति एकड़ की दर से बर्बाद फसल का मुआवजा देने की मांग की. भाकपा अंचल सचिव देवेंद्र प्रसाद यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सांसद सहगल को चंदा स्वरुप 25 हजार, 51 रुपये की थैली दी गई. मौके पर जनवादी महिला समिति की प्रदेश सचिव रामपरी देवी, दिगंबर ठाकुर, महेंद्र पासवान, शंकर पासवान, विनय महतो, हरि मंडल, राम जीवन महतो, शुभ नारायण साह, नेमी महतो, सुनीता देवी, रीता देवी रेणु देवी समेत सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे. *–विभा*

प्रशिक्षण का आयोजन

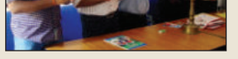

पुपरी में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बलहा मधुसूदन कृषि विज्ञान केंद्र में एक दिवसीय पशुपालन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. उद्घाटन केंद्र समन्वयक डॉ. राम ईश्वर प्रसाद व वीरबैक एनिमल हेल्थ इंडिया प्राईवेट लिमिटेड मुंबई के क्षेत्रीय प्रबंधक पीएन पांडेय ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया. प्रशिक्षण में शामिल कुल 65 किसानों को केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. दीपक सिंह, डॉ. सच्चिदानंद प्रसाद, डॉ. मनोहर पंजिकार ने किसानों को समुचित जानकारी दी. *– गोविंद कुमार*

महिला खिलाड़ियों का चयन

शिवहर जिला मुख्यालय स्थित नवाब उच्च विद्यालय में जिला स्तरीय महिला खिलाड़ियों का चयन किया गया. चयन प्रतियोगिता का उद्घाटन डीपीओ मनोज कुमार रजक ने किया. कबड्डी के लिए श्रुति कुमारी, किरण कुमारी, प्रतिभा कुमारी, कौशल्या कुमारी, नरेशी कुमारी, कंचन कुमारी, प्रतिमा कुमारी, रागिनी कुमारी का चयन किया गया. बैडमिंटन के लिए रिया एवं प्रियंका का चयन किया गया. नोडल पदाधिकारी अनिल कुमार सिंह के संचालन में चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. *–शशांक*

कहानी संग्रह का लोकार्पण

कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद सिंह के शोषण व भ्रष्टाचार के खिलाफ हाल ही में प्रकाशित कहानी संग्रह का लोकार्पण अनोखे ढंग से हुआ. लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों व साहित्यप्रेमियों का काफिला हाथी, घोड़े, बैंड-बाजे के साथ दानापुर बस स्टैंड से पटना के कारगिल चौक तक मार्च किया. मार्च का आयोजन शिवम क्लासेज की तरफ से किया गया था. मार्च का नेतृत्व शिवम क्लासेज के निदेशक व महंत हनुमान शरण कॉलेज के प्राचार्य डॉ. बिमल नारायण आर्य व कथाकार डॉ. लालजी प्रसाद ने संयुक्त रूप से किया. काफिले के कारगिल चौक पहुंचने के बाद प्राचार्य डॉ. विमल नारायण आर्य, डॉ. लालजी प्रसाद एवं उपस्थित लोगों ने किताबों का लोकार्पण किया. अपने 38वें पुस्तक लोकार्पण के मौके पर डॉ. लालजी प्रसाद ने कहा कि अभावों में रहने के बावजूद भी एक साहित्यकार अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति के माध्यम से समाज को बदल सकता है. उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में आतंकवाद के खतरों से सावधान करती कहानी स्वर्ग का कर्फ्यू और सांप्रदायिक एकता से लबरेज कहानी रात-रानी काफी महत्वपूर्ण है.

रालोसपा की बैठक

पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक बैठक की. बैठक में रालोसपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र सिंह सहित पार्टी के कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे. बैठक के दौरान अमरेंद्र सिंह ने सत्ता पक्ष पर जमकर निशाना साधा. अपने संबोधन के दौरान सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार लूट और भ्रष्टाचार की सरकार हो गई है. उन्होंने कहा कि नीतीश के न्याय के साथ विकास का नारा फ्लॉप हो गया है. मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश बताएं कि आखिर कौन सी मजबूरी है कि वे अब-तक मंत्री मंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही नीतीश मंत्री मंडल का विस्तार करेंगे, जदयू में टूट पड़ना शुरू हो जाएगा. *– अमृता कुमारी*

एसडीओ जांच करेंगे

चतरा जिले के अनुमंडलाधिकारी सतीश चंद्र ने बताया कि जिले के सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के पास फर्जी कार्ड हैं. इसकी वजह से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है. उन्होंने बताया कि ऐसी शिकायत सभी प्रखंडों से मिल रहे हैं. साथ ही एसडीओ ने बताया कि कार्डधारियों की वास्तविक स्थिती का आंकड़ा जुटाया जा रहा है, इसके बाद मामले की जांच की जाएगी. *– अमरेंद्र सिंह*

समाहरणालय पर धरना प्रदर्शन

मोतिहारी जिला सरपंच संघ ने आज अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में समाहरणालय के समक्ष धरना दिया. धरना को संबोधित करते हुए संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला ने कहा कि सरपंचों पर झूठे मुकदमें किये जा रहे हैं और उन्हें कई तरह से परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है और अपने आलाधिकारियों के आदेश की अवहेलना खुलेआम थानेदार कर रहे है. धरना को प्रदेश प्रधान महासचिव राजेन्द्र सिंह, जिलाध्यक्ष राज कुमार उपाध्याय, लालबाबू, शंभू यादव, ब्रजकिशोर सिंह, बच्चा कुमार, नगीना कुमार, रमाशंकर, इलियास, कृष्णा मिश्रा, विश्वनाथ चौरसिया, मो. रइश नूरी, छतीश टंडन, रामनरेश तिवारी, जन्मेजय पटेल, मुंद्रिका सिंह, द्वारिका नाथ यादव, राजेंद्र सिंह, मो. अबुल हसन, आमोद कुमार निराला, विनोद प्रसाद एवं शम्भू यादव आदि ने संबोधित किया. *– इंतेजारुल हक*

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2012-13-14, RNI No. DELHIN/2009/30467

www.chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

14 अक्टूबर–20 अक्टूबर 2013

पूर्णिया के पूर्व विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में पिछले 12 वर्ष 3 महीने से जेल में बंद रहे पूर्व सांसद पप्पू यादव को हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपमुक्त कर दिया है. लंबी जेल अवधि को उन्होंने और उनके समर्थकों ने भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास से तुलना करते हुए उन्हें योद्धा के रूप में दिखाया है.

मंत्री-डीएम विवाद पर राजनीतिक रंग चढ़ा

बिहार के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह और गया ज़िले के पदाधिकारी बाला मुरूगन डी के बीच कथित रूप से हुए विवाद तथा प्रोटोकॉल का मामला राजनीतिक रूप ले चुका है. जदयू नेता जहां नरेंद्र सिंह के पक्ष में खड़े हो चुके हैं, वहीं भाजपा नेता जिला पदाधिकारी के पक्ष में खड़े होकर नरेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं.

सुनील सौरभ

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री से गया के जिले के पदाधिकारी बाला मुरूगन डी की शिकायत करते हुए कहा है कि उन्होंने ज़िला पदाधिकारी को सूखे की समीक्षा बैठक में सिर्फ़ प्रोटोकॉल का ध्यान दिलाया था. इस पूरे प्रकरण पर गया जिला पदाधिकारी और न ही ज़िला प्रशासन का कोई पदाधिकारी कुछ कहने को तैयार हैं. सत्ता से अलग होने के बाद ज़िला पदाधिकारी को सत्ता का भोपू कहने वाले भाजपा नेता उन्हें अब एक ईमानदार पदाधिकारी बता कर जिला पदाधिकारी बाला मुरूगन डी के पक्ष में खड़े हो गए हैं. पूरा मामला यह है कि पिछले 15 सितम्बर, 2013 को गया महानगर जदयू द्वारा आयोजित गया नगर विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के लिए राज्य के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह 14 सितंबर की शाम गया पहुंचे. वे रात्रि में सर्किट हाउस में ठहरे. सुबह जिला स्कूल के प्रांगण में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लेने के बाद कृषि मंत्री ने गया जिले में सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा के लिए समाहरणालय में बैठक रख दी. इस बैठक में जब कृषि मंत्री पहुंचे तो जिला पदाधिकारी बाला मुरूगन डी और उप विकास आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह पहले से सभाकक्ष के मंच पर बैठे थे. मंत्री के मंच पर पहुंचने पर कहा गया कि जिला पदाधिकारी ने उनका सम्मान नहीं किया और कुर्सी से उठने की जरूरत भी नहीं समझी.

बाला मुरूगन

इस पर मंत्री बैठक स्थगित कर पटना लौट गए. इस घटना के पीछे नरेंद्र सिंह द्वारा अपने किसी समर्थक के खनन पट्टा के संबंध में डीएम से खफा होने की बात कही जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन का कोई पदाधिकारी इस मामले पर कोई प्रमाण नहीं दे सका. मंत्री–डीएम के इस प्रकरण पर अखबारों में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के वरीय उपसमाहर्त्ता जिला भू–अर्जन पदाधिकारी प्रभात कुमार झा का यह बयान छपा कि एक ईमानदार अफसर को अपमानित करना उचित नहीं है, लेकिन यह विवाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंचा तो जिला पदाधिकारी बाला मुरूगन डी या जिला प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने से परहेज कर रहा है. इधर, नरेंद्र सिंह ने गया के जिला पदाधिकारी की शिकायत करते हुए कहा है कि सुखाड़ पर समीक्षा बैठक के दौरान डीएम का व्यवहार संवेदनहीन था. वह बेमन से बैठक में आए और जब मैं मंच पर पहुंचा तो डीएम पहले से कुर्सी पर बैठे हुए थे. उन्होंने सम्मान प्रदर्शन की भी जरूरत नहीं समझी. इसी पर मैंने डीएम को प्रोटोकॉल और रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस के बारे में समझाया. मंत्री ने बताया कि मंत्रियों और अन्य जन प्रतिनिधियों के साथ उन्हें किस तरह व्यवहार करना चाहिए. कृषि मंत्री ने मुख्यमंत्री को बताया कि गया जिला सूखाग्रस्त है, लेकिन डीएम इसके प्रति गंभीर नहीं है. वे बैठक से जल्दी जाने की जिद्द करने लगे, तब मैंने बैठक स्थगित करने की घोषणा कर दी. कृषि मंत्री ने बताया कि इससे पहले बाला मुरूगन डी से कभी बात–चीत भी नहीं हुई है. खनन पट्टा देने के लिए पैरवी की बात को उन्होंने सरासर गलत बताया. इस मामले को लेकर गया जिले के जदयू और भाजपा नेता आमने–सामने आ गए हैं. कृषि मंत्री की डीएम से विवाद की खबर आते ही गया जिला ग्रामीण जदयू के जिलाध्यक्ष अभय कुशवाहा की अध्यक्षता में एक अपात बैठक हुई, इस बैठक में वरीय उपसमाहर्त्ता के बयान को बेबुनियाद बताया गया और इसकी निंदा की गई. इस बैठक में गया महानगर जदयू अध्यक्ष राजू बर्णवाल, डॉ. अरविंद कुमार सिंह, धीरेंद्र कुमार मुन्ना, विनोद कुमार, शौकत अली, कुंडल वर्मा, कल्लू आर्य, मुनेश्वर सिंह, निर्भय सिंह, अभिमन्यू बौद्ध समेत अनेक नेता शामिल थे. वहीं दूसरी ओर गया नगर विधायक व पूर्व मंत्री डॉ. प्रेम कुमार ने इस मामले पर कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह द्वारा गया में पदस्थापित एक ईमानदार छवि वाले कर्तव्यनिष्ट जिला पदाधिकारी बाला मुरूगन डी को अपमानित किये जाने पर भाजपा उन्हें मंत्रीमंडल से बर्खास्त करने की मांग करती है. प्रेम कुमार ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह का रवैया हमेशा विवादों में रहा है. इसीलिए भाजपा मंत्रीमंडल से नरेंद्र सिंह को बर्खास्त करने की मांग करती है. इस पर गया महानगर भाजपा अध्यक्ष कंचन कुमार सिन्हा, महामंत्री संतोष कुमार, मंत्री दीपक पांडेय, प्रदेश भाजपा के दीपक कुमार चंद्रवंशी, अशोक सिंह, निकहत परवीन, राजनंदन गांधी, आदी समेत दर्जनों भाजपा नेता ने कृषि मंत्री के व्यवहार की निंदा की है. जहानाबाद के पूर्व सांसद रामाश्रय प्रसाद सिंह ने कहा है कि सुशासन में ईमानदार और कर्मठ अधिकारियों की पूछ नहीं है. गया के जिला पदाधिकारी पहले जहानाबाद में थे. वहां बाला मुरूगन डी ने गरीबों, महादलितों और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है. ऐसे पदाधिकारी को एक मंत्री द्वारा अपमानित किया जाना अपराध है. इस मंत्री को मंत्रीमंडल से हटाया जाए और अपमानित करने का मुकदमा चलाया जाए. इस विवाद का पटाक्षेप चाहे जिस रूप में हो, फिलहाल गया जिले की राजनीति इस मामले में गरम है. भाजपा–जदयू आमने–सामने है तो प्रशासनिक वर्ग कुछ भी टिप्पणी करने से परहेज कर रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

शिक्षक के ख़िलाफ़ साज़िश!

शिक्षा के मंदिर में कभी-कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिससे न केवल इस पवित्र पेशे पर दाग़ लगता है, बल्कि समाज यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आख़िर लड़कियां कहां सुरक्षित हैं.

सुरेंद्र कुमार

विनीता कुमारी

विवेकानंद

जुबैर अंसारी

पिछले दिनों नगर पंचायत वीरपुर स्थित मवि शालीवासा के प्रधान शिक्षक राम प्रसाद यादव पर विद्यालय के ही चौथी वर्ग की छात्रा रिया कुमारी ने छेड़खानी का आरोप लगाया. प्रधान शिक्षक इस घटना को साजिश का नतीजा बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सहायक शिक्षिका विनीता कुमारी साजिश की बातों को खारिज करती हैं. उनका कहना है कि मैं वर्ग चार की शिक्षिका हूं. इसी कक्षा की रिया ने मुझे लिखित चिट्ठी दी थी की प्रधान शिक्षक मेरे साथ छेड़खानी करते हैं. यह बात मैं विद्यालय में तकरीबन सभी शिक्षकों व शिक्षिकाओं को बता चुकी हूं, लेकिन ज्यादातर शिक्षकों का कहना है कि प्रधान शिक्षक यादव का चरित्र खराब नहीं है. हम व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानते हैं. उन्हें साजिश का शिकार बनाया गया है, जबकि दूसरी तरफ इस मामले को लेकर वीरपुर डीएसपी मनोज राम वर्तमान बलुआ थाना अध्यक्ष शंभुनाथ सिंह, विद्यालय की शिक्षिका मधु रानी व विनीता कुमारी के अलावा चालक नीक्कू सिंह पर व्यवहार न्यायालय, वीरपुर में प्रधान शिक्षक यादव द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया है. रिया कुमारी और नेहा कुमारी ने पुलिस को बताया कि वह हमारे साथ छेड़खानी करते हैं. छात्राओं के बयान पर पुलिस ने 224/013 225/013 एवं 226/013 दर्ज कर यादव को जेल भेज दिया, लेकिन बाद में कोर्ट में लड़की अपने बयान से बदल गई, तब यादव को जमानत पर रिहा कर दिया गया. उक्त मामले में नियोजित शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विवेकानंद दास का कहना है कि प्रधान शिक्षक राम प्रसाद यादव एक निहायत ही ईमानदार शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं. वह अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं और उनके चरित्र पर किसी तरह का दाग नहीं है. उस दिन की घटना पूरी तरह सुनियोजित थी, जो परत–दर–परत खुलने लगी है. साजिशकर्ता कोई भी हो वह बेनकाब हो कर रहेगा. विद्यालय के सहायक शिक्षक सुरेंद्र कुमार का कहना है कि वह उस दिन वहां मौजूद था. यह घटना पूरी तरह साजिश है, जबकि रूपकुमार का कहना है कि मात्र एक माह में हेडमास्टर के रूप में यादव जी यहां आए और शिक्षा से लेकर मध्याह्न भोजन तक के व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाए, इसीलिए वह साजिश का शिकार हो गये. हालांकि इस पूरे मामले में प्रधान शिक्षक को बेगुनाह बताया जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर लड़की ने शिक्षक पर आखिर क्यों छेडखानी का आरोप लगाया और फिर बाद में मुकर क्यों गई. ■

feedback@chauthiduniya.com

रक्सौल

जाम से जूझती अंतरराष्ट्रीय सीमा

राज कुमार

अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में अपनी पहचान बना चुका रक्सौल उदासीनता का शिकार है. शहर में जाम की समस्या सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी है. समस्या इतनी विकराल हो गई है कि आए दिन कोई न कोई सड़क दुर्घटना हो ही जाता है. जाम की वजह से पूरा शहर सुबह से शाम तक अस्त व्यस्त तो रहता ही है, अफरा–तफरी का माहौल भी बना रहता है, लेकिन विकराल हो रही समस्या के बावजूद प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा. जाम का मुख्य कारण सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमणकारियों का कब्जा है. भारत नेपाल की मुख्य सीमा होने के कारण यहां गाड़ियों की भीड़ हमेशा ही रहती है. अंतरराष्ट्रीय सीमा होने के बावजूद प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल ही लचर दिखाई देती है. क्षेत्र के लोग बताते हैं कि अगर मुख्य सड़क को प्रशासन वनवे कर दे तो थोड़ी राहत मिल सकती है. साथ ही यह भी कहते हैं कि नेपाल जाने वाली और नेपाल से आने वाली गाड़ियों के मार्ग को अलग–अलग कर दिया जाए तो भी बात बन सकती है, लेकिन सबसे पहले सड़क को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराना जरूरी होगा. हैरत की बात है कि भारत की इस महत्वपूर्ण सीमा पर गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था नहीं है. यह स्थिती तब है, जब इस शहर से सूबे को विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी विभागों से सलाना लगभग पांच सौ करोड़ की राजस्व कर की प्राप्ति होती है. केवल भारतीय सीमा शुल्क विभाग से ही दो सौ करोड़ का राजस्व मिलता है. स्थानीय लोग कहते हैं कि इस राजस्व का दस प्रतिशत भी अगर इस शहर पर खर्च किया गया होता तो इसकी सूरत ही बदल गई होती. ■

feedback@chauthiduniya.com

सहरसा

आशीर्वाद रैली में उमड़ा हुजूम

मनोज ठाकुर

feedback@chauthiduniya.com

युवा शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद पप्पू यादव ने खुद को अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला योद्धा कहा. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से विद्रोही रहा हूं और ऐसे ही मरूंगा. यादव 30 सितंबर को सहरसा के स्टेडियम में आयोजित आशीर्वाद रैली को संबोधित कर रहे थे. बताते चलें कि पूर्णिया के पूर्व विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में पिछले 12 वर्ष 3 महीने से जेल में बंद रहे पूर्व सांसद पप्पू यादव को हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आरोप मुक्त किया है और अपनी लम्बी जेल अवधि को उन्होंने और उनके समर्थकों ने भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास से तुलना करते हुए योद्धा के रूप में दिखाया है.

सहरसा स्टेडियम में आयोजित आशीर्वाद रैली में सहरसा जिला समेत मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, दरभंगा और मधुबनी सहित कई अन्य जिलों से उनके समर्थक पहुंचे थे. हाथी, घोड़ा, मोटर साइकिल और कारों की लम्बी कतार दिन भर ट्रैफिक जाम करती रही. बैंड पार्टी की धुन पर नाचते समर्थकों की भीड़ से स्टेडियम भर गया था.

अपार समर्थकों के हूजूम से गदगद यादव ने नीतीश कुमार, शरद यादव व नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कई सवाल खड़े किए. एक तरफ जहां उन्होंने नीतीश कुमार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया तो वहीं दूसरी तरफ शरद यादव को ढकोसला करने वाला नेता कहा. उन्होंने कहा कि खुद को विकासपुत्र और क्रांतिपुत्र कहने वाले नेता कहां हैं? यहां लोग भूख से मर रहे हैं और आप विकास का ढ़ोल पीट रहे हैं. सड़कें केन्द्र सरकार बना रही है और लोगों को सड़कें दिखा कर ठग आप रहे हैं. साथ ही यह भी कहा कि आम लोगों को सरकारी खैरात (अन्तोदय योजना, मिड डे मिल योजना, मनरेगा, अन्नपूर्णा योजना) पर जीने को मजबूर करने वाले नेता गरीबों के शुभचिंतक बन रहे हैं. वहीं नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा शासित गुजरात में गरीबी व छत्तीसगढ़ में नक्सली पैदा हो रहे हैं. इतना ही नहीं इन पर धर्म और मजहब के नाम पर समाज को बांटने का भी आरोप लगाया. वहीं पूर्व सांसद व उनकी पत्नी रंजीता रंजन ने युवाओं और महिलाओं से शराबबंदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई शुरू करने की अपील करते हुए सरकार को क्षेत्र की बदहाली का कुसूरवार भी ठहराया. रंजीता ने कहा कि कोसी व सीमांचल का इलाका कोसी नदी की वजह से नहीं, बल्कि सरकारी उदासीनता के कारण बदहाल है. कोसी नदी के कारण हमारी जमीन उर्वर है, अथाह पानी हमें उपलब्ध है. आज सिर्फ उनके सदुपयोग की जरूरत है और यह सदुपयोग बिना दृढ़ इच्छाशक्ति के संभव नहीं है. इसका आभाव हमारे सरकार में भी है. उन्होंने आगे कहा कि अगर कटैया थर्मल पॉवर का सही ढंग से इस्तेमाल हो तो हमें मुफ्त में बिजली मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, सरकार इस दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठा पा रही है. सभा में कई स्थानीय मुद्दे जैसे बैजनाथपुर पेपर मिल चालू नहीं होना, दूध और मक्का फैक्ट्री की स्थापना नहीं होना भी बहस का विषय बना. सभा को मुख्य रूप से विधायक अशफाक आलम, जिप उपाध्यक्ष रीतेश रंजन, स्थानीय नेता शशि यादव, इंदल यादव, नूनू यादव, गोलू यादव, अमित कुमार, गणेश झा, नंदन कुमार यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया.

वहीं पप्पू यादव के करीबी व चुनाव प्रभारी इंदल यादव ने सभा की सफलता पर बताया कि पप्पू जी आशिर्वाद यात्रा के लिए बिहार के सभी जिलों का दौरा करेंगे. फिलहाल उन्होंने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बक्सर, पूर्णिया, मधेपुरा और सहरसा में दौरा कर चुके हैं. सभी जिलों में उन्हें काफी जन समर्थन मिल रहा है.

अगामी 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर यादव द्वारा आयोजित आशिर्वाद यात्रा को झलकी नहीं माना गया और न ही उन्होंने इस रैली को अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखाने की बात कही. लेकिन चुनाव पर नजरें गड़ाये हुए लोगों व नेताओं को इतना बताने में वे जरूर कामयाब रहे कि कोसी व सीमांचल के इलाके में उनकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है और इनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मदद के बगैर यहां किसी भी दल का भला नहीं हो सकता. अब देखना यह है कि लगातार अपनी दमदार उपस्थिती दर्ज करा रहे पप्पू यादव लोकसभा चुनाव में किस करवट बैठते हैं.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

14 अक्टूबर–20 अक्टूबर 2013

उत्तर प्रदेश– उत्तराखंड

अजय कुमार

फूट डालो, राज करो की नीति पर ‘अंकल प्रदेश’

समाजवादी सरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैली सांप्रदायिक हिंसा से हुए राजनैतिक नुकसान की भरपाई के लिए आने वाले दिनों में कई गैर जरूरी फैसले कर सकती है. खासकर उसके निशाने पर भाजपा और उसके बड़े नेता रहेंगे. सपा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों की जंग को अपने और भाजपा के बीच में समेटना चाहती है. भय दिखा कर प्रीत और सरकारी खजाने का मुंह मुस्लिम वोटरों की तरफ करके युवा सीएम अल्पसंख्यकों को लुभाना और सपा के पक्ष में मुस्लिम ध्रुवीकरण करना चाहते हैं. इस हकीकत से भी पर्दा हट गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने विकास और कानून व्यवस्था को लेकर जो वायदे किए थे, वह महज वादे ही थे. दरअसल अखिलेश को अंग्रेजों के साथ-साथ अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की *फूट डालो और राज करो* की नीति को ही आगे बढ़ाना है, जिसके बल पर तीन बार मुलायम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे थे. अपने नाम के साथ मौलाना शब्द का संबोधन जुड़ने पर मुलायम गौरवान्वित महसूस करते थे, ऐसी ही प्रसन्नता मुस्लिम टोपी और अंगवस्त्र पहनकर अखिलेश यादव महसूस करते हैं. वह कहते हैं मैं तो काफी समय से मुस्लिम टोपी पहनता रहा हूं. उनके बयान ऐसे होते हैं मानो किसी वर्ग विशेष का प्रवक्ता बोल रहा है. बिना जांच पड़ताल के वह किसी को क्लीन चिट दे देते हैं तो किसी पर आरोप मढ़ देते हैं. अपनी पार्टी के नेताओं की बुराई तो वह सुनना ही नहीं चाहते हैं. उनके मंत्री आजम खान पर आरोप लगता है तो सीएम सुरक्षा कवच बन जाते हैं. नौकरशाही और पुलिस को काम नहीं करने दिया जाता है. शासन-प्रशासन में बैठे अधिकारियों पर दबाव डालकर विरोधियों को फंसाने और निपटाने की साजिश रची जाती है. हालात इतने खराब हो जाते हैं कि बड़े-बड़े अधिकारी बीमार पड़ जाते हैं. ऐसा की कुछ मुजफ्फरनगर के एसएसपी के साथ हुआ. बीमारी के चलते उन्होंने अवकाश ले लिया, लेकिन महकमे में उनकी बीमारी से अधिक चर्चा उनके ऊपर पड़ रहे राजनीतिक दबाव की थी. कहा जाता है कि क्षेत्र के एक बड़े भाजपा नेता के खिलाफ रासुका तामील करने का प्रवीण के ऊपर सत्ता का दबाव था. प्रवीण इसके लिए तैयार नहीं थे. राजपाट कुछ ऐसे चलाया जा रहा है मानो सपा नेता दूध के धुले हैं और बाकी दलों के नेता दंगाई, उपद्रवी. मुख्यमंत्री रिमोट से चल रहे हैं. पूरा प्रदेश आजम, राम गोपाल और शिवपाल अंकल के इशारे पर चल रहा है. इस *अंकल प्रदेश* में भतीजा मुख्यमंत्री बौना पड़ गया है.

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में मुलायम सिंह यादव यूपी के दंगों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन मुलायम या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यह नहीं बता पाते हैं कि उन्हें किस आधार पर या कौन सी जांच से इस बात का पता चला. अगर मुलायम की बात सच थी तो दंगों से पहले यह बात सार्वजनिक क्यों नहीं की गई. मुलायम ही नहीं, उनकी पूरी सपा बिग्रेड एक ही सुर में बोल रही है. बात दंगों में आरोपी बनाए गए भाजपा विधायकों की करें तो यहां भी सपा को किरकिरी का ही सामना करना पड़ा. जेल भेजे गए भाजपा के दो और बसपा के एक विधायक में से भाजपा के सुरेश राणा और बसपा के नूर सलीम राणा को दो दिन में ही जमानत मिल गई. सरकारी वकील की दलीलें अदालत में जरा भी नहीं चलीं. पकड़े गए भाजपा विधायक संगीत सोम पर सरकारी मंशा के अनुरूप रासुका तो लगा दिया गया, लेकिन अदालत के सामने इस फैसलों को सही ठहराना आसान नहीं होगा.

मुजफ्फरनगर कुछ शांत हुआ तो नरेंद्र मोदी की रैलियों को लेकर भाजपा और सपा सरकार के बीच टकराव वाली स्थिति पैदा की जा रही है. सूत्र बताते हैं कि यूपी सरकार भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में होने वाली कुछ रैलियों को सौहार्द बिगड़ने की आड़ लेकर रद्द कर सकती है. भाजपा ने तीज-त्योहारों के आसपास रैली की तिथियां रखकर अपने खिलाफ मौके की तलाश में रहने वाली सपा को रैली रोकने का बहाना दे दिया है. कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी भी कहती हैं कि भाजपा को पता होना चाहिए कि अक्टूबर-नवंबर का महीना धार्मिक त्योहारों का होता है, इसलिए इन दिनों पार्टियां राजनीतिक आयोजन करने से बचती हैं. शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए. सपा प्रवक्ता और मंत्री राजेंद्र चौधरी को भी मोदी की रैली से एतराज है. उनका कहना है कि किसी को भी सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की छूट नहीं दी जा सकती. यह सच है कि लोकतंत्र का राज है, लेकिन इसमें सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं है. प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल किसी भी कीमत पर बिगाड़ने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी, चाहें वह मोदी ही क्यों न हों. वैसे, भाजपा को भी सरकार की मंशा का पता चल गया है. वह बदले हालात में नई रणनीति बना रही है. कहा जा रहा है कि अगर सरकार ने मोदी की रैलियों की अनुमति नहीं दी तो मोदी रैली वाले जिलों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ पदयात्रा प्रारंभ करेंगे.

उत्तर प्रदेश के जो हालात नेताओं द्वारा बनाए जा रहे हैं, वह इस बात के संकेत हैं कि चुनावी मौसम में नेताओं को प्रदेश का अमन-चैन रास नहीं आ रहा. आज प्रदेश फिर उसी मुहाने पर खड़ा है, जहां नब्बे के दशक में अयोध्या विवाद के चलते खड़ा था. इस समय के नेताओं की तीखी बयानबाजी का ही परिणाम था जो विवादित ढांचा गिरा दिया गया. तब भी हमारे नेताओं ने हिंदू-मुसलामानों के बीच खाई बढ़ाने का काम किया था और आज भी यही हो रहा है. बस चेहरे बदल गए हैं. तब भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, उमा भारती, राजनाथ सिंह, विजयराजे सिंधिया, विनय कटियार, मौनी बाबा, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा, जनेश्वर मिश्र, मोहन सिंह आदि नाम चर्चा में थे. अब उनकी जगह नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश यादव, आजम खान, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आदि ने ले ली है. कोई हिंदुओं का मसीहा बनने को बेताब है तो कोई मुसलमानों के लिए दुबला हुआ जा रहा है.

सत्ता द्वारा ही वोट बैंक की राजनीति से स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है. यहां तक कि न्यायपालिका को भी दखलंदाजी करनी पड़ती है. जनता के हक के लिए जब सरकार आंख मूंद ले और न्याय के लिए लोगों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़े तो स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है. तनाव के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों को धार्मिक क्रिया कलाप नहीं करने दिया जाए. कहीं जाने से रोका जाए. यह सही नहीं हो सकता है. अखिलेश सरकार को समझना होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका आदेश अंतिम नहीं हो सकता. कानून व्यवस्था का हवाला देकर राज्य में जगह-जगह होने वाली दुर्गा पूजा की अनुमति न देने के मामले में हाईकोर्ट ने सपा सरकार को आईना दिखाया. अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि देश में प्रजातंत्र है. शासन संविधान के दायरे में चलाया जाता है. नागरिकों को धार्मिक क्रियाकलापों से रोका नहीं जा सकता है. इसके साथ ही न्यायमूर्ति डीपी सिंह और न्यायमूर्ति अशोक पाल सिंह की पीठ ने 25 सितंबर 13 को दिए अपने आदेश में सभी जिलों के आला अफसरों को निर्देश दिए कि नवरात्रि के मद्देनजर जहां भी देवी की मूर्तियां स्थापित की जाएं, वहां प्रशासन कानून और व्यवस्था का चाक चौबंद इंतजाम करे. इस आदेश का अक्षरश: पालन करने का आदेश दिया गया है. कोर्ट ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों पर आदेश पालन की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डाली. सरकार की मजबूरी यह है कि इसे अपने पक्ष की बातों के अलावा कुछ दिखाई-सुनाई नहीं देता. यहां तक कि वह तब तक न्यायपालिका को भी ठेंगा दिखाती रहती है, जब तक अदालत गंभीर रुख नहीं अपनाती. तनाव की बात करने वाली सरकार ने कभी इस बात की कोशिश नहीं की कि प्रतिबंधित समय में रोक के बाबजूद मजहबी-धार्मिक स्थलों पर ऊंची आवाज में लाउडस्पीकर क्यों बचते रहते हैं. धर्म की आड़ में कैसे सरकारी जमीन पर बड़ी-बड़ी मस्जिदें और मंदिर बन जाते हैं.

सरकार की हठधर्मिता का ही नतीजा है कि दंगों में सपा सरकार के मंत्री आजम खान की भूमिका की जांच के लिए बनी सर्वदलीय जांच कमेटी (स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सेल) काम शुरू करने से पहले ही विवादों में घिर गई. भाजपा ने कमेटी से अपने आप को अलग कर लिया. भाजपा का कहना है जब तक आजम खान मंत्री हैं, तब तक जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती. भाजपा को इस विरोध का मौका सपा सरकार ने ही दिया. दरअसल सेल के गठन के 24 घंटे के भीतर ही एसपी विशेष जांच सेल कैलाश नाथ मिश्र को चलता कर दिया गया. उनके स्थान पर सेल की प्रभारी मुजफ्फरनगर की एसपी क्राइम कल्पना सक्सेना बना दी गईं, लेकिन सरकार ने यह बताना जरूरी नहीं समझा कि मिश्र को बिना वजह जांच से क्यों हटाया गया. कहा जा रहा है कि बात-बात पर नाराज हो जाने वाले मंत्री फिर कहीं न रूठ जाएं, इसीलिए उनकी तरफ से मिश्रा जी को लेकर गलत संकेत मिलते ही मिश्रा जी की छुट्टी कर दी गई थी. ऐसा लगता है सरकार फूट डालो और राज करो की नीति से फायदा उठाने के लिए ही भाजपा के ऊपर ज्यादा हमलावार होने का नाटक कर रही है. उसे पता है कि वोटों का ध्रुवीकरण तो ऐसे ही होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com.

दो पाटों के बीच सपा-बसपा

दर्शन शमा

लोकसभा चुनाव के महासमर की तैयारी जितनी तेजी से उत्तर प्रदेश में हो रही है, शायद ही उतनी किसी दूसरे प्रदेश में देखने को मिले. प्रधानमंत्री चाहे मोदी बनें या राहुल, माया या मुलायम अथवा अन्य. हमेशा से ही प्रधानमंत्री की कुर्सी की बात उत्तर प्रदेश के गलियारों में ज्यादा सुनने को मिलती है. जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर की ताजपोशी कराने वाला यही प्रदेश तो है, जो विश्व के मानचित्र पर इसलिए अंकित है, क्योंकि यह धरा राजनीति की धुरी है. पूरब से पश्चिम की लंबाई में फैले इस प्रदेश के पैर जहां नेपाल की सीमा को छूते हैं, वहीं इसका पश्चिमी सिरा देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है. कई बार इसे बांटने की बातें भी हुईं, लेकिन राज्य की सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती कि इतने बड़े राज्य का ताज उसके सिर से उतरे. इस राज्य को बांटने की फिक्र उन नेताओं को ज्यादा रहती है, जिन्हें इस बड़े राज्य की कुर्सी पाने की दूर-दूर तक गुंजाइश नहीं दिखती है. ऐसे कई राजनेता रहे हैं, जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब पाले जरूर रहे, लेकिन सत्ता के धुरंधरों की धक्का-मुक्की में वह किधर चले गए, कोई बता नहीं सकता. यहां की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता जातिपरक है. जिसके हक में जितनी जातियां, उतना ही बड़ा राजनीतिक कद का वह योद्धा कहलाता है. एक जमाने में कांग्रेस के साथ हिंदू-मुस्लिम और दलित वर्ग का थोक वोट था. स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग चल रही थी. यह सिलसिला उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी के मुख्यमंत्रित्व काल तक रहा. मुलायम और मायावती के उदय ने कांग्रेस के इस सामूहिक जनाधार को खंड-खंड कर दिया. मायावती ने दलितों के बल पर जहां चार बार मुख्यमंत्री का ताज पहना, वहीं मुलायम ने मुस्लिम-यादव छतरी के तले तीन बार मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली. चौथी बार अखिलेश यादव भी इसी समीकरण के तहत सत्तारूढ़ हुए.

राजनीति के जानकारों का कहना है कि जहां 2012 बसपा के लिए अपशकुन बनकर उभरा, वहीं 2013 समाजवादी पार्टी के लिए अनिष्टकाल माना जा रहा है. जिसके चलते इसका 2014 का मिशन भी गड़बड़ाने लगा है. इससे पहले 2007 की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने दलितों को जहां एकजुट किया, वहीं सोशल इंजीनियरिंग का जामा पहनकर सपा के मुस्लिमों और भाजपा के ब्राह्मणों को अपने पक्ष में कर पहली बार सत्ता में प्रचंड बहुमत प्राप्त किया था. सपा-बसपा की इस जातिवादी राजनीतिक लड़ाई में राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा उत्तर प्रदेश में हाशिये पर ठिठक कर रह गईं. उन्हें आगे बढ़ने का मौका न तो बसपा सुप्रीमों मायावती ने ही दिया और न ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह ने ही कभी उभरने दिया . सपा और बसपा के इन दोनों महारथियों ने जातिवादी राजनीति की चाबी अपने हाथों में कसकर पकड़ रखी है. बसपा सुप्रीमो का जज्बा इतना ऊंचा कि उनकी एक हुंकार पर लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में तिल रखने की जगह नहीं मिलती थी. लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उन्हें उत्तर प्रदेश का ताज सिर से उतारना पड़ा. भले ही उन्होंने चुनाव से पूर्व आपरेशन क्लीन के तहत भ्रष्टाचार में लिप्त अपने करीब सौ विधायकों के टिकट काट दिए. लेकिन इसका फायदा बसपा को नहीं मिला. भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी बसपा को जनता ने नकार दिया और सत्ता सपा को सौंप दी. सपा की इस अप्रत्याशित जीत ने बड़े-बड़े दिग्गजों के दिल दहला दिए थे. राजनीति में मुलायम सिंह का कद इतना ऊंचा उठा कि 2012 के विधानसभा चुनाव में लोकसभा में उनकी तूती बोलने लगी. बड़े-बड़े राजनीतिक पहलवान उनसे हाथ

(शेष पृष्ठ 18 पर)

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन और प्रसार प्रतिनिधियों की. पारिश्रमिक योग्यता अनुसार. शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
ajaiup@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा
(गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

दो पाटों के बीच सपा-बसपा

पृष्ठ 17 का शेष

मिलाने के लिए आतुर रहने लगे. खुद सोनिया ने भी उनके राजनीतिक बाहुबल का लोहा माना. बिना मुलायम की सलाह के सदन में कोई भी बिल पेश होना इतना आसान नहीं था. कांग्रेस ने धैर्य का परिचय देते हुए अपनी संप्रग दो की नैया पार लगाने के लिए जहां मुलायम का सहारा लिया, वहीं बसपा नेता मायावती को अपना बगलगीर बना लिया. उत्तर प्रदेश के इन दोनों राजनीतिक धुरंधरों पर सीबीआई ने अपना शिकंजा कस रखा था. कहते हैं सीबीआई के फंदे से बचने के लिए ही मायावती और मुलायम सिंह ने संप्रग सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया था.

सपा सरकार के बनते ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ने लगीं थीं. अपराधों की बाढ़ आ गई. लूट, डकैती, बलात्कार की घटनाएं इतनी बढ़ीं कि जनता त्राहिमाम कर उठी. अखिलेश की सरकार पर विपक्ष की ओर से लगातार उंगली उठ रही थी. विपक्ष अखिलेश सरकार को कभी नाबालिग सरकार तो कभी साढ़े चार मुख्यमंत्रियों की सरकार कहने लगा. इसके बावजूद ला एंड आर्डर की स्थिति सपा सरकार के लिए सिरदर्द बनी रही. इसके लिए स्वयं मुलायम सिंह ने भी सरकार और उसके कारिंदों को फटकार लगाई थी. मगर उनकी फटकार का विशेष असर नहीं हो सका. मुलायम एक साल पहले से ही लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे थे. अल्पसंख्यक वोटों के लिए वे उनकी हर मांग को कहीं न कहीं पूरा करते दिख रहे थे. ताकि विधानसभा की तरह लोकसभा में भी उनके पक्ष में मुस्लिम वोट उनकी झोली में आ सकें. उन्हें खुश करने के लिए उन्होंने हर यत्न किए. नौकरियों में, शिक्षा में अथवा अन्य मामलों में उनकी दशा-दिशा बदलने की पुरजोर कोशिश की. हर मोर्चे पर वह एक वर्ग विशेष के लिए ही मेहरबान दिखे. लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों ने उनके सब किए धरे पर पानी ही फेर दिया है. सुख और दुख में हाजिर रहने वाले मुलायम सिंह को अब मुजफ्फरनगर जाने में डर लगने लगा है. क्योंकि इस कांड में सारा दोष सरकार के सिर पर मढ़ा जा रहा है. मुख्यमंत्री अखिलेश जब पीड़ितों के बीच पहुंचे तो उन्हें काले झंडे दिखाए गए. बुद्धिजीवियों का मानना है कि सरकार की चूक के चलते ही इतना बड़ा हादसा हुआ है. दंगे को समय रहते रोका जा सकता था. लेकिन अदूरदर्शिता का परिणाम ही रहा, जिसकी वजह से 62 लोग इसकी भेंट चढ़ गए.

कुल मिलाकर सपा और बसपा दोनों ही लोकसभा चुनाव लड़ने की ताकत खोते जा रहे हैं. बसपा में हुए भ्रष्टाचार को लोग अभी भूले नहीं हैं, वहीं सपा सरकार में हुए 107 दंगे लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं. ऐसी स्थिति में जनता या तो कांग्रेस की ओर आकर्षित हो सकती है या फिर भाजपा को अपना मत देकर जिता सकती है. जाहिर है कि इन दो बड़ी पार्टियों के बीच सपा और बसपा की स्थिति दो पाटों के बीच पिसने जैसी ही कही जाएगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

सौहार्द और पुर्नवास की मुहिम

चौथी दुनिया ब्यूरो

शरणार्थी शिविरों में रह रहे दंगा पीड़ितों के पुनर्वास का काम तेजी से चल रहा है. प्रशासनिक अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है. वह समाज के संभ्रांत नागरिकों और नेताओं को साथ लेकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं. इसी क्रम में हाल में ही मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बुढ़ाना तहसील के ग्राम गढ़ी नौआबाद में पलायन के बाद वापस लौटे 200 लोगों से सम्पर्क किया. उन्होंने सभी वर्गों से शांतिपूर्ण ढंग से रहने का आह्वान करते हुए कहा कि वर्षों पुराने रिश्ते व प्यार को कायम रखने के लिए आपसी विश्वास व सौहार्द जरूरी है. हमें अब एक दूसरे के दिल में विश्वास जगाकर प्यार को बढ़ाना है. जिलाधिकारी ने वापस लौटे परिवारों के सदस्यों इकरामुद्दीन, जुम्मन व नूरा आदि से कहा कि वे किसी प्रकार से भयभीत न हों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है. यहां के ग्राम प्रधान बाबू सिंह व ओमकार सिंह बालियान आदि ग्रामीणों ने उन्हें विश्वास दिलाया है. उन्होंने कहा कि अब नियमित रूप से अर्द्धसैनिक बलों का भ्रमण भी जारी रहेगा.

जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान व अर्द्धसैनिक बलों तथा प्रबुद्ध नागरिकों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते हुए कहा कि अब लोगों में विश्वास जगाएं और उन्हें पहले के समान रहने के लिए प्रेरित करें. जिलाधिकारी ने कहा कि जो परिवार वापस अपने घर लौटे हैं, उनको खाद्य सामग्री आदि उनके गांव में ही दी जाएगी. इस अवसर पर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के समक्ष विद्युत के जर्जर तारों को बदलने की मांग की, क्योंकि कई बार तार टूटने से ईख की फसल बर्बाद हो जाती है. ग्रामीणों ने प्रभावित क्षेत्रों में रोडवेज बसें चलाने की भी मांग की तथा हिंसा के दौरान निरस्त किए गए शस्त्र लाइसेंसों को बहाल करने की भी मांग की. जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि शीघ्र ही सर्वे कराकर विद्युत तारों को बदला जाएगा व इस क्षेत्र में शीघ्र ही प्राइवेट व रोडवेज बसों का संचालन भी करा दिया जाएगा. जिलाधिकारी ने कहा कि इस गांव के जो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनकी बहाली करने पर विचार किया जाएगा. जिलाधिकारी ने सभी वर्गों के साथ गांव की गलियों में भ्रमण किया और लोगों से मिले. उन्होंने सभी से आपस में विश्वास व सौहार्द कायम करने की अपील की. ■

दंगों की राजनीति से बर्बाद हो रहा उत्तर प्रदेश

दर्शन शर्मा

छेड़खानी की एक चिन्गारी ने न केवल मुजफ्फरनगर के कवाल गांव जलाया, बल्कि उसकी लपटों में जिले के अन्य गांव भी झुलस गए. भड़की आग ने देखते ही देखते कई गांवों को तबाह कर दिया. किसी का भाई मरा, तो किसी का बेटा और किसी का बाप. महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सभी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में भागे. किसी का सुहाग उजड़ा, तो किसी की गोद सूनी हो गई. गांव के गांव खाली हो गए. शहर में दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे. पुलिस मूकदर्शक बनी थी. कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई थी, जैसे सूबे में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं हो. यहां तक कि पुलिस अफसरों की समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से दंगे को नियंत्रित किया जाए? किसको गिरफ्तार करें, किसको छोड़ें. क्योंकि उनकी हैंडलिंग रिमोट के जरिए हो रही थी. जानकार इसे सरकार की जानबूझकर अनदेखी मानते हैं. वहीं विपक्षी इसे तुष्टीकरण का दुष्परिणाम बताते हैं. गौरतलब है कि एक समय ऐसा था, जब शहर के दो वर्ग के लोग होली-दीवाली, ईद-बकरीद मिलकर मनाते थे. रोजा इफ्तार या अन्य तीज त्योहारों पर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते थे. वे सदियों से साथ रह रहे थे, एक दूसरे का सहयोग करते आ रहे थे. जो लोग साथ-साथ खेले हों, साथ पढ़े-लिखे हों, शहर की बाजारों, गलियों, मुहल्लों पर रोज ही मिलकर दुआ-सलाम करते रहे हों, उनमें अचानक ऐसी वैमनस्यता कैसे घर कर गई. एक प्रदेश सांप्रदायिकता और दंगों की आग में क्यों झुलस रहा है, यह जानना जरूरी है.

बीस करोड़ आबादी सहेजने वाले सूबे में पिछड़ेपन और दुर्दशा के पीछे यहां की जातिवादी राजनीति ही उत्तरदायी है. लोगों को सांप्रदायिकता की हड्डी डालकर लड़ाने वाले माननीय एसी में बैठकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं, जिसे अनपढ़ और गरीब जनता समझ नहीं पाती है. लड़ाने की राजनीति ये करते हैं, लेकिन मरती है भोली-भाली जनता. चुनाव के दरम्यान चार दिन उनके दरवाजों पर मत्था टेककर अपनी उम्मीदवारी को जीवित रखने वाले ये खिलाड़ी बड़ी बारीकी से उनके दिलों को जीतकर वोट बटोर कर चले जाते हैं. माननीय बनने के बाद पांच साल तक वे हवाईजहाजों से आसमान पर उड़ते हैं और फाइवस्टार होटलों में नाश्ता करते हैं. कहने को तो वे जनता के सेवक होते हैं, मगर जनता के हिस्से का सारा पैसा बीच में ही हड़पने की पुरजोर कोशिश करते हैं.

मंहगाई और भ्रष्टाचार के इस दौर ने आम जनता की कमर तोड़कर रख दी है. इस पर दंगे का दंश लग जाए तो उनकी क्या हालत होगी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और शामली के किसानों के खेत और खलिहानों में सन्नाटा पसरा है. दंगे की मार झेल चुके मेहनत मजदूरी करने वालों के सामने भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है. वे शहर छोड़कर दूसरे प्रांतों का रुख करने लगे हैं. इधर गुड़ का सीजन आने वाला है. ऐसे में स्थानीय किसानों के लिए मुसीबत होने वाली है कि उन्हें गन्ने की पेराई के लिए मजदूर कहां से मिलेंगे. पलायन कर रहे मजदूरों के कारण गुड़ बनाने वाले क्रेशर चालू नहीं हो पा रहे हैं. दंगे के बाद खेतों पर हुए हमलों से किसान और मजदूर दहशत में हैं. आज भी लोग खेतो में हरे चारे के लिए जाने से कतरा रहे हैं. अगर जाते हैं तो झुंड बनाकर साथ-साथ लौटते हैं. मजदूर भी खेत पर बिना सुरक्षा के जाने को तैयार नहीं हैं. लोगों का कहना है कि मजदूर अब पास के राज्यों उत्तराखंड और पंजाब में रोजी-रोटी के लिए रुख करने लगे हैं. जो पहले से वहां हैं, वे लौटने को राजी नहीं है. उनका मानना है कि बैठे बिठाए मुसीबत सिर कौन मोल ले, वह जहां हैं, पूरी तरह सुरक्षित तो हैं.

भाजपा नेताओं का आरोप है कि तुष्टीकरण की नीति के चलते ही दंगे से सपा का असली चेहरा सामने आ गया है. लोग सपा से बेहद खफा हैं. भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र का कहना है कि अखिलेश सरकार ने कवाल गांव की घटना की अनदेखी करने के बाद बहू बेटी सम्मान बचाओ महापंचायत को जिस तरह होने दिया, इससे वह शक के घेरे में आ गई है. घटना को अनदेखा कर दंगा होने दिया गया. दंगों से अब तक सियासी लाभ उठाती रही सपा इस बार बुरी तरह मुसलमानों के बीच बेनकाब हो गई है. सपा के लोकसभा उम्मीदवारों में खलबली मची हैं. वे सपा का साथ छोड़ने लगे हैं. जातीय आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनातियां होने से राज्य की नौकरशाही का मनोबल टूटा है. सपा की जमीन खिसकने लगी है. लोग बदलाव चाहते हैं. बहरहाल राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सूबे की 80 में से 60 सीटें जीतने का ख्वाब पालने वाले मुलायम को दंगे ने फर्श पर ला दिया है. इस दंगे ने मुलायम का सुख चैन छीन लिया है. उनके ही लोग उन्हें धोखा देने पर तुले हुए हैं. कांग्रेस ने भी इस दंगे में सियासी रोटियां सेंकने की कोशिश की है. वे बिना अजीत सिंह को लिए ही मुसलमानों से मिलने चले गए.

सूबे की सरकार में अधिकारी भी परेशान हैं. बदले हालात और चुनौतियों के बीच अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) अरुण कुमार अब प्रदेश पुलिस सेवा में नहीं रहना चाहते. उन्होंने प्रदेश के डीजीपी देवराज नागर और शासन को पत्र लिखकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए कार्यमुक्त करने को कहा है. माना जा रहा कि अरुण कुमार लंबे अरसे से महकमे की कार्यशैली से खुश नहीं हैं. पिछले साल सांप्रदायिक दंगा और तनाव बढ़ने के बाद से अरुण कुमार को नौ नवंबर को एडीजी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई थी. तब उन्हें यह उम्मीद थी कि वह पुलिस की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करते हुए कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने में सक्षम होंगे. लेकिन उनके मंसूबे पर तब पानी फिर गया था, जब उनके कहने पर गोंडा में एक पशु तस्कर के खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन किया गया, लेकिन लालबत्ती के आगे स्टिंग आपरेशन फेल हो गया. नतीजतन पुलिस अधीक्षक नवनीत राणा का तबादला कर दिया गया. इसी तरह मजफ्फरनगर में भी उनके द्वारा भेजे गए सुभाषचंद्र दुबे को निलंबन दंश झेलना पड़ा. अरुण कुमार व्यक्तिगत कारणों पर छुट्टी पर चले गए हैं.

बहरहाल सूबे के एक बड़े अधिकारी के उत्तर प्रदेश से बाहर काम करने की इच्छा ने न केवल पुलिस प्रशासन में खलबली मचा दी है, बल्कि राजनीतिक हलकों में भी चर्चा होने लगी है कि आखिर ऐसे कर्मठ अधिकारी के मन में ऐसे कौन से हालात घर कर गए हैं, जिससे वह इस सूबे में सेवा करने के इच्छुक नहीं हैं. ■

अखिलेश सरकार राजहठ कर रही है

उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार अपने को घोर लोहियावादी मानती है. लेकिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी का कहना है कि सपा सरकार छद्म लोहियावादी है. सरकार राजधर्म न निभाकर वोटों की खातिर राजहठ पर आमादा है. एकतरफा कार्रवाई के कारण प्रदेश हिंसा की आग में जल रहा है. मेरठ के सरधना में पंचायत में लाठीचार्ज व गोलीबारी के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है. इसे तुरंत इस्तीफा देना चाहिए अन्यथा राज्यपाल इसे बर्खास्त करें. इसके अलावा नगर विकास मंत्री आजम खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए. राहत कैंप तक में भेदभाव बरता जा रहा है, जो अधिकारी निष्पक्ष कार्रवाई करता है, उसका उत्पीड़न किया जा रहा है. सपा सरकार जहां सद्भावना सप्ताह मना रही है, वहीं वह दंगे के आरोपियों को खुला छोडकर और निर्दोष लोगों को फंसाकर सदभाव को खत्म कर रही है. वाजपेयी ने आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी सरकारी अल्पसंख्यक आतंकवाद से इस कदर त्रस्त हैं कि वे यहां काम ही नहीं करना चाहते. एडीजी अरुण कुमार का छुट्टी पर जाना, एसएसपी प्रवीण कुमार का बीमार पड़ना, इसका उदाहरण है. यह मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है कि जो मौलाना नजीर जानसठ थाने में सांप्रदायिक दंगे का आरोपी है, सरकार उसे राजकीय अतिथि बनाकर हवाई जहाज से लखनऊ बुलवाती है और सीएम उससे मुलाकात करते हैं. वहीं इसी मामले में भाजपा विधायकों को जेल भेजा जाता है, जबकि मुस्लिम समाज के आरोपी खुले घूम रहे हैं.

उन्होंने सवाल किया कि आखिर क्या कारण है कि सरधना में पंचायत पर सरकारी पाबंदी होने और फोर्स लगाए जाने के बाद भी हजारों लोग खेड़ा गांव पहुंच गए. सरकार को समझना चाहिए कि एकपक्षीय कार्रवाई से लोगों के भीतर आक्रोश पनप रहा है. बहुसंख्यक आबादी का उत्पीड़न होगा तो कहां से शांति आएगी. भाजपा नेता ने सरकारी अल्पसंख्यक आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक वर्ग विशेष के अधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है. समाचार चैनल द्वारा दंगों के सिलसिले में किए गए स्टिंग ऑपरेशन को गलत बताने वाली जांच रिपोर्ट प्रेस परिषद के पास नहीं भेजे जाने पर सरकार बेनकाब हो गई हैं. उप्र की सांप्रदायिक घटनाओं पर नियंत्रण के नाम पर पुलिस प्रशासन द्वारा विवेक, विधिसम्मत निष्पक्ष कार्रवाई के बजाए सपा और इसके कुछ विशेष मंत्रियों के दबाव में एकक्षीय कार्रवाई कर रही है. मुजफ्फरनगर में फर्जी नामजदगी और और उत्तर प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ गांव-गांव में महिलाओं का नया आंदोलन खड़ा होता दिख रहा है. बीस से अधिक गांवों में महिलाओं ने आक्रामक पंचायतें कर मुख्यमंत्री और आजम खान से लेकर सपा के और भी कई नेताओं के पुतले फूंके हैं. हाथों में डंडे लेकर जवान से लेकर बुजुर्ग महिलाएं पुलिस प्रशासन से मोर्चा लेने से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं. वे सरकार को कोस रही हैं. उनके घर के मर्द पुलिस के डर से गायब हैं. उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है. उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठप है. मवेशी भूख से मर रहे हैं. खेतों में फसल खड़ी है. उनका नुकसान हो रहा है. वे कहती है कि गांव के लोगों को झूठा फंसाया गया है तो पुलिस को पहले उनसे निपटना होगा. जाट नेताओं का मानना है कि मुजफ्फरनगर में जब से दंगे हुए हैं, तब से राज्य सरकार जाटों को निशाना बनाए हुए है. गांवों के जवान पुलिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं. पुलिस इन पर जबरन दोष मढ़कर उनका भविष्य चौपट करने पर उतारू है. वे कहते हैं कि सरकार की एकतरफा कार्रवाई के चलते जनता ने सीधे टकराव का रास्ता अपनाया है. सरकार भेदभाव न करती तो ऐसी स्थिति न उपजती. मेरठ बार एसोसिएशएन के सचिव मुकेश वालिया का कहना है अगर पुलिस प्रशासन ने निर्दोष लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना जारी रखा तो वकील अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे. वहीं सपा प्रमुख मुलायम सिंह का कहना है कि सपा सरकार मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है. सरकार की कोशिश है कि प्रदेश के हालात बेहतर बने रहें. अयोध्या में परिक्रमा की इजाजत देते तो प्रदेश की स्थिति और अधिक खराब हो सकती थी. देश के लिए अहम योगदान करने वाले किसान व मुसलमान दोनों ही उपेक्षा का शिकार हैं. सपा उन्हें उनका हक दिलाकर रहेगी. रंगनाथ मिश्रा व सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू कराने को लेकर कई बार केंद्र से बात की जा चुकी है, लेकिन केंद्र गंभीर नहीं है. मुसलमानों के विकास के लिए सपा के पास नीतियां भी हैं और नीयत भी, जबकि अन्य पार्टियों के पास दोनों का अभाव है. बुद्धिजीवियों का तर्क है कि मुजफ्फरनगर की एक छोटी से घटना ने जिस तरह सांप्रदायिक रूप धारण किया है, वह राज्य सरकार की अदूदर्शिता का परिणाम है. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के तबादलों और उन्हें दंडित करने का काम जिन तर्कों के आधार पर किया गया है, इससे भी राज्य सरकार के कामकाज पर प्रश्नचिन्ह लगा है. इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वोट बैंक की राजनीति. यह किसी भी सरकार के लिए अच्छी और स्वस्थ सोच है. जनता ने जिन आकांक्षाओं के साथ सपा को बहुमत दिया था, अखिलेश सरकार उसे कुचलने पर आमादा है. अखिलेश सरकार वोट की खातिर जो कर रही है, इसे राजधर्म नहीं, राजहठ कहेंगे. सपा सरकार को ऐसा हठ त्यागना चाहिए, जिससे जनता को धक्का न लगे.

गौरतलब यह है कि मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर एक चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सरकार के मंत्री का नाम आने पर फजीहत हुई. वहीं सरकार ने पुलिस प्रशासन को दोषी मानते हुए तबादले कर दिए. पुलिसकर्मी इस तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए. पुलिस वालों ने याचिका में आरोप लगाया कि तबादले आजम खान के दबाव में किए गए हैं. हाईकोर्ट ने आजम खान को नोटिस जारी किया है और इन पुलिसकर्मियों के तबादले पर रोक लगा दी है. ■ (द. श.)

दंगों के बाद सद्भावना गोष्ठी

सैयद शावेज़ फिरोज़

समाजवादी पार्टी के शासन काल में यूपी दंगों का गढ़ बन गया है. एक तरफ यूपी में सपा कार्यकर्ताओं की गुंडई आम है तो वहीं अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के आतंक के सामने जनता बेबस नज़र आ रही है. आए दिन सांप्रदायिकता के नाम पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, जिनमें से अधिकतर साजिशें कामयाब भी हो चुकी हैं. बिगड़ते माहौल पर लगाम लगाने में प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पूरी तरह से विफल साबित हुए हैं. न तो उन्हें कार्यकर्ताओं का ही समर्थन मिल रहा है और न ही प्रशासनिक अधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं. उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने तो यहां सपा सरकार में बढ़ रही अराजकताओं को देखते हुए पिछले दिनों यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने तक की मांग की है. ग़ौरतलब हो कि वर्तमान सरकार के राज में पिछले एक साल में यूपी में दंगों की संख्या अपना शतक पूरा कर चुकी है. केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में सांप्रदायिक हिंसा से सम्बंधित आंकड़े जारी किए हैं. आंकड़ों के मुताबिक़ पिछले नौ महीनों में यूपी में 93 दंगे हो चुके हैं. जिसमें अब तक 62 लोग मारे गए हैं. मरने वालों में 42 मुस्लिम और 20 हिंदू थे. अखिलेश राज में इस साल सांप्रदायिक झगड़ों में तक़रीबन 1,697 लोग घायल हुए हैं. जिसमें 794 हिंदू और 703 मुस्लिम शामिल थे. दंगों में घायल हुए लोगों में 200 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. सपा शासित उत्तर प्रदेश में इस साल हुए दंगों में कुल 219 मुस्लिम और 134 हिंदू घायल हुए हैं.

दंगों को रोकने में नाकाम हुई समाजवादी सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए एक नई मुहिम छेड़ दी है. वह अपने कार्यकर्ताओं के सहारे आम जनता को नए कलेवर में ढालने में जुटी है, ख़ास तौर से मुसलमानों को. पिछले दिनों ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली में. यहां समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में मुग़लसराय में नगरपालिका इंटर कॉलेज के वीर अब्दुल हमीद सभागार में यूपी के रास्ते पूरे देश में बिगड़ रहे सौहार्द पर लगाम लगाने के लिए एक सद्भावना गोष्ठी का आयोजन किया गया. लेकिन इसमें सद्भावना की जो लहर बही, इसमें सिर्फ़ सपाइयों और उनके सहयोगियों ने ही गोते लगाए. यहां तक कि पालिका के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में नगरपालिका परिषद की अध्यक्ष को भी नहीं पूछा गया, क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं. उनके पति परमेश्वर प्रांगण में दाखिल हुए तो ऐसा लगा मानो सद्भावना की झलक दिखावटी रूप में ही सही, लेकिन ज़रूर दिखेगी. लेकिन वह सभागार में प्रवेश न करके सीधे सिर झुकाए कॉलेज की फील्ड में हो रहे एक निजी कार्यक्रम में शामिल हो गए. यह देखकर कुछ गैर-सपाई लोगों ने कटाक्ष किया कि 'दंगे भी तुम ही कराओ और गोष्ठी भी तुम ही.' बहरहाल समाजवादी पार्टी की सद्भावना गोष्ठी में मुफ़्ती-ए-शहर बनारस व ज्ञानवापी मस्जिद के शाही इमाम मौलाना अब्दुल बातिन नोमानी ने कहा कि हिंदुस्तान हमेशा से बहुत से मज़हब के मानने वालों का रहा है. यहां हर इंसान एक दूसरे का ग़म बांटता आया है. हमारे मुल्क में इंसान को धर्म और ज़ात के तराज़ू में नहीं तौला जाता है, क्योंकि क़ुदरती परेशानियां जो आती हैं, वह किसी का धर्म-ईमान पूछ कर नहीं आती हैं. सिर्फ़ इंसानों पर नाजिल होती हैं. इसलिए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए. मौलाना ने हदीस शरीफ़ का हवाला देते हुए लोगों को बताया कि यहां फ़रमाया गया है कि 'ऐ लोगों तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा.' यहां ज़मीन वालों से मतलब सिर्फ़ इंसानों से ही नहीं, बल्कि जानवरों, परिंदों और तमाम क़ुदरती नेमतों से भी है. आख़िर में मौलाना बातिन ने मुल्क में अमन, चैन और तरक़्क़ी के लिए दुआ मांगी कि हिंदुस्तान को एक ऐसी मिसाल बनाएं कि दुनियां के और मुल्क इससे इबरत हासिल कर सकें. यहीं मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी के महंत राजेंद्र तिवारी ने समाजवादी पार्टी की सद्भावना की कलई खोलते हुए कहा कि देश में आज जो माहौल है, राजनीतिक दलों की वजह से है. ये मुट्ठी भर लोग अपनी सियासत की बुनियाद को मज़बूत बनाने के लिए नफ़रत का बीज बोते हैं. इन्हें कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. यह हमारा संकल्प है कि मानवता के दुश्मन यहां पनप नहीं पाएंगे. हमारी यही वेदना पूरे देश को सिंचित करेगी. इस दौरान मौजूद प्रमुख समाजसेवी गुलाम जीलानी ने कहा कि हमारा जनपद चन्दौली सदियों से गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल के लिए जाना पहचाना जाता है. यहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं. यहां जो सद्भाव है, वह पूरे देश को प्रेरित करेगा. ■

बुंदेलखंड में डेंगू का डंका

सुरेंद्र अग्निहोत्री

आम तौर पर सूखे से सूखता रहा बुंदेलखंड हद से ज्यादा बारिश के बाद अब डेंगू के कहर से जूझ रहा है. ललितपुर, जालौन, हमीरपुर और बांदा के अनेक गांवों में डेंगू और डायरिया का प्रकोप जारी है. प्रशासनिक लापरवाहियों के कारण निजी अस्पतालों ने भोले-भाले ग्रामीणों को लूटना शुरू कर दिया है. वहीं सरकारी चिकित्सालय सफेद हाथी की तरह खड़े हैं. मूकदर्शक बनी मशीनरी के प्रति लोगों के मन में गुस्सा है. ललितपुर शहर में डेंगू की दस्तक को लेकर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना होने का दावा कर रहा है. शहर में डेंगू की पुष्टि के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.

अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य झांसी मंडल डा. राजेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि मंडलीय कीट विशेषज्ञ डा. रविदास के साथ तालाबपुरा स्थित साई मंदिर के पीछे एंटोमोलोजिकल सर्वेक्षण किया. इस दौरान डेंगू रोग वाहक मच्छर एडीज एल्वोपिक्ट्स व मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की पहचान की गई, जिससे शहर में डेंगू, चिकनगुनियां और मलेरिया फैलने की संभावना है. सीएमओ डा. आरसी निरंजन ने तत्काल प्रभाव से अलर्ट जारी कर निरोधात्मक कार्रवाई का आदेश है. हमीरपुर जनपद के ग्राम अछाह में डेंगू से पीड़ित एक युवक की कानपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई. बांदा में

डायरिया व बुखार से लोगों की जान पर बन आई है. अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं. बुखार की चपेट में आए रामविशाल (75) निवासी देहात कोतवाली ग्राम सैमरा की उपचार के दौरान मौत हो गई. ग्राम चहितारा निवासी कृष्णा देवी (55) की भी उपचार के दौरान मौत हो गई. देहात कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पिपरी निवासी अनीता (6) की मस्तिष्क ज्वर से मौत हो गई. दर्जनों लोग डायरिया व बुखार से पीड़ित हैं. हमीरपुर विकासखंड गोहांड के अतरा गांव में 20 ग्रामीण अजीबो-गरीब बीमारी की चपेट में हैं. डॉक्टरों का कहना है कि बीमारी के बारे में जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. गांव में ग्रामीण गले में सूजन से परेशान हैं. सांस में लेने में परेशानी होती है. इसी जनपद के इमिलिया गांव में कई लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है. गांव के एक व्यक्ति ने कानपुर ले जाते समय दम तोड़ दिया. इसी गांव की मुन्नी बाल्मीकि ने कानपुर ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया. प्रधान राजकुमार राजपूत ने बताया कि गांव में मलेरिया व डेंगू से कई लोग प्रभावित हैं. भरुआसुमेरपुर कसबे के धर्मेश्वरबाबा मोहल्ले में भी डेंगू फैल गया है. जालौन जनपद के रामपुरा बीहड़ क्षेत्र में मस्तिष्क बुखार से दो किशोरियों की मौत हो गई है. कई लोग बीमारी की चपेट में हैं. प्रभारी चिकित्साधिकारी का कहना है कि मस्तिष्क ज्वर से लोग बीमार हैं. रामपुरा कस्बे के नई बस्ती निवासी बालकिशुन की 16 वर्षीय बेटी मीना को तेज बुखार के बाद ग्वालियर ले जाया गया, जहां देर रात उसकी मौत हो गई. रामपुरा क्षेत्र के ही पचोखरा निवासी लखपत की 11 वर्षीय बेटी रोशनी की भी स्वास्थ्य केंद्र रामपुरा में मौत हो गई. हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से सपा के प्रत्याशी विशम्भर प्रसाद निशाद कहते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि बुंदेलखंड में पीड़ितों को तत्काल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाए. भाजपा की स्थानीय विधायक साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि लोग डेंगू से पीड़ित होकर जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहे हैं. प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है. दो दर्जन से अधिक मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग जागने को तैयार नहीं है. कांग्रेस विधायक गयादीन अनुरागी कहते हैं कि हमीरपुर में डेंगू का कहर है फिर भी टीकाकरण और साफ सफाई यहां चौपट ही है. ■

पूर्वांचल में दिमागी बुखार से मौतें नहीं थम रहीं

मारकण्डेय प्रसाद सिंह

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों-बस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महराजगंज, पडरौना व देवरिया सहित आस-पास के इलाकों में दिमागी बुखार और डेंगू का प्रकोप तेजी से फैला है. इसके बावजूद प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य महकमे को तत्परता दिखाना जरूरी नहीं लगा. नतीजा सामने है कि पूर्वांचल के जनपदों में बुखार ने भयावह रूप ले लिया है. गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष दिमागी बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ी है, काल के गाल में अब तक 800 से अधिक मासूम समा गए हैं. आधिकारिक आकड़ों के मुताबिक पूर्वांचल व आस-पास के जिलों में डेंगू के मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है. गुरु गोरक्षनाथ अस्पताल के उप मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. राकेश तिवारी के अनुसार अस्पताल में भर्ती 29 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि तीन हफ्ते में 70 से अधिक मरीज इलाज के लिए भर्ती हो चुके हैं. जिला अस्पताल समेत गोरखपुर शहर के दूसरे अस्पतालों में भी मरीजों के भर्ती होने का क्रम जारी है. जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सक डॉ. बीके श्रीवास्तव के अनुसार डेंगू के दो मरीज सदर अस्पताल में भी भर्ती हुए हैं. यह स्थिति तब है, जब सरकार लगातार दावा कर रही है कि दिमागी बुखार व डेंगू प्रकोप से निपटने में स्वास्थ्य विभाग ने कारगर कदम उठाया है, जबकि हकीकत इसके एकदम विपरीत है. हस्तक्षेप (मानवाधिकार जन निगरानी समिति) के राष्ट्रीय सचिव जेपी सिंह ने पूर्वांचल समेत बिहार प्रदेश के आंशिक क्षेत्र जो पूर्वी जिलों से सटे हैं, में बढ़ रहे दिमागी बुखार व डेंगू के कहर पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि इस खतरनाक बीमारी से निपटने के मामले में भी लापरवाही क्यों हावी है. हर मरने वालों की तादाद में बढ़ोतरी हो रही है. आम लोग अपने स्तर पर आपेक्षित और जरूरी सावधानी नहीं बरतते, वहीं वक्त रहते सरकार भी नहीं चेती. गोरखपुर और देवरिया में दिमागी बुखार से सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं. स्वास्थ्य महकमा पीड़ितों के साथ मजाक कर रहा है. सिंह ने मांग की कि पूर्वांचल में यह महामारी रोकने के लिए गंभीर रुख अपनाया जाए. ■

रेलपथ कर्मचारियों का सपना रह जाएगा अधूरा

पिछले साल मुग़लसराय रेल मंडल में डिपार्टमेंटल प्रमोशन के लिए इंजीनियरिंग विभाग के रेलपथ इकाई कर्मचारियों की परीक्षा ली गई थी. जिसका परीक्षा परिणाम जुलाई 2013 तक आना सुनिश्चित हुआ था. लेकिन रेल प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण ये अब भी अधर में लटका हुआ है. जिस कारण ही लिखित परीक्षा में सफ़ल हो चुके 30 अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है. प्रमोशन पाकर रेलपथ पर्यवेक्षक या जूनियर इंजीनियर रेल पथ का पद पाने का सपना सजाए ये कर्मचारी अपने विभाग को कोसते नज़र आ रहे हैं. परीक्षा परिणाम के सम्बन्ध में अधिकारियों से कोई संतुष्टि भरा जवाब न मिलने की वजह से उनका पारा सातवें आसमान पर है. मंडल रेल प्रबंधक के भोलेपन की तो अभ्यर्थी मिसाल देते नहीं थक रहे हैं. कभी विभागीय कर्मचारी डीआरएम को अपने शक के दायरे में रखते हैं तो कभी उन्हें लल्लू लाल की उपाधि देकर अन्य अधिकारियों की टांग खींचते हैं. हांलाकि भारतीय रेल को विश्व का दूसरा और भारत का पहला एम्पलाई सेंटर माना जाता है. जहां हालात ये पैदा हो चुके हैं कि किसी की नियुक्ति हुए 6 से 8 माह बीत गए और अभी तक तनख़्वाह नहीं मिली तो किसी के प्रमोशनल परीक्षा का परिणाम तीन-तीन महीने से रोक रखा गया है. ऐसे में कोई रोटी को रोता है तो कोई रोज़ी को.

गौरतलब है कि इंजीनियरिंग विभाग के रेलपथ इकाई में 50 प्रतिशत विभागीय कोटे के तहत वरीय रेलपथ पर्यवेक्षक के रिक्त पदों को भरने के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन 7 नवंबर 2012 में किया गया था. जिसमें 292 रेल प्रमोशनल कर्मचारियों ने परीक्षा दी थी. जिसका परिणाम इसी वर्ष 28 जून को घोषित कर दिया गया. इसमें सफ़लता प्राप्त करने वाले 30 अभ्यर्थियों की सूची निकाली गई और परीक्षा नियंत्रक इंजीनियरिंग विभाग पूर्व मध्य रेल द्वारा मुग़लसराय रेल मंडल के वरीय मंडल अभियंता समन्वय को मंडल के कार्मिक अधिकारी की चिट्ठी के तहत अवगत कराया गया कि प्रमोशन के लिए परीक्षा में सफ़ल कर्मचारियों को पेपर स्क्रूटनिंग के लिए उत्तीर्ण घोषित किया जाता है. इन सभी का फ़ाइनल पैनल पेपर स्क्रूटनी के बाद प्रकाशित किया जाएगा. इसमें आवश्यक कार्यवाही के लिए सहायक अभियन्ता प्रथम एवं द्वितीय मुग़लसराय एवं सहायक अभियन्ता डेहरी, गया व जपला समेत वरिष्ठ अनुभाग अभियन्ता रेलपथ साइथ एवं नॉर्थ मुग़लसराय, चन्दौली, भभुआ रोड, डेहरी, अनुग्रह नारायण रोड, रफ़ीगंज, गया एवं जपला पूर्व व पश्चिम को प्रतिलिपि दी गई, जिसमें यह निर्देशित किया गया था कि संबंधित विभाग के सभी कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं पिछले 9 वर्ष की वर्किंग रिपोर्ट 10 दिनों के अंदर वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी कार्यालय पूर्व मध्य रेल मुग़लसराय में जमा की जाए. जिसके आधार पर ही फ़ाइनल रिज़ल्ट एवं पदोन्नति की अगली कार्यवाही की जा सकेगी. इसके पूर्व रेलपथ पर्यवेक्षकों को जूनियर इंजीनियर रेलपथ के साथ मर्जर करने का एक शासनादेश रेलवे बोर्ड भारत सरकार द्वारा रेल के समस्त ज़ोनों एवं मंडलों को प्राप्त हुआ था कि अब रेलपथ पर्यवेक्षक जूनियर इंजीनियर रेलपथ कहलाएंगे. लेकिन अफ़सोस कि इंजीनियर कहलाने का सपना पालने वाले लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए परीक्षार्थियों को उनकी मेहनत पर पानी फिरता नज़र आ रहा है. विभाग की तरफ़ से की जा रही लेट-लतीफ़ी उन्हें क़तई रास नहीं आ रही है. कर्मचारियों के मुताबिक़ सर्विस रिकार्ड भी जांच के लिए मांगा जा चुका है और जांच भी पूरी हो चुकी है. लेकिन फिर भी न जाने क्यों उनका प्रमोशन अधर में लटका हुआ है. अभ्यर्थियों को लगता है कि कहीं पदोन्नति कोटा रद्द न हो जाए और उनकी सारी मेहनत धरी की धरी न रह जाए. डिपार्टमेंटल प्रमोशनल इम्जाम के बाबत मुग़लसराय के मंडल रेल प्रबंधक अनूप कुमार का कहना है कि विभागीय पदोन्नति की परीक्षाएं अक्सर आयोजित होती रहती हैं. फ़िलहाल इस पर कोई कमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है. ■ (सै.शा.फि.)

feedback@chauthiduniya.com

जनपद के समस्त कृषकों को आत्मा योजनांतर्गत कृषि विभाग, सिद्धार्थनगर की तरफ से देय सुविधाएं

कृषि तकनीकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) योजना के अंतर्गत संचालित किए जाने वाले कार्यक्रम :

1. **प्रदर्शनों का आयोजन :** खरीफ एवं रबी सत्र में एक एकड़ क्षेत्रफल के प्रदर्शनों का आयोजन प्रत्येक विकास खंडों में किया जाना.
2. **कृषक से कृषक प्रदर्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम :** प्रदर्शन स्थल पर कृषकों को प्रशिक्षित किया जाना.
3. **कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम :** कृषकों को जनपद के अंदर, राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर कृषि की नवीनतम जानकारी प्राप्त कराने हेतु कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि अनुसंधान केंद्रों पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना.
4. **कृषक भ्रमण कार्यक्रम :** कृषि की नवीनतम जानकारी प्राप्त कराने हेतु जनपद के अंदर, राज्य के अंदर तथा राज्य के बाहर कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि प्रदर्शन एवं अनुसंधान केंद्रों पर कृषकों का भ्रमण आयोजित किया जाना.
5. **किसान मेला :** जनपद स्तर पर किसान मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाना.
6. **किसान गोष्ठियों का आयोजन :** विकास खंड स्तर पर किसान गोष्ठियों का आयोजन किया जाना.
7. **समूह गठन :** कृषकों के समूहों का गठन किया जाना.
8. **रिवाल्विंग फंड :** गठित समूहों को उनके क्षमता विकास हेतु रिवाल्विंग फंड उपलब्ध कराया जाना.
9. **फार्म स्कूल :** प्रगतिशील कृषकों के यहां एक है. क्षेत्रफल का प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना.

डॉ. राजीव कुमार (पीसीएस) उप कृषि निदेशक, सिद्धार्थनगर
अखिलेश तिवारी (पीसीएस) मुख्य विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर
सूर्य प्रकाश मिश्र (आईएएस) जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर

दशहरा, बकरीद और दीपावली पर जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

ओमकार नाथ मेहता
अधिवक्ता, सिविलकोर्ट गोरखपुर
कानूनी सलाहकार, हस्तक्षेप, (मानवाधिकार जन निगरानी समिति)

चौथी दुनिया साप्ताहिक अख़बार के सफलतम प्रकाशन पर हार्दिक शुभकानाएं

- डी.पी. यादव, राष्ट्रीय महासचिव, हस्तक्षेप (मानवाधिकार जननिगरानी समिति)
- जे.पी. सिंह, राष्ट्रीय सचिव, हस्तक्षेप (मानवाधिकार जननिगरानी समिति)
- मूरत राम, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैंपेन फॉर मनरेगा
- डॉ राजेश कुमार यादव, प्रभारी, आरटीआई टास्कफोर्स उत्तर प्रदेश
- डॉ शैलजा राय, अध्यक्ष, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग) उ.प्र.
- संगीता जायसवाल, महासचिव, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग) उ.प्र.
- सरोज पांडेय, राष्ट्रीय महासचिव, डोमेस्टिक वायोलेंस एक्शन ग्रुप (डग)
- ओमकार नाथ मेहता, एडवोकेट
- हंसराज तिवारी एडवोकेट, कानूनी सलाहकार हस्तक्षेप (मानवाधिकार जन निगरानी समिति)

संस्था का सदस्य बनने अथवा संस्था के विषय में जानकारी के लिए संपर्क करें
Email : awsar3334@gmail.com
अथवा कॉल करें 09455209120, 09453517557,07668952813

अजय कुमार, लखनऊ ब्यूरो प्रमुख कार्यालय का पता : जे-3/2 डॉलीबाग़, हजरतगंज, लखनऊ-226001, फोन -(0522) 2204678/09415005111

पिछले दिनों विधानसभा में पेश रिर्पोट को प्रधान महालेखाकार मुकेश पी.सिंह ने जारी करते हुए यह भी खुलासा किया कि 2007 से 2012 के दौरान काम मांगने वाले महज़ 2.3 से 6.8 फ़ीसदी ग़रीब परिवारों को ही 100 दिन का काम सरकार द्वारा मुहैया कराया गया. जिस आधार पर हर परिवार को लगभग 18 से 29 दिन का ही काम नसीब हो सका.

उत्तराखंड खबरें

अटल खाद्यान्न योजना कांग्रेस के गले की फांस

उत्तराखंड में कांग्रेस लोकसभा चुनाव के नौ महीने पूर्व ही अपनी पांच सीट को बचाए रखने की कसरत में जुट गई है. मिशन 2014 के लिए गेम चेंजर मानी जा रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना उत्तराखंड में कितना कमाल दिखा पाएगी, इसे लेकर खुद प्रदेश के कांग्रेसी रणनीतिकार दुविधा में हैं. इस योजना में जनता को मिलने वाले लाभ दो साल से भाजपा राज से ही लागू अटल खाद्यान्न योजना के जरिये मिलते रहे हैं. ऐसे में योजना की कामयाबी सरकार के कामकाज के तरीके और खाद्य सुरक्षा के लुभावने प्रावधानों को गुड गवर्नेंस के साथ अमल में लाने पर टिकी है. जबकि एक सच्चाई यह भी है कि अटल खाद्यान्न योजना में जितना लाभ आम जनता को सहज रूप से मिल रहा था, उतना लाभ भी नई योजना नही दे पा रही है. ऐसे में मार्च, 2011 से पूरी तरह लागू अटल खाद्यान्न योजना का ही दबाव रहा कि कांग्रेस सरकार को खाद्य सुरक्षा योजना में तब्दीली करनी पड़ी है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक अंत्योदय को तो प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न दिया गया, बीपीएल के लिए प्रति यूनिट पांच किलो खाद्यान्न की व्यवस्था है. अटल खाद्यान्न योजना में बीपीएल के लिए भी प्रति परिवार 35 किलो सस्ता खाद्यान्न की व्यवस्था देखते हुए प्रदेश सरकार नई योजना में बीपीएल के लिए पहले से चली आ रही व्यवस्था लागू करने को विवश हुई. खाद्य सुरक्षा योजना पूरी तरह लागू होने के बाद एपीएल का बड़ा तबका सस्ते खाद्यान्न से वंचित हो जाएगा. यह तबका पिछली सरकार की योजना के कारण अब तक लाभान्वित होता रहा है. कमरतोड़ महंगाई की मार की वजह से एपीएल का बड़ा तबका भी अब सरकारी राशन की दुकानों पर कतार में खड़ा नजर आने लगा है. राज्य स्थापना दिवस पर खाद्य सुरक्षा योजना पूरी तरह लागू होने की स्थिति में एपीएल की बड़ी तादाद को मायूसी हाथ लगी है जो कांग्रेस के लिए आत्मघाती सिद्ध होगा. खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्रदेश के 61.94 लाख लोगों को मिलना है. इसमें 45.85 लाख ग्रामीण और 16.09 लाख शहरी आबादी शामिल हैं. बीपीएल और अंत्योदय को हटाने पर तकरीबन 39.44 लाख जनता को योजना के दायरे में लेना है. कांग्रेस के रणनीतिकार भी मान रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ राज्य के लिए नई नहीं है. ऐसे में जनता के दिलों में दस्तक देने को योजना को प्रशासनिक चुस्ती के साथ लागू करने की आवश्यकता है. इसके तहत नए प्राथमिक परिवारों का चिन्हीकरण पहली चुनौती है. अधिनियम में दिए गए निर्देशों पर अमल हुआ तो मौजूदा बीपीएल परिवारों की सूची छोटी हो सकती है. इससे खासतौर पर पार्टी के वे विधायक बेचैन हैं, जिनके क्षेत्र में मलिन बस्तियां हैं. पार्टी से लेकर विभागीय स्तर पर होने वाली बैठकों में कांग्रेस के ही विधायक पात्र परिवारों के चिन्हीकरण को लेकर अपनी शंकाएं उठा चुके हैं. खाद्य सुरक्षा से जनता को सीधे जोड़ने और किसी भी परेशानी के निराकरण के लिए जिला और राज्य स्तर पर सतर्कता समितियों, नोडल अधिकारियों और खाद्य आयोग की प्रभावी भूमिका रखी गई है. शिकायतों की सुनवाई और निराकरण की व्यवस्था कितनी प्रभावी होती है, प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का सियासी सफर इससे ही तय होना है. कांग्रेस के नीति नियंताओं की निगाहें इसी रणनीति पर टिकी हैं. कांग्रेसियों को अटल खाद्यान्न योजना को मिली सफलता का भय सता रहा है. ■

जंगली जानवरों ने उड़ाई आपदा पीड़ितों की नींद

उत्तराखंड में मौसम सामान्य होने के चलते टेंटों अथवा छप्परों में जीवनयापन कर रहे प्रभावितों को दैवीय आपदा की दहशत से कुछ निजात मिल ही रही थी कि अब जंगली जानवरों के खौफ ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इससे आपदा प्रभावित खासे परेशान हैं. आपदा के चलते कई गांवों के तबाह होने के चलते ग्रामीण बेघर हो गए थे. इस कारण आपदा के दौर में प्रभावितों ने टेंटों अथवा छावनियों में शरण ली. पूरी बरसात भर आपदा की दहशत में जीवन-यापन करने के बाद अब जबकि मौसम कुछ सामान्य होने लगा था. इस बीच अब जंगली जानवरों के आतंक ने टेंटों अथवा छानियों में रह रहे प्रभावितों की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है. आपदा के कारण मकानों के ध्वस्त हो जाने से प्रभावित लोग सुरक्षित स्थानों पर टेंटों अथवा छप्परों में रह रहे हैं. मौसम के सामान्य होने के बाद भी तमाम परिवार टेंटों और शिविरों में ही रहे हैं, क्योंकि उनके घर उजड चुके हैं. जोशीमठ विकासखंड के भ्यूंडार तथा पुलना के सभी परिवार टेंटों में दिन गुजार रहे हैं. इसी तरह पिनोला-घाट के कई परिवार भी टेंटों में शरण लिए हुए हैं. उर्गम घाटी के भर्की और बांसा गांव के प्रभावित भी छानियों में रह रहे हैं. आपदा के बाद इन्हें अब तक घर नसीब नहीं हो पाया है. इसी तरह, सुनाली, नौली, हिंडोली, कोठी आदि गांवों के लोगों ने भी सुरक्षित स्थानों पर आपदा के दौर में छानियों में शरण ली थी. कर्णप्रयाग प्रखंड के नौली, हिंडोली, कोठी आदि के ग्रामीणों की भी अमूमन यही स्थिति है. हिंडोली के लोगों ने भूमियाल तोक में छानियां बनाकर वहीं शरण ली थी. अब भी वे बारिश होने पर शिविरों में शरण ले रहे हैं. लेकिन अब आपदा से तबाह जीवन संभलने लगा है, तब जंगली भालुओं ने इस समय इन क्षेत्रों में आतंक मचाना शुरू कर दिया है. भ्यूंडार, पुलना से लेकर पिनोला-घाट, उर्गम घाटी के साथ ही हिंडोली के प्रभावितों के टेंटों अथवा छानियों में भालुओं की आमद बढ़ गई है. बंदरों ने टेंटों व छप्परों में उत्पात मचाना शुरू कर दिया है. टेंटों में रखी खाद्यान्न सामग्री भी बंदर ले जा रहे हैं. कई हिंसक बंदर तो पीड़ितों पर हमला भी कर रहे हैं. झुंड के झुंड भालुओं के विचरण करने से प्रभावितों के दहशत के मारे हाथ पांव भी फूलने लगे हैं. ■

सरकार नौ दिन चलै अढ़ाई कोस

उत्तराखंड सरकार नौ दिन चलै अढ़ाई कोस की तर्ज पर आपदा प्रभावित क्षेत्र में जनता को राहत दे पा रही है. सरकार एक अक्टूबर से केदारनाथ यात्रा शुरू कर चुकी है लेकिन स्थिति यह है कि आपदा के चलते सड़क मार्ग से कट चुके 107 गांव अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं. इन गांवों के निवासियों को मूलभूत जरूरत पूरी करने के लिए मीलो पैदल ही सफर तय करना पड़ रहा है. प्रदेश में आई आपदा को सौ दिन से अधिक का समय बीत चुका है. अभी तक आपदा राहत कार्य चल ही रहे हैं. आपदा के बाद सरकार ने भले ही सड़क मार्ग से कटे 4200 गांवों में से 4093 को अस्थायी रूप से सड़क से जोड़ने का कागजी दावा किया है फिर भी अभी भी धरातल की सच्चाई यह है कि 107 गांव सड़क मार्ग से कटे हुए हैं. यहां तक कि आपदा से क्षतिग्रस्त 186 मार्ग अभी तक नहीं खोले जा सके हैं. 15 क्षतिग्रस्त पेयजल योजनाओं चालू नहीं हो पाई हैं. जबकि दो तक अभी भी विद्युत आपूर्ति बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं. राज्य की विजय बहुगुणा सरकार का दावा है कि आपदा राहत के लिए कार्य युद्धस्तर पर जारी है. सरकार अभी तक लगभग एक अरब बावन करोड़ रुपये आपद प्रभावितों को वितरित कर चुकी है। इसमें से सबसे अधिक तकरीबन 43 करोड़ की राहत राशि अकेले रुद्रप्रयाग में वितरित की गई है. आज भी उत्तरकाशी, केदारघाटी को मदद की दरकार है. सरकार उतनी मदद आपदा पीड़ितों को नहीं कर रही है, दुनिया भर से मिल रही आपदा मदद राशि का प्रयोग सरकार जनहित से अधिक अपनी सेहत सुधारने और अपनी छवि बनाने में अपव्यय कर रही है. ■

रेनु शर्मा

feedback@chauthiduniya.com

जनरल खंडूड़ी की राह में रोड़ा बनेंगे निशंक

राजकुमार शर्मा

गढ़वाल संसदीय सीट से पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ताल ठोंककर इस बार अपने पार्टी के दिग्गज भुवनचंद्र खंडूड़ी की राह में जिस तरह से रोड़े अटकाने का मन बना लिया है, इससे भाजपा हाईकमान की उलझन बढ़ गई है. पूर्व मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी ने भी पहले ही गढ़वाल लोकसभा सीट से ही लड़ने की इच्छा जता दी थी. राजनीति के मर्मज्ञों का मानना है कि अब इस सीट पर दावा कर रहे भाजपा के अन्य नेताओं को अपने लिए कोई और सीट तलाशनी होगी, क्योंकि दूर-दूर तक ऐसी संभावना नहीं नजर आती कि आलाकमान खंडूड़ी की इच्छा के विरुद्ध उन्हें कहीं और से लड़ाने का जोखिम मोल लेगा. ऐसे में विभिन्न दावेदारों का गणित बिगड़ना तय माना जा रहा है, जिसमें निशंक भी शामिल हैं. यह सब समझने के बावजूद भी निशंक इतना जल्दी मानने वाले इन्सान नहीं है. उनकी हर कोशिश है कि उन्हें गढ़वाल सीट से प्रत्याशी बनाया जाए. इसके पीछे उनकी मंशा साफ है कि वे जलरल की राह में एक बार फिर रोड़ा अटकाना चाह रहे हैं. उत्तराखंड की राजनीति में इस घटना को सदैव याद किया जाएगा कि जब पूरी भाजपा ने खडूड़ी है जरूरी के नारे के सहारे सूबे में अपनी बढ़त का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही थी, उस समय जनरल को अभिमन्यु की तरह भितरघात के चक्रव्यूह में फंसा कर करारी हार दी गई. इस भितरघात के खेल के पीछे किसका हाथ था, यह किसी से छिपा नहीं है. भाजपा में अभी यह असमंजस बना हुआ है कि अन्य चार लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का चयन सर्वे के आधार पर होगा या नेताओं के कद या छवि के आधार पर. भाजपा के अंदरूनी सूत्रों की मानें तो हाल में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बने अनिल बलूनी तक यहां से दावा करते हुए नरेंद्र मोदी से अपनी नजदीकियों को इसका आधार बना रहे थे. हरिद्वार सीट पर उमा भारती की दावेदारी की चर्चा के बाद पूर्व सीएम डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक भी गढ़वाल से टिकट मिलने की उम्मीद पाले हुए थे, खंडूड़ी ने अपनी इच्छा सार्वजनिक कर यहां से ताल ठोंकने का सपना पाले सभी संभावित दावेदारों के सपनों पर पानी फेर दिया है. भाजपा में अब यह सवाल तैर रहा है कि क्या भाजपा का कोई और दिग्गज किसी सीट पर अपना दावा पेश कर सकता है. ऐसा होता है तो भाजपा के समीकरणों में और बदलाव हो सकता है. इस बार भाजपा 2009 में मिली करारी हार का बदला लेना चाहती है. इस करारी शिकस्त के चलते खंडूड़ी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी और बदलते गुटीय समीकरण के बीच निशंक मुख्यमंत्री बने थे. इस वक्त जैसी राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उन्हें भाजपा अपने लिए मुफीद मानती है और पांचों सीटों पर अपना कब्जा चाहती है. इसके लिए हर सीट पर फूंक-फूंक कर फैसला लेना चाहती है. पिछले साल टिहरी लोकसभा उपचुनाव में रानी राज्यलक्ष्मी शाह को मिली जीत से वह उत्साहित है. उसे लगता है कि यह चुनावी ट्रेंड कायम रहेगा. पार्टी में बार-बार यह चंचा रहती है कि 2014 के चुनाव में बेहतर नतीजों के लिए भाजपा तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों बीसी खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी व निशंक को मैदान में उतार सकती है. देखा जाए तो तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ कई वरिष्ठ नेता विभिन्न सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं. मसलन टिहरी में मौजूदा सांसद माला राज्यलक्ष्मी शाह, त्रिवेंद्र सिंह व लाखीराम जोशी और नैनीताल सीट पर भगत सिंह कोश्यारी व बच्ची सिंह रावत लड़ने के इच्छुक हैं. भगत सिंह कोश्यारी नैनीताल क्षेत्र में काफी समय से सक्रिय भी हैं. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी बिना सर्वे के टिकट देने के मूड में नहीं है. यानी साफ है कि पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा से पहले क्षेत्र में उसकी छवि और पकड़ को परख लेना चाहती है. नितिन गडकरी के समय में पार्टी में सर्वे काफी प्रचलन में थे. पिछले विधानसभा चुनाव में अधिकांश प्रत्याशियों के चयन में सर्वे का काफी हाथ था. अब देखना यह है कि राजनाथ सिंह पुराने अध्यक्ष की लीक पर ही चलते हैं या कि नेताओं की छवि और कद को देखकर फैसला लेते हैं. राजनाथ के राज में खंडूड़ी का हर तरह से कद बढ़ने का संकेत मिल रहा है, भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी की भी पहली पंसद जनरल खंडूड़ी ही हैं. ■

उत्तर प्रदेश में मनरेगा मज़दूरों का अकाल

सैयद शावेज़ फ़िरोज़

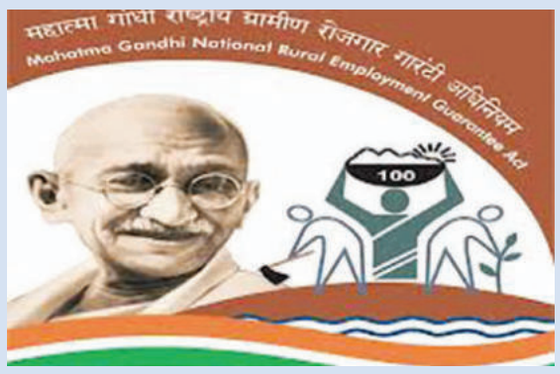

कांग्रेस की अगुवाई वाली संप्रग सरकार की महात्वाकांक्षी योजना मनरेगा का उत्तर प्रदेश में बुरा हाल है. हाल ही में जारी कैग रिर्पोट में कहा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (मनरेगा) को यूपी में मज़दूर ही नहीं मिल रहे हैं. जारी आंकड़ों पर अगर नज़र दौड़ाएं तो पैरों तले ज़मीन खिसकती दिखाई देगी. हैरानी की बात यह है कि वित्त वर्ष 2010-11 के मुक़ाबले 2011-12 में प्रदेश में काम पाने वाले परिवारों की संख्या में 11.80 लाख की गिरावट आई है. यह कमी क्यों आयी? इसके जवाब में सरकार का कहना है कि कामगार अब नहीं रहे. क्योंकि काम मांगने कोई आ ही नहीं रहा. वर्ष 2007 से 2012 के दौरान नियम के विपरीत पीडब्ल्यूडी से मनरेगा के 2700 करोड़ रुपये का काम कराया गया. इसमें 33 फ़ीसदी महिलाओं को काम मिलना चाहिए था. लेकिन नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए महज़ 18 से 22 प्रतिशत महिलाओं को ही काम दिया गया. यही नहीं कैग का तो यह भी कहना है कि लोगों को काम के प्रति सरकार द्वारा जागरूक न करने के चलते उत्तर प्रदेश में मज़दूरों का आकाल पड़ गया है. रिर्पोट में चौंकाने वाले तथ्य यह भी हैं कि मनरेगा के तहत जो काम ग्राम पंचायतों को तय करने थे, इनमें से कई काम प्रदेश सरकार ने खुद ही तय कर दिए. ज़्यादातर कामों का निर्धारण जिला पंचायत स्तर पर हो गया. इसके चलते बहुत सारे ऐसे काम भी हो गए जिनके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. कैग ने 18 जनपदों के जिला पंचायत, 46 ब्लाकों के क्षेत्र पंचायत, 460 ग्राम पंचायतों में 4453 कार्यों की नमूना जांच के आधार पर यह रिर्पोट प्रस्तुत की है. पिछले दिनों विधानसभा में पेश रिर्पोट को प्रधान महालेखाकार मुकेश पी.सिंह ने जारी करते हुए यह भी खुलासा किया कि 2007 से 2012 के दौरान काम मांगने वाले महज़ 2.3 से 6.8 फ़ीसदी ग़रीब परिवारों को ही 100 दिन का काम सरकार द्वारा मुहैया कराया गया. जिस आधार पर हर परिवार को लगभग 18 से 29 दिन का ही काम नसीब हो सका. कैग ने सीधे तौर पर मनरेगा में मज़दूरों की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है. यह सच भी है कि प्रचार-प्रसार के अभाव में उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना दम तोड़ती नज़र आ रही है. ग़रीबों का इस योजना से मुंह मोड़ना इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में खोट है. जिसके कारण गारंटी के साथ मिलने वाला 100 दिन का काम मजदूरों को समझ में नहीं आ रहा है. इसके चलते यह महत्वाकांक्षी योजना फ्लॉप होती दिखाई दे रही है. अब आगे देखना है कैग रिर्पोट के खुलासे के बाद इसमें सुधार लाने के क्या प्रयास किए जाते हैं. ■

कार्यालय अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण, फैजाबाद

प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय/व्यावसायिक योजनाओं में रिक्त सम्पत्तियों के आवंटन हेतु पंजीकरण का सुनहरा अवसर

पंजीकरण अवधि- दिनांक 1.10.2013 से दिनांक ...30.10.2013... तक

सम्पत्ति का विवरण

क्र0	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	उपलब्ध संख्या	क्षेत्रफल वर्गमी0 में	अनुमानित मूल्य (रू0 में)0	पंजीकरण/धरोहर धनराशि(रू0)	श्रेणी
1	जनकपुरी आवासीय योजना	ई.डब्लू.एस. भवन (भूतल)	8	32	6,47,350.00	65,000.00	सभी श्रेणी हेतु
		ई.डब्लू.एस. भवन (प्रथम तल)	18	32	5,65,191.00	56,500	सभी श्रेणी हेतु
		एल0आई0जी0 भवन (भूतल)	15	75	17,13,844.00	1,71,500.00	सभी श्रेणी हेतु
		एल0आई0जी0 भवन (प्रथमतल)	23	75	15,01,973.00	1,50,000.00	सभी श्रेणी हेतु
		एम.आई.जी डूपलेक्स	10	65	26,34,638.00	2,64,000.00	सभी श्रेणी हेतु
2	साकेतपुरी	एम0आई0जी0 भवन	01	152.14	28,19,960.00	2,82,000.00	सभी श्रेणी हेतु
3	अवध बिहार	दुकान जी0एफ0	01	13.20	5,72,000.00	57,000.00	6 एस.सी
		" एल0जी0एफ0	07	13.20	4,29,550.00	43,000.00	1 भूपूसै01स्टाफ
		एफ0एफ0 हाल	02	132.75	39,33,050.00	4,00,000.00	सभी श्रेणी हेतु
4	कोशलपुरी फेज-2	दुकान	12	19.035	5,30,404.00	.53,000.00	सभी श्रेणी हेतु
5	कोशलपुरी फेज-1	दुकान	04	9.70	3,61,308.00	36,500.00	सभी श्रेणी हेतु
6	साकेतपुरी	दुकान	05	17.28	5,05,725.00	55,000.00	2 एस.सी. 2 ओबीसी 1स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी
7	वाहन पर्किंग	दुकान	08	12.79	3,19,581.00	32,000.00	सभी श्रेणी हेतु
8	बैभव काम्पलेक्स	दुकान	01	14.15	10,05,839.00	1,06,000.00	सामान्य
9	बैभव काम्पलेक्स	द्वितीय तल हाल(ए)	01	44.75	33,51,730.00	3,50,000.00	सभी श्रेणी हेतु
		(बी)	01	28.30	21,19,642.00	2,20,000.00	"
		सी	01	28.30	21,19,642.00	2,20,000.00	"

* पंजीकरण पुस्तिका रू0 300.00 नकद जमा कर पी0 एन0 बी0 शाखा विकास प्राधिकरण एवं आई0 डी0 बी0 आई0, आई सी.आई0सीआई, एच.डी.एफ.सी बैंक सिविल लाइन्स से प्राप्त की जा सकती है।

* अनुसूचित जाति/जन जाति, ओबीसी, स्वतन्त्रता सेनानी व उनके आश्रित व विकलांग व्यक्तियों को निर्धारित पंजीकरण/धरोहर धनराशि की आधी ही जमा करनी होगी।

* कमांक 1 एवं 2 की सम्पत्तियों का निस्तारण लाटरी द्वारा तथा शेष कम सं0 3 से 9 तक का आवंटन नीलामी बोली द्वारा किया जायेगा।

* किसी भी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि संशोधनीय होगी। लाटरी/नीलामी/नियम/शर्तो की जानकारी विस्तृत रूप से पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित की गयी है।

नोट :- अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्यालय कार्यदिवसों में प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति/उपसचिव से सीधे सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।

भुगतान पद्धति- अधिकतम नीलामी बोली की 25 प्रतिशत धनराशि पत्र प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर पी0 एन0 बी0 शाखा विकास प्राधिकरण (जिसमें पंजीकरण धनराशि सम्मिलित होगी) शेष 75 प्रतिशत धनराशि 5 वर्ष की 60 मासिक किश्तो में नियमानुसार ब्याज सहित जमा करना होगा।

(डी0एस0 राठौर) उपसचिव | (आलोक कुमार) सचिव | (पी0के0 श्रीवास्तव) उपाध्यक्ष

चौथी दुनिया

आवश्यकता है

संवाददाता, विज्ञापन प्रतिनिधि, प्रसार प्रतिनिधि

चौथी दुनिया के लिए उत्तराखण्ड के सभी मंडल और जिला मुख्यालयों पर अनुभवी संवाददाताओं, विज्ञापन, प्रसार प्रतिनिधियों एवं एजेंसियों के लिए शीघ्र आवेदन करें.

E-mail- konica@chauthiduniya.com
arifali@chauthiduniya.com
चौथी दुनिया F-2, सेक्टर 11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश-201301,
PH : 120-6450888, 6451999